G20 भारत 2023 INDIA

सत्यमेव जयते
भारत सरकार

आज़ादी का अमृत महोत्सव

9 साल
सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण

9 साल

सेवा, सुशासन
और गरीब कल्याण

विषय-सूची

1	गरीबों की सेवा, वंचितों का सम्मान	1
2	सुनिश्चित हो रहा किसानों का कल्याण	13
3	नारी शक्ति हो रही और ताकतवर	25
4	भारत की अमृत-पीढ़ी हो रही सशक्त	35
5	मध्यम वर्ग का जीवन हुआ आसान	43
6	सभी के लिए सस्ती, सुलभ स्वास्थ्य सेवा	53
7	'राष्ट्र प्रथम'- विदेश नीति और राष्ट्रीय सुरक्षा	63
8	भारत, वैश्विक आर्थिक महाशक्ति	75
9	ईज ऑफ़ डूइंग बिज़नेस से कारोबार को लगे पंख	83
10	इंफ्रास्ट्रक्चर- तेज़ी से हो रहा बेहतर	91
11	टेक्नोलॉजी से भारत को नई शक्ति	101
12	नॉर्थ ईस्ट बन रहा विकास का नया इंजन	109
13	विरासत और विकास	119
14	पर्यावरण एवं सतत विकास	133

परिचय

वर्ष 2023 में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सरकार के नौ वर्ष पूरे हो चुके हैं। ये नौ वर्ष समावेशी, प्रगतिशील और सतत विकास लाने के लिए समर्पित रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में सरकार अपने सभी नागरिकों के लिए समानता और अवसरों के सृजन की अपनी प्रतिबद्धता में दृढ़ रही है।

प्रधानमंत्री मोदी ने विकास की राजनीति अर्थात विकासवाद को केंद्र बिंदु बनाते हुए मुख्यधारा में ला दिया है और अब राजनीतिक संवाद एवं नीतिगत कार्य प्रक्रिया इसी के इर्द-गिर्द घूमती है।

2014 में पदभार ग्रहण करने के बाद से, प्रधानमंत्री मोदी हर नीति निर्माण और इसे कार्यान्वित करने में 'भारत प्रथम' के दृष्टिकोण को प्रस्तुत करने के अपने संकल्प पर अडिग रहे हैं। यह संकल्प सरकार की बाहरी और आंतरिक सुरक्षा, आर्थिक प्रबंधन, वंचित समूहों के लिए सशक्तिकरण योजनाओं, सांस्कृतिक संरक्षण के प्रयासों आदि के लिए समाधान निकालने में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है।

प्रधानमंत्री मोदी की सरकार हमेशा चुनौतीपूर्ण लक्ष्यों को तय करने और निर्धारित समय सीमा से पहले उन्हें प्राप्त करने में विश्वास रखती है। इस दृढ़ संकल्प को, चाहे वह कोविड-19 के खिलाफ रिकॉर्ड समय में पूरी पात्र आबादी का टीकाकरण करना हो, देश के इतिहास में अब तक का सबसे अधिक निर्यात दर्ज करना हो, पूरे भारत में हो रही डिजिटल क्रांति हो, ग्रामीण क्षेत्रों के विद्युतीकरण में महत्वपूर्ण लक्ष्यों को प्राप्त करना हो, विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे के निर्माण का हो अथवा घरों में पेयजल की सुविधा प्रदान करने का हो, सभी क्षेत्रों में देखा जा सकता है।

पिछले नौ वर्षों में, जन धन, आधार और मोबाइल के रूप में जेएएम-त्रिशक्ति का उपयोग करते हुए सार्वजनिक सेवा वितरण और सरकारी योजनाओं के कार्यान्वयन में एक आदर्श बदलाव लाया गया है। जेएएम-त्रिशक्ति भारत के रूपांतरित और बेहतर तरीके से विकसित डिजिटल परिदृश्य का प्रमुख प्रवर्तक है। इसने मध्यस्थों को हटा दिया है और लाभार्थी के बैंक खाते में लाभों के सीधे हस्तांतरण को सुलभ बना दिया है।

किसी देश को समृद्ध होने के लिए, यह आवश्यक है कि इसके बुनियादी ढांचे में तेजी से वृद्धि हो और प्रधानमंत्री मोदी के गतिशील नेतृत्व में सरकार इस तथ्य को बेहतर रूप से समझती है। दशकों से विलंबित परियोजनाओं को पूरा करने के साथ ही नई परियोजनाओं का शुभारंभ इस सरकार के विकासात्मक दृष्टिकोण की आधारशिला रही है।

पूर्व में विकास के दिशाहीन दृष्टिकोण के विपरीत, मोदी सरकार ने समग्र विकास की संस्कृति को अपनाया है जो किसी भी पक्ष को पीछे नहीं छोड़ती है। पिछले नौ वर्षों में कल्याण कवरेज के व्यापक विस्तार ने सभी भारतीयों को बड़े सपने देखने और अधिक से अधिक उपलब्धियों की आकांक्षा रखने के लिए प्रेरित किया है।

विकास और कल्याणकारी योजनाओं की व्यापक और समग्र पहुंच ने विभिन्न वंचित समूहों के लिए अपरिवर्तनीय सशक्तिकरण सुनिश्चित किया है, जिससे उन्हें महत्वाकांक्षी और आत्मनिर्भर बनने में सहायता मिली है।

दुनिया अब यह समझ रही है कि जो विकास स्थाई नहीं है, वह वास्तविक विकास नहीं है। यह प्राचीन भारतीय दर्शन के अनुरूप है जिसने हमेशा प्रकृति और पर्यावरण को महत्व दिया है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में, भारत ने विश्व स्तर पर पर्यावरण संरक्षण का समर्थन किया है और हमारा देश इस आंदोलन के अग्रणी मार्ग-दर्शक के रूप में उभरा है। पर्यावरण की तरह प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और संवर्धन के लिए भी प्रतिबद्ध है। संयुक्त राष्ट्र ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में घोषित किया है, यह भारतीय विरासत को वैश्विक मान्यता की स्वीकृति है।

2001 में पहली बार गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में निर्वाचित होने के बाद और 2014 में भारत के प्रधानमंत्री बनने के पश्चात, नरेन्द्र मोदी ने सुधारों और शासन में एक नया मानदंड स्थापित किया है। जो न केवल भारत के लिए बल्कि दुनिया के कई हिस्सों के लिए समावेशी विकास का एक

मॉडल बन गया है। उन्होंने न केवल लोगों को आकांक्षा रखने के लिए प्रोत्साहित किया है बल्कि उनकी बढ़ती आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त सरकारी सहायता भी प्रदान की है ताकि प्रत्येक भारतीय 'अमृत काल' में भारत की विकास गाथा का हिस्सा बन सके।

यह पुस्तक प्रधानमंत्री मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में नीति निर्माण के चौदह पहलुओं अर्थात बुनियादी ढांचे से होते हुए विदेश नीति से लेकर सामाजिक न्याय तक भारत के परिवर्तन को दर्शाने वाला एक व्यापक संग्रह है। यह वंचितों की सेवा करने, महिलाओं को सशक्त बनाने, युवाओं को अवसर प्रदान करने और किसानों को सम्मान दिलाने से जुड़ी नौ वर्षों की गाथा है। यह एक नए भारत की कहानी है।

* * *

डीबीटी हो, बिजली, पानी, टॉयलेट जैसी सुविधाएं गरीब व्यक्ति तक पहुंचाने की योजना हों, इन सभी ने जमीनी स्तर पर एक क्रांति ला दी है। इन योजनाओं ने देश के गरीब से गरीब व्यक्ति को भी सम्मान और सुरक्षा के भाव से भर दिया है।

-नरेन्द्र मोदी

गरीबों की सेवा, वंचितों का सम्मान

1

सारांश

संविधान प्रत्येक भारतीय नागरिक को समानता प्रदान करता है, और उनमें से प्रत्येक के लिए गरिमापूर्ण जीवन की गारंटी देता है। फिर भी आजादी के कई दशकों के बाद भी, कई भारतीयों में सम्मान के साथ जीवन जीने के लिए मूलभूत सुविधाओं की कमी बनी रही। इसे बदलना था, और तेजी से बदलना था। 2014 से, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सरकार विकास के एक मॉडल के लिए प्रतिबद्ध है। यह मॉडल यह सुनिश्चित करती है कि कोई भी पीछे न रहे। ऐसा विकास जो न केवल कुछ चुनिंदा लोगों के लिए, बल्कि सभी लोगों के लिए पीने के पानी, बिजली कनेक्शन, स्वास्थ्य सेवा, शौचालय, एलपीजी सिलेंडर, शिक्षा और वित्तीय समावेशन जैसी बुनियादी सुविधाओं की गारंटी देता है।

नरेन्द्र मोदी की सरकार ने पिछले नौ वर्षों में, प्रत्येक भारतीय को सशक्त बनाने के लिए कई कल्याणकारी योजनाओं को लॉन्च और कार्यान्वित किया।

इस तरह के त्वरित सशक्तिकरण के परिणाम मुद्रा योजना और स्टैंड अप इंडिया जैसे कार्यक्रमों में देखे जा सकते हैं, जो हाशिए के समूहों से युवा उद्यमियों का एक बड़ा पूल बना रहे हैं। मुद्रा योजना के तहत दिए गए 40 करोड़ ऋणों में से आधे से अधिक अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जनजातियों/ अन्य पिछड़ा वर्गों के उद्यमियों को दिए गए हैं। यह न केवल व्यक्तियों के सशक्तिकरण की शुरुआत कर रहा है, बल्कि पारंपरिक रूप से उपेक्षित समुदायों को सशक्त बनाने का एक साधन भी है।

अपने कल्याण कार्यक्रम के अनुरूप, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण प्रदान करने के मोदी सरकार के ऐतिहासिक फैसले ने गरीब परिवारों को बहुत आवश्यक सहायता प्रदान की है।

समावेशी विकास की अपनी दृष्टि के हिस्से के रूप में, सरकार ने दिव्यांगजन, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों, विमुक्त और खानाबदोश जनजातियों, और अब तक सेवा से वंचित या कम सेवा वाले ऐसे अन्य समूहों को सशक्त बनाने के लिए कई सुधार किए हैं। सामाजिक न्याय के लिए सरकार का संकल्प चिकित्सा शिक्षा में अखिल भारतीय कोटे की सीटों पर अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक पिछड़ा वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के लिए आरक्षण को लागू करने के अपने निर्णय में स्पष्ट था, यह सुनिश्चित करते हुए कि इन समूहों के छात्र भी किफायती सरकारी कॉलेजों में डॉक्टर बनने की आकांक्षा कर सकते हैं। इसी तरह, नमस्ते योजना के तहत, सरकार का लक्ष्य असुरक्षित सीवर और सेप्टिक टैंक सफाई की प्रथाओं को खत्म करना है, ताकि सफाई कर्मचारी सम्मान का जीवन जी सकें।

प्रधानमंत्री मोदी की सरकार का एक अभिन्न अंग सामाजिक सशक्तिकरण के प्रतीकों को पहचानने का प्रयास रहा है। उदाहरण के तौर पर बहादुर आदिवासी सेनानियों के बलिदान को याद करने के लिए, सरकार ने हर साल 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस घोषित किया है। इस तरह की मान्यता राष्ट्र-निर्माण में उनके योगदान को उजागर करके समुदायों के बीच गौरव का निर्माण करती है।

सरकार के कल्याण संबंधी प्रावधान और गरीबी उन्मूलन के प्रयासों को वैश्विक संस्थानों से मान्यता मिली है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के एक पेपर ने देश में अत्यधिक गरीबी को समाप्त करने के लिए श्री मोदी की सरकार को श्रेय दिया है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) और ऑक्सफोर्ड गरीबी और मानव विकास पहल (ओपीएचआई) द्वारा जारी वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक (एमपीआई) ने भी भारत को अपने सभी दस बहुआयामी गरीबी संकेतकों में कमी लाने का श्रेय दिया है। गरीबों और वंचितों की सेवा करना श्री मोदी की सरकार का अंतर्निहित वादा रहा है, एक ऐसा वादा जो 'अंत्योदय' के सिद्धांत द्वारा निर्देशित है, जिसका अर्थ है कि विकास का लक्ष्य तब तक पूरा नहीं होता जब तक कि यह समाज के अंतिम व्यक्ति तक नहीं पहुंचता।

***

मुख्य बातें

पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना
के तहत
80 करोड़
लोगों को मुफ्त अनाज

11.88 करोड़
नल से जल कनेक्शन

प्रधानमंत्री आवास योजना
के तहत
3 करोड़
से ज़्यादा शहरी और ग्रामीण आवास

स्वच्छ भारत
के तहत
11.72 करोड़
शौचालयों का निर्माण

पीएम स्वनिधि
के माध्यम से
34.45 लाख
रेहड़ी-पटरी वालों को मिला आर्थिक बल

मुद्रा योजना
के तहत
छोटे उद्यमियों को व्यापार बढ़ाने के लिए मिले करीब
39.65 करोड़
लोन

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को
संवैधानिक दर्जा

COVID लॉकडाउन के दौरान
20 करोड़
महिलाओं के खातों में कैश ट्रांसफर

स्टैंड अप इंडिया
के तहत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों को
7,351 करोड़ रुपये
से अधिक का लोन

वर्तमान में केंद्र में
60%
मंत्री एससी, एसटी या ओबीसी हैं

2014 से पहले की तुलना में
पांच गुना अधिक
एकलव्य आवासीय विद्यालय स्वीकृत

117
आकांक्षी जिले
विकास के मापदंडों पर आगे बढ़े

उपलब्धियां

अंत्योदय और सैचुरेशन कवरेज से तुष्टिकरण का अंत

2014 से कल्याणकारी योजनाएं **अंत्योदय के सिद्धांत** से प्रेरित रही हैं। (कोई भी न छूटे)। इसका मतलब है कि सरकार अपनी हर योजना में सैचुरेशन यानी शत-प्रतिशत लक्ष्य को टारगेट कर रही है।

शत-प्रतिशत कवरेज का मतलब ही है कि ऐसे शासन से सभी को लाभ मिलेगा ।

उपेक्षित वर्गों का स्थाई सशक्तिकरण

- पहले की कुछ सरकारों का रवैया केवल आंशिक लाभ देकर वंचित वर्गों पर कृपा दिखाना था।
- वे लोगों को अपने ऊपर निर्भर रखना चाहते थे और इसलिए उनका सशक्तिकरण नहीं किया गया।
- लेकिन अब, पीएम मोदी ने वंचित वर्गों का **स्थाई सशक्तिकरण** सुनिश्चित किया है।
- स्टैंड-अप इंडिया और मुद्रा योजना जैसी योजनाएं उद्यमिता के अवसर उपलब्ध कराकर कमजोर वर्गों के लोगों को सशक्त कर रही है।
- ये नए उद्यमी न केवल नई आकांक्षाओं को आकार देंगे, बल्कि **पूरे समुदाय के लिए रोल मॉडल** बन जाएंगे।

कामचलाऊ व्यवस्था वाली राजनीति का अंत

- अगर एक बार गैस कनेक्शन, बिजली कनेक्शन या फिर पानी का कनेक्शन दे दिया गया तो फिर **कोई उसे छीन नहीं सकता**।
- इसके बाद गरीब की आकांक्षा और अपेक्षाएं बढ़ती जाती हैं, क्योंकि उनकी बुनियादी आवश्यकताएं पूरी हो चुकी होती हैं।
- इससे उम्मीदें और ज्यादा बढ़ती हैं और जिससे सरकार उन्हें पूरा करने की ओर बढ़ती है।
- बहुत लंबे समय तक **Low Delivery और Low Expectations ने भारत का अहित** किया है। लेकिन अब पीएम मोदी बदलाव ला रहे हैं।

* * *

सरकार के बड़े काम

आंकड़े गवाह हैं कि सरकार गरीबों के लिए बड़ा सोचती है। बीते 9 वर्षों के दौरान करोड़ों परिवारों को पहली बार सबसे जरूरी बुनियादी सुविधाएं मिली हैं।

48.27 करोड़
जन-धन खाते खोले गए

29.75 करोड़
लोग प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में शामिल

13.53 करोड़
लोगों को जीवन ज्योति बीमा योजना का लाभ

37 करोड़
आयुष्मान भारत हेल्थ एकाउंट बने

3 करोड़
से अधिक आवास
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत

25 लाख करोड़
रुपये से अधिक सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में

2.86 करोड़
घर बिजली से रोशन
सौभाग्य योजना के तहत

9.6 करोड़
उज्ज्वला योजना एलपीजी कनेक्शन

वंचितों की सेवा सर्वोपरि

71% प्रधानमंत्री फ़सल बीमा योजना के अंतर्गत आने वाले किसान SC/ST/OBC वर्ग से

80% छोटे और सीमान्त किसान जिसमें ज्यादातर ST/SC/OBC वर्ग के किसान शामिल हैं, PM-KISAN के तहत आय प्राप्त कर रहे हैं

45.45% घर PMAY(G) के तहत SC/ST को मिले

58% छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले ST/SC/OBC वर्ग के छात्र

51% मुद्रा योजना के 40 करोड़ लाभार्थियों में SC/ST/OBC वर्ग से

जनसेवा के काम में बदलती मानसिकता

पहले

सरकार 1 रुपया भेजती है, उसमें से लोगों तक सिर्फ 15 पैसे पहुंचते है।

अब

"सैचुरेशन मेरा सपना है। हमें 100 प्रतिशत कवरेज के लक्ष्य की ओर बढ़ना है। सरकारी मशीनरी को इसकी आदत डाल लेनी चाहिए।"

Sabka Saath
Sabka Vikas
Sabka Vishwas
Sabka Prayas

समावेशी शासन

केंद्रीय मंत्रिपरिषद में SC, ST और OBC का अब तक का **सबसे ज्यादा प्रतिनिधित्व**

उच्च शिक्षा में **10 प्रतिशत EWS Quota** लागू

OBC और EWS के लिए मेडिकल एजुकेशन में अखिल भारतीय कोटा सीटों पर आरक्षण

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा

Transgender Persons (Protection of Rights) Act, 2019 से ट्रांसजेंडरों के अधिकारों का संरक्षण

युवाओं को मादक पदार्थों के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए **नशा मुक्त भारत अभियान** की शुरुआत

डीनोटिफाइड, घुमंतु और अर्ध-घुमंतु जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग की स्थापना

मान्यता प्राप्त अक्षमता की संख्या **7 से बढ़ाकर 21** किए जाने से दिव्यांगजनों को लाभ

क्या आप जानते हैं ?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय दिव्यांगजनों की मदद के लिए कैंप आयोजित कर उन्हें सहायक उपकरण वितरित करता है। 2014 के बाद करीब 13,528 कैंप का आयोजन हो चुका है, जिससे 24.45 लाख से ज्यादा दिव्यांगजनों का सशक्तिकरण हुआ है।

श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा और सशक्तिकरण

प्लेटफॉर्म वर्कर्स पर ध्यान

एग्रीगेटर्स जैसे नए युग के प्लेटफॉर्म के विकास का मतलब श्रमिकों के लिए नए प्रकार की नौकरियां। भारत उन पहले कुछ देशों में से एक है जो अपने श्रमिकों के सामाजिक सुरक्षा के बारे में सोचता है।

एग्रीगेटर्स को लाभ प्रदान करने के लिए टर्नओवर के 1-2% के योगदान पर 5% तक फायदे का प्रावधान किया गया है।

e-Shram सशक्तिकरण के लिए

28.85 करोड़
असंगठित श्रमिक पोर्टल पर पंजीकृत

400 व्यवसाय, कौशल सेट, शिक्षा, आय, सामाजिक श्रेणी, बैंक खाता विवरण संबद्ध

26
असंगठित श्रमिकों को सामाजिक कल्याण की योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए राज्य/केंद्र शासित प्रदेश, डाटा साझा करने हेतु इ-श्रम से जुड़े

प्रधानमंत्री श्रम-योगी मानधन असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए पेंशन

49.29 लाख
असंगठित क्षेत्र के कामगार पंजीकृत

रु. 3,000
न्यूनतम पेंशन है, जो उन्हें 60 वर्ष की आयु के बाद मिलेगी

बोझ हुआ कम, अनुपालन में सुधार

कर्मचारी राज्य बीमा निगम के अंशदान दरों में कमी

नियोक्ताओं का योगदान **4.75%** से घटाकर **3.25%** किया गया

कर्मचारियों का योगदान **1.75%** से घटाकर **0.75%** किया गया

श्रमिकों के लिए COVID-19 राहत कार्य

24%

- 15,000 रुपये प्रति माह से कम वेतन पाने वाले श्रमिकों के ईपीएफ खातों में भुगतान की गई मासिक मजदूरी का अनुपात।

19,126 करोड़ रु

- इपीएफओ कार्यालयों द्वारा 91.69 लाख श्रमिकों को COVID-19 एडवांस के रूप में वितरित की गयी राशि

ENTREPRENEURSHIP से EMPOWERMENT

PM-SVANidhi कार्यक्रम के तहत **34.45** लाख रेहड़ी-पटरी वालों को लोन सुविधा

40 करोड़ MUDRA लोन में से आधे से ज़्यादा SC/ST/OBC उद्यमियों को

Standup India के माध्यम से **25,000** से अधिक SC/ST उद्यमियों को बैंक लोन और बिजनेस की सुविधाएं

सामाजिक सशक्तिकरण के लिए प्रतीकों को पहचान

डॉ. बी. आर. अम्बेडकर से जुड़े 5 प्रमुख स्थलों का 'पंचतीर्थ' के रुप में पुनर्विकास

हर साल 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रुप में मनाया जायेगा

दस नए आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालयों की स्थापना

“

किसानों की आय बढ़ाना, खेती का खर्च कम करना, बीज से बाजार तक किसानों को आधुनिक सुविधाएं देना, ये हमारी सरकार की प्राथमिकता है।

-नरेन्द्र मोदी

”

सुनिश्चित हो रहा किसानों का कल्याण

2

सारांश

किसान, कृषि और इससे जुड़ी गतिविधियाँ हमेशा से भारत के सामाजिक-सांस्कृतिक जीवन और अर्थव्यवस्था की प्रमुख घटक रहीं हैं। पिछले नौ वर्षों में, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के "बीज से बाजार तक" के दृष्टिकोण पर आधारित मार्गदर्शन से भारतीय कृषि को नयी गति मिली है।

सरकार ने किसानों को धनराशि का सुनिश्चित नकद हस्तांतरण करते हुए, पीएम किसान सम्मान निधि के माध्यम से उनकी आय को समर्थन दिया है। प्रत्यक्ष नकद धनराशि अंतरण के जरिये किसानों को प्रति वर्ष 6,000 रुपये प्रदान किये जाते हैं। नियमित किस्तों के माध्यम से प्राप्त होने वाली इस पूरक आय ने बिचौलियों की भूमिका को खत्म कर दिया है तथा छोटे और सीमांत किसानों को भी बेहतर गुणवत्ता के इनपुट खरीदने, अपनी भूमि की उत्पादकता में सुधार करने और अपनी आय बढ़ाने के प्रति सक्षम बनाया है।

कृषि से जुड़े जोखिमों के प्रभाव को न्यूनतम करने के लिए, सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत की, जो एक कृषि बीमा प्रणाली है तथा बेमौसम बारिश, कीट क्षति, फसल कटाई के बाद होने वाले नुकसान आदि कारकों के खिलाफ किसानों को सुरक्षा प्रदान करती है। इसी तरह, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना ने सिंचाई कवरेज का विस्तार किया है।

परिणाम सभी के सामने हैं, 2021-22 की कोविड-अवधि के दौरान, भारत के खाद्यान्न उत्पादन ने एक नया रिकॉर्ड बनाया तथा 2022-23 के अनुमान और भी अधिक उत्पादन का संकेत देते हैं। बागवानी क्षेत्र में भी तेजी से विकास हुआ है। भारतीय कृषि के संबद्ध क्षेत्रों - पशुधन, वानिकी और लकड़ी आपूर्ति, मत्स्य पालन तथा जलीय-कृषि में तेज वृद्धि देखी जा रही है और ये क्षेत्र कृषि आय के संभावित स्रोत बन रहे हैं। आठ करोड़ से अधिक किसानों को रोजगार देने वाला डेयरी क्षेत्र अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। भारत विश्व स्तर पर दुग्ध उत्पादन में प्रथम, अण्डा उत्पादन में तृतीय, मत्स्य उत्पादन में तृतीय तथा मांस उत्पादन में आठवें स्थान पर है। कृषि और संबद्ध क्षेत्र की विकास क्षमता का उपयोग करने के लिए, सरकार ने कृषि अवसंरचना निधि की शुरुआत की है। यह वर्ष 2020-21 से 2032-33 तक फसल कटाई के बाद के लिए आवश्यक प्रबंधन अवसंरचना और सामुदायिक कृषि संपत्तियों के निर्माण के लिए एक वित्तपोषण सुविधा है।

संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट (श्री अन्न) वर्ष घोषित किया गया है । मोटे अनाज, मनुष्यों द्वारा खेती की जाने वाली सबसे पुरानी फसलों में से एक हैं और इन्हें भविष्य की फसलें भी कहा जाता है। सुपरफूड के रूप में इनके मूल्य को दर्शाने के लिए मोटे अनाजों को 'श्रीअन्न' का नाम दिया गया है। प्रधानमंत्री के शब्दों में, "मोटे अनाज उपभोक्ता, किसान और जलवायु के लिए अच्छे हैं।"

2014 से सरकार की प्राथमिकता, भारतीय कृषि का आधुनिकीकरण करने की रही है। इसे 'स्मार्ट' खेती की ओर आगे बढ़ते हुए लगातार बदलाव करने के जरिये किया जा रहा है। सरकार द्वारा जारी किए गए मृदा स्वास्थ्य कार्डों के उपयोग से किसानों को विभिन्न इनपुट का कुशल उपयोग करने और उनकी उपज को अधिकतम करने में मदद मिली है। राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन (एनएमएनएफ) जैसे कई कार्यक्रमों, जो रसायन मुक्त और जलवायु स्मार्ट कृषि को बढ़ावा देते हैं, के माध्यम से छोटे किसानों को प्राकृतिक और जैविक खेती अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। इन कार्यक्रमों से इनपुट पर कम निवेश, उच्च कृषि आय और जलवायु परिवर्तन के खतरों व विभिन्न अनिश्चितताओं से सुरक्षा आदि का लाभ मिला है।

"बीज से बाजार तक" के लक्ष्य को प्राप्त करने तथा किसानों की स्थिति में सुधार करने के लिए कृषि उपज की तैयारी के बाद की व्यवस्थाओं को मजबूत करना आवश्यक है। ई-एनएएम पहल के माध्यम से पूरे देश में कृषि बाजारों को जोड़ने से पारदर्शिता आई है और कृषि बाजारों में प्रतिस्पर्धा बढ़ी है।

पिछले नौ वर्षों में भारतीय कृषि क्षेत्र से जुड़ी पूरी व्यवस्था में व्यापक परिवर्तन देखा गया है, जिसने इसे आधुनिक, वैज्ञानिक और समृद्ध बनाया है। आज, भारतीय किसान न केवल भारत के लिए खेती कर रहा है, बल्कि पूरी दुनिया को अपने उत्पादों के व्यापक बाजार के रूप में देख रहा है।

* * *

मुख्य बातें

2013-14 की तुलना
2022-23 में कृषि बजट में
5.7 गुना वृद्धि

एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर
फंड के माध्यम से
1 लाख करोड़ रुपये

11 करोड़
से अधिक
पीएम किसान
लाभार्थी

करीब
23 करोड़
मृदा स्वास्थ्य कार्ड
जारी

वित्त वर्ष 2013-14 से
वित्त वर्ष 2021-22 तक
गैर-बासमती चावल
निर्यात में
109.7 %
की वृद्धि

एमएसपी पर
तिलहन खरीद में
1500%
की बढ़ोतरी

एमएसपी पर
दलहन खरीद में
7350%
की वृद्धि

2022-23 में 2021-22 के
मुकाबले कुल उर्वरक सब्सिडी
500%
की वृद्धि

2022-23 में
20 लाख करोड़ रुपये
कृषि लोन प्रदान
किया जाएगा

पीएम फसल बीमा योजना
के तहत दावों में
1.33 लाख करोड़ रुपये
से अधिक का निपटारा

2021-26 के लिए
पीएम कृषि सिंचाई योजना के लिए
93,068 करोड़ रुपये
आवंटित

eNAM
के माध्यम से अब
1260 मंडियां
जुड़ी हुई हैं

उपलब्धियां

बीज से बाजार तक

- मोदी सरकार भारतीय किसानों के साथ खड़ी है और Agriculture Cycle के सभी चरणों में मदद दे रही है।
- **Seeds से Soil Health, Insurance से Irrigation, MSP से Markets** तक-एक व्यापक अप्रोच ने किसानों को हर कदम पर मजबूत बनाया है।

आय बढ़ाने के लिए किसानों को बाजारों से जोड़ा गया

- **eNAM**: एकीकृत राष्ट्रीय बाजार से प्रतियोगिता बढ़ी। कृषि उत्पादों के लिए बेहतर कीमत मिली।
- **किसान उत्पादन संगठन**: FPO के जरिए बिक्री से बेहतर कीमत मिलना संभव हुआ और किसानों की आमदनी बढ़ी।
- **Forward linkages**: मेगा फूड पार्क की संख्या तेजी से बढ़ी, 2014 के 2 से बढ़कर 2023 में 23 हो गई।
- **कृषि क्षेत्र में स्टार्ट-अप का इकोसिक्टम:** कृषि और सम्बन्ध क्षेत्रों में 2019-20 से 2022-23 में 1138 स्टार्टअप और उन्हें 124.2 करोड़ रुपए अनुदान स्वीकृत किया गया।

* * *

सरकार के बड़े काम

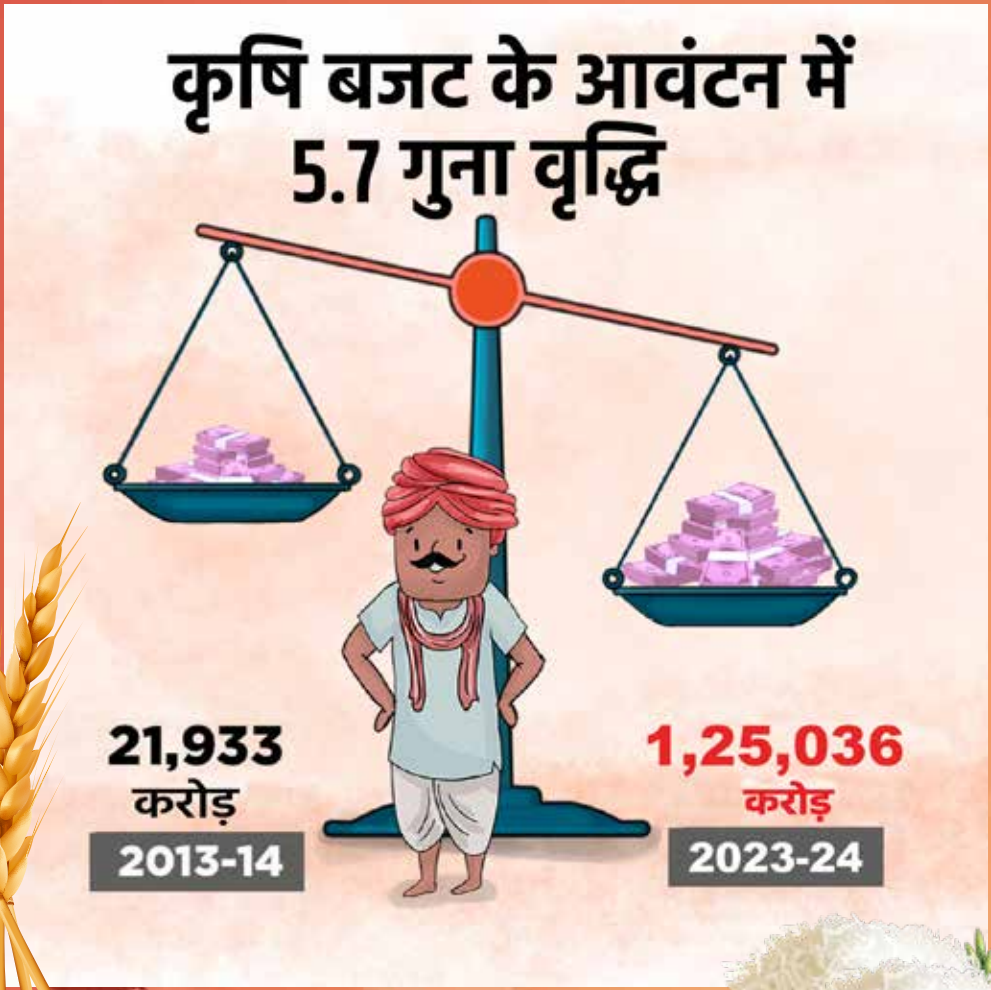

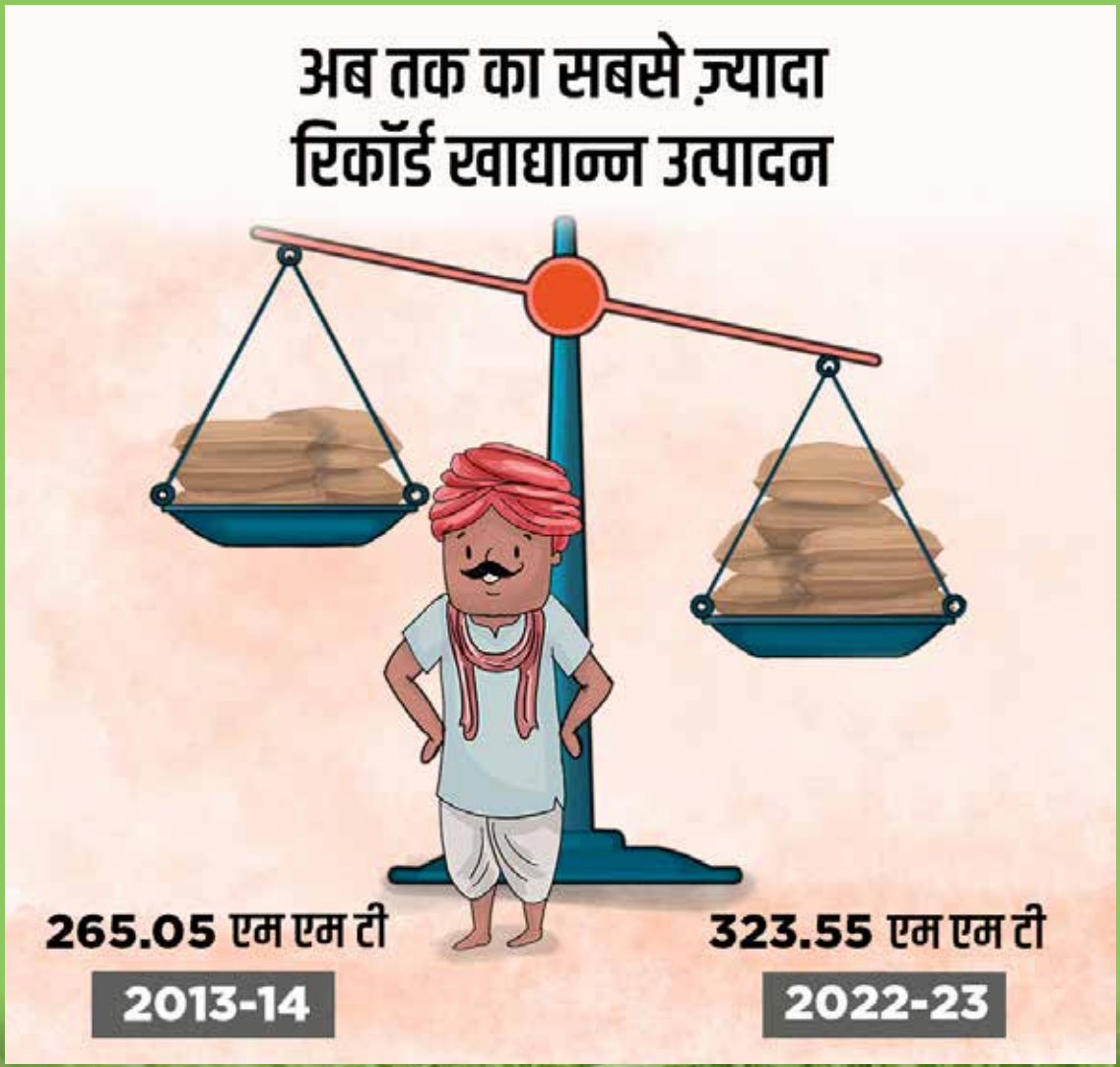
अब तक का सबसे ज़्यादा
रिकॉर्ड खाद्यान्न उत्पादन
265.05 एम एम टी
2013-14
323.55 एम एम टी
2022-23

गेहूँ के लिए एम एस पी का भुगतान
2.39
लाख करोड़ रुपये
2006-14
4.52
लाख करोड़ रुपये
2014-22

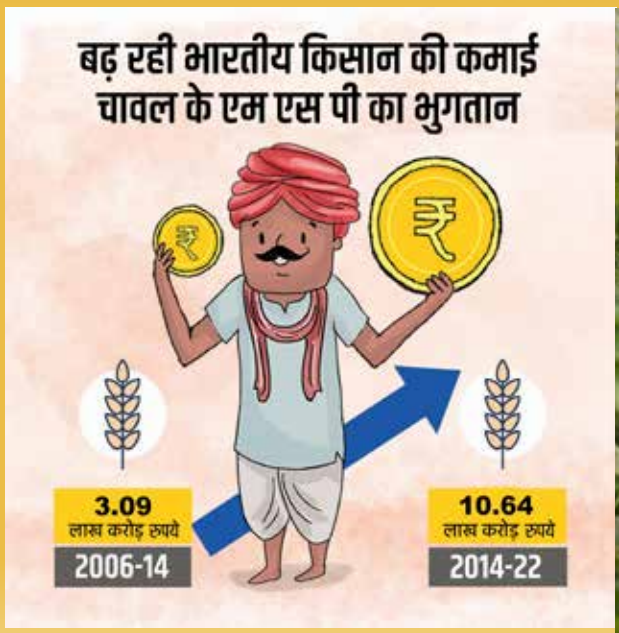
बढ़ रही भारतीय किसान की कमाई
चावल के एम एस पी का भुगतान
3.09
लाख करोड़ रुपये
2006-14
10.64
लाख करोड़ रुपये
2014-22

किसानों की आय के साधन बढ़े

सोलर पैनल

बंजर भूमि पर सोलर पैनल लगा कर आमदनी में बढ़ोतरी को प्रोत्साहन।

दुग्ध उत्पादन में वृद्धि

दुग्ध उत्पादन में 2014-15 से 2021-22 के बीच 51.05% की सालाना वृद्धि।

Blue Revolution की शुरुआत

पूरा फोकस केंद्रित करने के लिए अलग Department of Fisheries

SWEET REVOLUTION

पिछले 9 साल में शहद का निर्यात दोगुना।

इथेनॉल की खरीद

2013-14 में 38 करोड़ लीटर के मुकाबले 2021-22 में 434 करोड़ लीटर इथेनॉल की खरीद।

अंतर्राष्ट्रीय मिलेट (श्री अन्न) वर्ष

मोटे अनाज के महत्व को पहचान कर लोगों को पोषक भोज्य पदार्थ उपलब्ध कराने और स्वदेशी व वैश्विक मांग का सृजन करने के क्रम में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की पहल पर भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में वर्ष 2023 को अंतरराष्ट्रीय मिलेट (श्री अन्न) वर्ष के रूप में घोषित कराने में अग्रणी भूमिका निभाई। भारत के इस प्रस्ताव को 72 देशों ने समर्थन दिया और मार्च 2021 में ही संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2023 को अंतरराष्ट्रीय मिलेट (श्री अन्न) वर्ष के रूप में घोषित कर दिया।

एम एस पी पर दालों की खरीद में 54.08 गुना वृद्धि

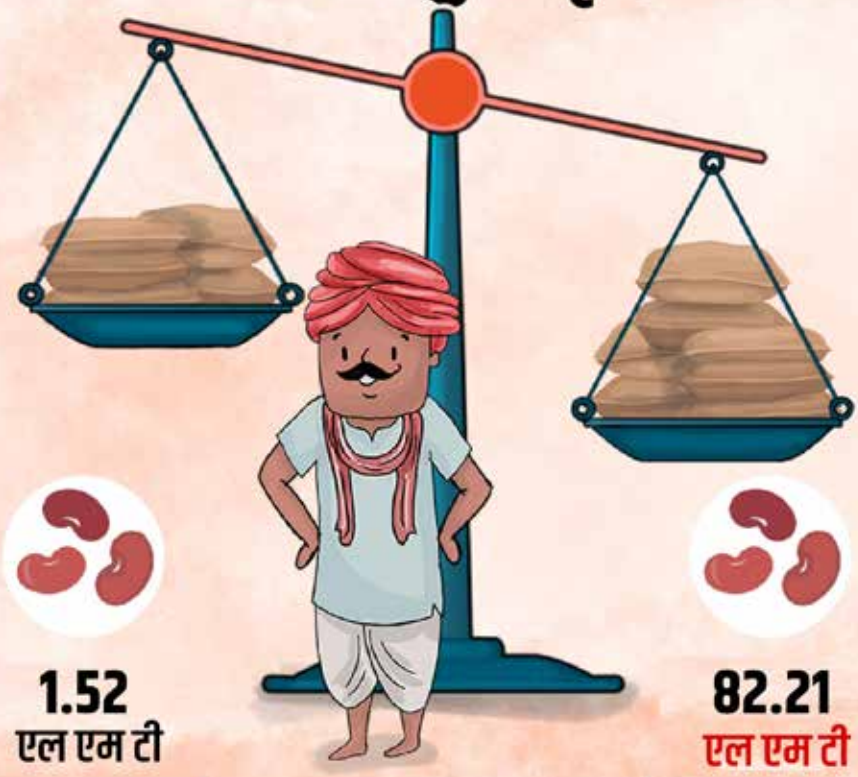

1.52
एल एम टी
2009-14

82.21
एल एम टी
2019-23

बढ़ रही भारतीय किसान की कमाई
चावल के एम एस पी का भुगतान
Rs. 1310
प्रति क्विंटल
2013-14
Rs. 2040
प्रति क्विंटल
2022-23

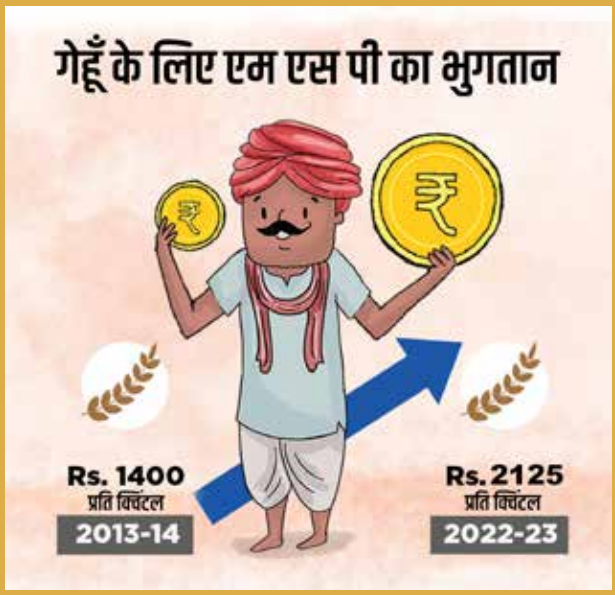
गेहूँ के लिए एम एस पी का भुगतान
Rs. 1400
प्रति क्विंटल
2013-14
Rs. 2125
प्रति क्विंटल
2022-23

शहरी महिलाओं से लेकर गांव में रहने वाली महिलायें हों, कारोबार रोजगार में व्यस्त महिलायें हों, या घर के काम में व्यस्त महिलायें हों, उनके जीवन को आसान बनाने के लिए बीते 9 वर्षों में सरकार ने अनेक कदम उठाएँ हैं।

-नरेन्द्र मोदी

नारी शक्ति हो रही और ताकतवर

3

सारांश

भारत का विकास दरअसल देश की महिलाओं के विकास से अटूट रूप से जुड़ा हुआ है। इसे देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने बीते नौ वर्षों में नारी शक्ति को भारत की विकास यात्रा में सबसे आगे रखा है।

मोदी सरकार का मानना है कि सशक्तिकरण वन स्टॉप समाधान नहीं है, बल्कि इसके लिए महिला सशक्तिकरण के लिए जीवनचक्र-आधारित दृष्टिकोण की आवश्यकता है। इस संबंध में, महिलाओं के लिए कल्याणकारी कार्यक्रम इस तरह से तैयार किए गए हैं कि जीवन के विभिन्न चरणों में उनके सशक्तिकरण के लिए सामाजिक आर्थिक बाधाओं को दूर करने में उनकी सहायता की जा सके।

मिशन पोषण एक एकीकृत पोषण सहायता कार्यक्रम है ताकि बच्चों, किशोर लड़कियों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं में कुपोषण की चुनौतियों का समाधान किया जा सके। इसमें पोषण सामग्री और वितरण में एक रणनीतिक बदलाव लाया गया है और इसमें एक ऐसे संमिलित इकोसिस्टम का निर्माण किया जाता है जो ऐसी प्रथाओं को विकसित और प्रोत्साहित करे जो स्वास्थ्य, कल्याण और प्रतिरक्षा का पोषण करती हों। मिशन शक्ति की बात करें तो इसमें महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए दो उप-योजनाएं संबल और सामर्थ्य शामिल हैं। नारी अदालत के एक नए घटक के साथ वन स्टॉप सेंटर (ओएससी), महिला हेल्पलाइन (181-डब्ल्यूएचएल), और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ (बीबीबीपी) की मौजूदा योजनाओं को संबल उप-योजना का हिस्सा बनाया गया है। वहीं प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई), शक्ति सदन (उज्ज्वला और स्वाधार गृह), कामकाजी महिला छात्रावास (सखी निवास) और राष्ट्रीय शिशुगृह योजना (पालना) जैसी योजनाओं को सामर्थ्य में शामिल किया गया है।

इन पहलों का प्रभाव परिणामों में स्पष्ट हो रहा है, जैसे कि शिशु जन्म दर में बेहतर लिंगानुपात, जो अब पहली बार प्रति 1000 पुरुषों पर 1020 महिलाएं हुआ हैं, वहीं संस्थागत प्रसव में वृद्धि, शिशु मृत्यु दर में कमी और मातृ मृत्यु दर में कमी आई है।

महिलाओं को सम्मान भरा जीवन प्रदान करना मोदी सरकार के शासन का एक बुनियादी वादा है। यह वादा उज्ज्वला योजना के तहत एलपीजी सिलेंडरों के बढ़ते उपयोग में प्रकट होता है, जिसने धुंआ मुक्त रसोई के माध्यम से करोड़ों महिलाओं को श्वसन संबंधी बीमारियों से बचाया है। स्वच्छ भारत अभियान की सफलता के साथ, करोड़ों महिलाएं अब बिना किसी असुरक्षा की भावना और सम्मान के उल्लंघन के अपने घरों में शौचालय का उपयोग कर ही हैं।

दैनिक खपत के लिए पानी लाने के लिए लंबी दूरी तय करना अतीत की बात होती जा रही है क्योंकि देश भर के घरों में जल जीवन मिशन के तहत नल के पानी के कनेक्शन मिल रहे हैं।

महिला सशक्तिकरण महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण पर निर्भर है। मुद्रा योजना जैसे कार्यक्रम, जिसमें महिलाओं को 68% ऋण दिया गया है, ने देश भर में करोड़ों महिलाओं को सूक्ष्म स्तर की उद्यमशीलता को आगे बढ़ाने और वित्तीय रूप से स्वतंत्र बनने में सक्षम बनाया है। महिलाओं के बीच वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए महिला सम्मान बचत प्रमाणपत्र को केंद्रीय बजट 2023-24 के हिस्से के रूप में पेश किया गया, जो विशेष रूप से महिला निवेशकों के लिए एक छोटी बचत योजना है।

पीएम आवास योजना के तहत, महिलाओं को घर का मालिक बनाया जा रहा है, इस प्रकार वे घरेलू निर्णय लेने में सक्रिय भागीदार बन रही हैं।

मोदी सरकार के 9 साल में महिलाएं लगातार ताकतवर होती गई हैं। उनकी सफलता को महिला पुलिस कर्मियों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि, देश के लिए खिलाड़ियों द्वारा जीते गए सम्मान और विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित के क्षेत्र में महिलाओं के संख्या से देखा जा सकता है।

सरकार ने महिलाओं को कल्याणकारी या मदद प्राप्त करने वालों के बजाए सशक्तिकरण के एजेंट में तब्दील कर दिया है। आज यह महिला विकास नहीं है, बल्कि महिलाओं के नेतृत्व में विकास बन गया है।

* * *

मुख्य बातें

भारत में पहली बार प्रति 1,000 पुरुषों पर
1,020 महिलाएं
(NFHS-5)

पेड मैटरनिटी लीव
12 सप्ताह से बढ़ाकर
26 सप्ताह
की गई

प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत
3.94 करोड़
नि:शुल्क प्रसव पूर्व जांच

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत
3.03 करोड़
से अधिक महिलाओं को सहायता

जन औषधि केंद्रों में
1 रुपये में
27 करोड़
से अधिक सैनिटरी पैड उपलब्ध कराए गए

3.18 करोड़
सुकन्या समृद्धि योजना
खाते खुले

9.6 करोड़
स्वच्छ ईंधन युक्त रसोई

करीब 2.5 करोड़
पीएम आवास-ग्रामीण लाभार्थियों में से
68.9%
महिलाएं

महिलाओं को मिले
27 करोड़
से अधिक
मुद्रा लोन

सशस्त्र बलों में महिलाओं के लिए
स्थायी कमीशन

लिंगानुपात
NFHS-4 में 991 से बढ़कर NFHS-5 में **1020** हुआ

2018-20 में
मातृ मृत्यु दर
घटकर 97 रह गई है

उपलब्धियां

महिलाएं पीएम मोदी का समर्थन क्यों करती हैं- महिला सशक्तिकरण के लिए सामाजिक बदलाव

- लड़कियों की **शादी की उम्र** 18 से **बढ़ाकर** 21 वर्ष करने का प्रस्ताव शिक्षा और रोजगार में मददगार।
- **तीन तलाक के खिलाफ कानून** से मुस्लिम महिलाओं की शोषण से सुरक्षा।
- **Paid Maternity Leave की अवधि** 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह करने से कामकाजी महिलाओं के लिए जीवन हुआ आसान।
- **Article 35A** के अंत से जम्मू-कश्मीर में महिलाओं को वो अधिकार मिले, जिन्हें पहले ऐतिहासिक रूप से नकार दिया गया था।

* * *

सरकार के बड़े काम

क्या आप जानते हैं ?

मुद्रा योजना के तहत लोन लेने वाले करीब 40 करोड़ लोगों में से 69 प्रतिशत महिला उद्यमी हैं, साथ ही सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त लगभग आधे स्टार्ट-अप्स का नेतृत्व महिलाओं द्वारा किया जा रहा है।

जीवन चक्र आधारित अप्रोच व्यापक स्तर पर मददगार

जन्म

चुनौती:
जन्म लेने की

समाधान:
बेटी बचाओ
बेटी पढ़ाओ

परिणाम:
भारत का समग्र लिंगानुपात 1020 (प्रति 1000 पुरुषों) हुआ

बेटियां

चुनौती:
पोषण तक पहुंच

समाधान:
मिशन पोषण

परिणाम:
उचित पोषण सुनिश्चित करने के लिए कुल 1.81 लाख करोड़ रुपये से अधिक का परिव्यय

स्कूलिंग

चुनौती:
अलग शौचालय तक पहुंच

समाधान:
स्वच्छ विद्यालय ने हर स्कूल में शौचालय सुनिश्चित किया

परिणाम:
स्कूलों में छात्राओं के लिए 9.52 लाख अलग शौचालय का निर्माण

शिक्षा

चुनौती:
वित्तीय संसाधनों तक पहुंच

समाधान:
45 लाख लड़कियों / महिलाओं को छात्रवृत्ति

परिणाम:
3.18 करोड़ से अधिक सुकन्या समृद्धि खातों में 80,000 करोड़ रूपए

महिलाओं को हर कदम पर, प्रत्येक निर्णय और हर अवस्था में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन मोदी सरकार ने ऐसी पहल की है, जहां हर चुनौती के लिए एक समाधान है।

रोजगार

चुनौती:
अवसरों तक पहुंच

समाधान:
नई महिला कर्मचारियों के लिए ईपीएफओ अंशदान को घटाया गया

परिणाम:
अंशदान 12% से घटकर 8%

राष्ट्र की सेवा

चुनौती:
सशस्त्र बलों में प्रवेश प्रतिबंधित

समाधान:
सभी विंग में महिलाओं को स्थायी कमीशन

उद्यमिता

चुनौती:
फंड तक पहुंच

समाधान:
महिलाओं को मिले 27 करोड़ से अधिक मुद्रा लोन

परिवार

चुनौती:
निर्णय लेने की शक्ति

समाधान:
2.5 करोड़ से अधिक PMAY-ग्रामीण घरों में से 70 प्रतिशत में महिलाएं स्वयं/संयुक्त रूप से घरों की मालिक हैं।

महिलाओं से संबंधित विभिन्न नतीजों में सुधार
भारत का समग्र लिंगानुपात (प्रति 1000 पुरुष पर)
943
2011
1,020
2019-21
मातृ मृत्यु दर
167
2011-13
97
2018-20

अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस
के अवसर पर
राष्ट्रीय आजीविका

विकसित भारत के विज़न को लेकर देश की अमृतयात्रा का नेतृत्व हमारे युवा ही कर रहे हैं।

-नरेन्द्र मोदी

भारत की अमृत-पीढ़ी हो रही सशक्त

4

सारांश

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का यह बयान खासा चर्चित रहा है, "दुनिया ने मान लिया है कि भारत के पास दो असीमित शक्तियां हैं - जनसांख्यिकी और लोकतंत्र।" भारत में वर्तमान में दुनिया की सबसे ज्यादा युवा आबादी है और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली सरकार अपनी इस क्षमता का पूर्ण रूप से दोहन करने के लिए प्रतिबद्ध है।

2020 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) ने 30 साल से ज्यादा वक्त के बाद मौजूदा शिक्षा प्रणाली का कायाकल्प कर दिया है। एनईपी भारतीय स्कूल और उच्च शिक्षा प्रणाली में एक आदर्श बदलाव की कल्पना करती है जो भारतीय लोकाचार में निहित है, अधिक ज्ञान पर केंद्रित है और इसका उद्देश्य भारत को वैश्विक स्तर पर ज्ञान की महाशक्ति बनाना है। पिछले नौ साल के दौरान, देश भर में रिकॉर्ड संख्या में नए आईआईटी, आईआईएम, मेडिकल कॉलेज और विश्वविद्यालय खुले हैं। मोदी सरकार का शिक्षा के साथ-साथ शिक्षा, कौशल और कौशल विकास पर भी जोर रहा है। पीएम कौशल विकास योजना के लॉन्च के बाद से, 1.37 करोड़ से अधिक युवाओं ने इस योजना के तहत कौशल प्रशिक्षण प्राप्त किया है, जिससे उनके लिए रोजगार की संभावनाओं में सुधार हुआ है।

युवाओं के लिए नए औपचारिक रोजगार सृजित करने की मोदी सरकार की प्राथमिकता की सफलता को नए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन खातों में भारी वृद्धि के रूप में देखा जा सकता है। भारत को निवेश के एक आकर्षक केंद्र में बदलने की दिशा में लगातार प्रयास, एमएसएमई को सहायता और घरेलू उत्पादन के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम आदि कार्यक्रमों ने युवा भारतीयों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने में योगदान दिया है।

सरकार ने केंद्र सरकार में 10 लाख नौकरियों के लिए एक भर्ती अभियान रोजगार मेला शुरू किया है। अग्निपथ योजना के तहत युवाओं को सशस्त्र बलों में सेवा करने का अवसर भी दिया जा रहा है। इससे सशस्त्र बलों में नए 'जोश' और 'जज़्बे' का संचार होगा, साथ ही तकनीक तौर पर ज्यादा कुशल सेना की दिशा में एक बड़ा बदलाव लाएगा।

सरकार का जोर सिर्फ रोजगार सृजित करने पर ही नहीं, बल्कि उद्यमिता का विकास, युवाओं को रोजगार खोजने वाले से रोजगार देने वाला बनाने पर भी है। पहले जहां लोग जोखिम लेने से बचते थे और वेतनभोगी नौकरियों का विकल्प चुनते थे, इसके विपरीत आज युवा अनुकूल नीतिगत माहौल के कारण आगे बढ़ने को उत्सुक हैं।

2016 में शुरू किए गए स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम के माध्यम से, मोदी सरकार ने कई कर लाभ प्रदान करके, नियमों को आसान बनाकर और अनुपालन बोझ को कम करके उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए कई उपाय किए हैं।

उद्यमशीलता की तरह, खेल को अधिकांश युवाओं के लिए पेशेवर नहीं माना जाता था, और उन्हें इनमें पेशेवर रूप से आगे बढ़ने के प्रति हतोत्साहित किया जाता था। हालांकि, पीएम मोदी एक महत्वपूर्ण व्यवहार और मानसिकता में बदलाव लेकर आए और कई नीतियां पेश कीं, जिससे असंख्य युवाओं को खेल को करियर बनाने में मदद मिली है। भारत ने वर्ष 2021 में टोक्यो ओलंपिक और पैरालिंपिक के दौरान इतिहास में अब तक का सबसे अच्छा प्रदर्शन देखा है। यह मुख्य रूप से टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम के माध्यम से दीर्घकालिक योजना और समर्थन का परिणाम रहा है। जैसे कि भारत अमृत काल में प्रवेश कर चुका है, इसका जनसांख्यिकीय लाभांश तेजी से सामाजिक, आर्थिक और तकनीकी नवाचार और उन्नति के युग में प्रवेश करने के लिए विशिष्ट रूप से तैयार है। पिछले नौ वर्षों के दौरान सरकार अपने सभी लक्ष्यों और प्रयासों में युवाओं का समर्थन करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध रही है।

* * *

मुख्य बातें

करीब चार दशक बाद
राष्ट्रीय शिक्षा नीति!

2016 से मान्यता प्राप्त स्टार्ट-अप की संख्या में
100 गुना वृद्धि

टॉप्स कार्यक्रम
के तहत टॉप्स कोर ग्रुप में **98** और टॉप्स डेवलपमेंट ग्रुप में **182** एथलीटों को मदद

टोक्यो 2020 में अब तक का
सर्वश्रेष्ठ ओलंपिक
(7 पदक) और पैरालंपिक (19 पदक) खेल प्रदर्शन

पीएम कौशल विकास योजना के तहत
1.37 करोड़
लोगों को प्रशिक्षित किया गया

7 नए आईआईएम
स्थापित, 2022 तक कुल संख्या 20

पीएम श्री योजना के तहत
14,500 स्कूल
और बेहतर बनाए जाएंगे तथा उनका विकास होगा

2017-2021 के बीच टेक स्टार्ट-अप्स द्वारा
23 लाख
प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष नौकरियों का सृजन

23 एम्स के साथ भारत में **एम्स की संख्या**
तिगुनी

देश भर में
7 नए IIT
खुले, अब कुल 23 IIT (2023)

राष्ट्रमंडल खेल 2022 में
61
पदक

390
नए विश्वविद्यालय
स्थापित

उपलब्धियां

भारतीय युवा: Job Seekers से Job Creators तक

- पीएम मोदी बदल रहे हैं समाज की सोच और लोगों के बीच बढ़ रहा है **जोखिम उठाने वालों का सम्मान**।
- Self-Employment और Entrepreneurship रोजगार के लोकप्रिय विकल्प बन रहे हैं।
- विभिन्न योजनाओं का लक्ष्य **Entrepreneurs को Institutional Support** देना है।

2021: भारतीय खेलों के लिए अविस्मरणीय वर्ष

- भारत ने टोक्यो ओलंपिक और पैरालंपिक में **अब तक का सबसे अधिक मेडल जीता**
- 2014 से जारी **दीर्घकालिक योजना** से ही रिकॉर्ड सफलता तक पहुंचे
- **TOPS Programmes** के माध्यम से खिलाड़ियों को मिला व्यापक सहयोग
- खेलो इंडिया से हुआ पूरे भारत में खेल-संस्कृति का निर्माण और **खेल बन गए जन आंदोलन**।

युवा भारत के लिए रोजगार हो रहे सुनिश्चित

- मजबूत आर्थिक नीतियां सालाना रोजगार के लाखों नए अवसर पैदा कर रही हैं।
- 2022-23 में 448 बिलियन डॉलर से अधिक का **रिकॉर्ड निर्यात** हुआ। इसमें Goods Exports का बड़ा हिस्सा शामिल था।
- **1.37 करोड़** लोगों को प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत **Skilled किया गया**, ताकि रोजगार के अवसर बढें।
- **4.78 करोड़ नए EPFO Subscribers** 2017 और जनवरी 2023 के बीच जोड़े गए, यानि इतने नए लोगों को नौकरी मिली।
- 1.2 करोड़ नए EPFO खाते देश में **महामारी के बावजूद** 2021-22 में खोले गए।
- ज्यादातर सर्वे **महामारी के पहले के वर्षों की तुलना में कम बेरोजगारी** और ज्यादा भर्तियों को लेकर मजबूत संकेत दे रहे हैं।
- **मुद्रा योजना** ने करोड़ों नए Entrepreneurs की मदद की है और नए रोजगार सृजित किए हैं।
- **23 लाख प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष नौकरियों का सृजन** टेक स्टार्ट-अप ने 2017-2021 के दौरान किया (NASSCOM)

* * *

क्या आप जानते हैं?

डायरेक्ट जॉब इंडिकेटर्स

- अप्रैल 2020 से 18-28 वर्ष की आयु वर्ग के 2.09 करोड़ से अधिक युवाओं को EPFO में जोड़ा गया
- नौकरी जॉब स्पीक इंडेक्स ने जनवरी 2021 में 1,925 से जनवरी 2022 में 2,716 की अप्रत्यक्ष नौकरी संकेतक की 41% की प्रभावशाली वृद्धि देखी
- कैपिटल गुड्स सेक्टर में कौशल, रीस्किलिंग और अपस्किलिंग कार्यबल को बढ़ाने के लिए स्किल काउंसिल द्वारा स्किल लेवल 6 में 46 क्वालीफ़िकेशन पैकेज बनाये गये।
- डब्ल्यूआरआई त्रिची हब-स्पोक मॉडल में पूंजीगत वस्तु योजना चरण- II के तहत नवीन वेल्डिंग तकनीकों में 5000 युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए बुनियादी ढांचा स्थापित कर रहा है

इनडायरेक्ट जॉब इंडीकेटर्स

- 2022-23 में भारत का माल निर्यात रिकॉर्ड 448 अरब डॉलर के स्तर पर पहुंच गया
- जनवरी 2022 की तुलना में जनवरी 2023 में इंजीनियरिंग निर्यात 55.54% अधिक रहा
- 2021-22 में परिधान निर्यात में 30% की वृद्धि देखी गई। यह अनुमान है कि प्रत्येक अतिरिक्त $1 बिलियन परिधान निर्यात 1.5 लाख नौकरियां पैदा करते हैं!

सरकार के बड़े काम

युवाओं की 'Can Do' की भावना को पीएम मोदी का अटूट समर्थन

स्टार्ट-अप संस्कृति के विकास के लिए प्रतिबद्ध

"एक और बदलाव जो अब दिख रहा है, वह यह है कि पहले जब कोई युवा स्टार्ट-अप शुरु करता था तो लोग अक्सर ये पूछा करते थे कि "आप कोई नौकरी क्यों नहीं करते? स्टार्ट-अप ही क्यों ? लेकिन अब लोग कहते हैं, 'नौकरी तो ठीक है, लेकिन आप अपना कोई स्टार्ट-अप क्यों नहीं खड़ा कर लेते?' और जो युवा पहले से ही स्टार्ट-अप में हैं उनके लिए पहली प्रतिक्रिया ये होती है, वाह ! यह आपका स्टार्ट-अप है।"

Prarambh- Startup India International Summit-2021 में पीएम मोदी का संबोधन।

युवा हो रहे प्रोत्साहित

"आज के युवाओं में 'Can Do' की जो भावना है, वह आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत है।"

राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2022 में पीएम मोदी का संबोधन (12 जनवरी, 2022)

युवाओं की ऊर्जा को सामर्थ्यवान बनाना

"मैं युवाओं की ऊर्जा को देश की ऊर्जा में बदलने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हूं।"

Start-Ups के साथ संवाद के दौरान पीएम मोदी का संबोधन (जनवरी 15, 2022)

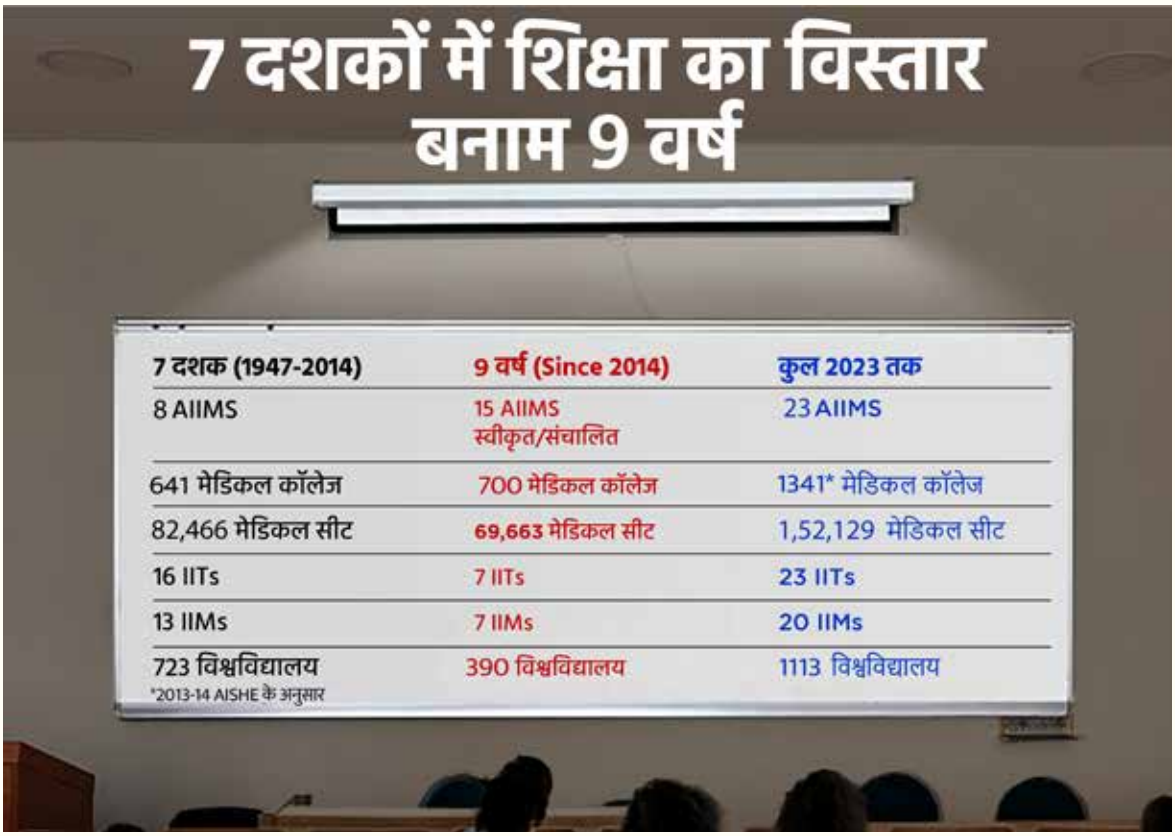

* मेडिकल के अन्तर्गत दंत चिकित्सा, एलोपैथी, आयुर्वेद और होमियोपैथी होंगे शामिल

ऑल इंडिया सर्वे ऑफ़ हायर एडुकेशन 2020-2021 के अनुसार

अमृत काल के पंच-प्रण

विकसित भारत का लक्ष्य

गुलामी के हर अंश से मुक्ति

अपनी विरासत पर गर्व

एकता और एकजुटता

नागरिकों में कर्तव्य की भावना

“

हमारा लक्ष्य सभी का कल्याण और भलाई है। हमारा लक्ष्य सबका शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कल्याण है।

-नरेन्द्र मोदी

”

मध्यम वर्ग का जीवन हुआ आसान

5

सारांश

एक घर का मालिक होना एक प्रतिष्ठित जीवन स्तर की निशानी है, जिसमें नल से पानी, खाना पकाने के लिए ईंधन, स्वच्छता, बिजली और इंटरनेट के साथ सुरक्षा बीमा, कर लाभ और सार्वजनिक उपयोगिताओं तक आसान पहुंच जैसी बुनियादी सुविधाएं हों। 2014 से, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने प्रत्येक भारतीय के जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए अथक प्रयास किया है।

मोदी सरकार ने सभी भारतीयों को सम्मानजनक जीवन प्रदान करने के अपने प्रयासों को आगे बढाते हुए एक घर के सपने को हकीकत में बदल दिया है। मोदी सरकार ने अपने कल्याणकारी कार्यक्रमों के माध्यम से यह सुनिश्चित किया है कि समाज के सभी वर्गों के नागरिकों को बैंकिंग, एलपीजी कनेक्शन, स्वच्छता, बिजली, नल का पानी, सस्ती स्वास्थ्य सेवा और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध हों। पीएम आवास योजना के तहत ब्याज दरों में कमी और मोदी सरकार की क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना ने लोगों को अपना पहला घर खरीदने में सक्षम बनाया है। इसके साथ-साथ, रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण (आरईआरए, रेरा) अधिनियम 2016 को लागू करने जैसे कदमों के माध्यम से नियामक ढांचे को मजबूत करना यह सुनिश्चित करता है कि नागरिकों की जीवन भर की कमाई एक कानूनी ढांचे द्वारा सुरक्षित है जो घर खरीदने वालों के अधिकारों को बरकरार रखती है।

स्वामित्व योजना ग्रामीण क्षेत्र में बसे हुए इलाकों में संपत्ति के स्पष्ट स्वामित्व की स्थापना की दिशा में एक सुधारात्मक कदम है। इसमें ड्रोन तकनीक का उपयोग करके भूमि खंडों का मानचित्रण करना और संपत्ति के मालिकों को कानूनी स्वामित्व कार्ड (संपत्ति कार्ड/टाइटल डीड) जारी करने के साथ ग्रामीण क्षेत्र में घर के मालिकों को 'अधिकारों का रिकॉर्ड' प्रदान करना शामिल है।

कर में कमी और सस्ती उधार दरों ने मध्यम वर्ग के परिवारों के लिए बड़े पैमाने पर बचत और उनकी खर्च करने की क्षमता को बढाया है। आयकर छूट और प्रत्यक्ष कर सुधारों में सकारात्मक बदलाव ने उन पर कर के बोझ को कम किया है और मध्यम वर्ग के लिए टैक्स भरने को आसान बना दिया है। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (जीएसटी) ने उपभोक्ताओं के लिए दैनिक खर्चों में कमी का कारण बना है।

"उड़े देश का आम नागरिक" (उड़ान) योजना, जो अब अपने छठे वर्ष में है, ने आम आदमी के लिए हवाई यात्रा सस्ती और सुविधाजनक बना दी है। इसने कई टियर 2 और टियर 3 शहरों को हवाई मार्ग से जोडा है और यह सुनिश्चित किया है कि हवाई यात्रा सभी के लिए सुलभ हो। 2014 के बाद से देश में परिचालन हवाई अड्डों की संख्या दोगुनी हो गई है।

शहरी नागरिकों के लिए परिवहन और दैनिक आवागमन को आसान बनाने के लिए, कई शहरों में रिकॉर्ड संख्या में मेट्रो रेल परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है और चालू की गई है। नागरिक अब निजी वाहनों से सार्वजनिक परिवहन की ओर जा रहे हैं और अपने आराम से समझौता किए बिना काफी बचत कर रहे हैं।

भारत में उभर रही डिजिटल भुगतान क्रांति ने वैश्विक ध्यान आकर्षित किया है। जनवरी 2023 में, लगभग 200 बिलियन डॉलर (लगभग 2 लाख करोड़ रुपये) के लगभग आठ बिलियन (800 करोड़) लेनदेन यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (UPI) पर किए गए थे। इस प्रणाली का उपयोग अब करीब 300 मिलियन व्यक्तियों और 50 मिलियन व्यापारियों द्वारा किया जाता है। छोटे से छोटे लेन-देन के लिए भी डिजिटल भुगतान किया जा रहा है, जिसमें लगभग 50 प्रतिशत को छोटे या सूक्ष्म भुगतान के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

भारत के डिजिटल परिवर्तन और कनेक्टिविटी को नई ऊंचाइयों पर ले जाते हुए, प्रधान मंत्री ने हाल ही में भारत में 5 जी सेवाओं की शुरुआत की। यह उच्च तकनीक प्रौद्योगिकी के साथ भारत के लिए असीम संभावनाओं को खोलता है और कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, परिवहन, रसद, स्मार्ट शहरों, उद्योग 4.0, वित्तीय समावेशन आदि सहित महत्वपूर्ण क्षेत्रों में परिवर्तन लाने का मार्ग प्रशस्त करता है।

सरकार ने पिछले नौ वर्षों में विभिन्न उपायों के माध्यम से अपने नागरिकों के दैनिक जीवन में सुधार लाने पर ध्यान केंद्रित किया है। सभी भारतीयों के लिए जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने का यह प्रयास 'सबका साथ, सबका विकास' के प्रधान मंत्री के व्यापक दृष्टिकोण के अनुरूप है।

* * *

मुख्य बातें

7 लाख रुपये
तक की आय तक
फुल टैक्स रिबेट

प्रभावी कर की दर 2013-14 में 19.22% से **घटकर** 2022 में 10.4% हो गई (15 लाख रुपये प्रति वर्ष)

उमंग ऐप
के माध्यम से **21,801 से अधिक सरकारी सेवाओं** तक पहुंच

रुकी हुई रियल एस्टेट परियोजनाओं को फिर से चलाने के लिए **स्वामी फंड** के तहत
25,000 करोड़ रुपये

30 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में **रेरा** द्वारा
1 लाख से अधिक
मामलों का निपटारा

सीएलएसएस
ने होम लोन के **59,048 करोड़ रुपये का बोझ कम किया**

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी और ग्रामीण)
के तहत
3 करोड़
से अधिक घर

2014 में
मेट्रो
5 शहरों से बढ़कर अब (2023)
20 शहरों में पहुंची

UDAN
योजना के तहत **1.16 करोड़ से अधिक** लोगों ने सस्ती हवाई यात्रा का लाभ उठाया

12.90 करोड़
से अधिक **डिजिलॉकर** उपयोगकर्ता

इंटरनेट डेटा की कीमतें
97% घटी

4,355 शहरों को
ओडीएफ
का दर्जा

उपलब्धियां

अब टैक्स की नो टेंशन...

- **ई-फाइलिंग** सामान्य प्रक्रिया बनी
- **रिफंड** अब कुछ दिनों में मिलता है, महीनों में नहीं
- Faceless Assessments और Appeals से **उत्पीड़न में कमी**
- Tax Rates में वास्तविक रूप से **कमी**

एक विश्वसनीय सरकार, विश्वास करने वाली सरकार

- मोदी सरकार ने **परस्पर विश्वास के माहौल** का वातावरण बनाया
- Self-Attestation जैसे कदम इस बात का प्रमाण है कि सरकार को अपने नागरिकों पर भरोसा है
- IT Returns की संख्या साल 2013-14 के 3.91 करोड़ से बढ़कर साल 2022-23 में 7.60 करोड़ तक पहुंच गई। इससे पता चलता है कि **जनता सरकार पर भरोसा** करती है कि उनके टैक्स का सदुपयोग हो रहा है।

सबकी पहुंच में अपने घर का सपना

- **गरीब के लिए**, ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में पीएम आवास योजना
- **मध्यम वर्ग के लिए** 01-01-2017 से 31-03-2023 तक सीएलएसएस ने मध्यम वर्गीय आय समूह के लिये आवास ऋण के ब्याज दरों में कमी की। जिससे 6 लाख मध्यम वर्गीय ख़रीदारो को मदद मिली।
- **RERA** ने समय पर घरों की डिलीवरी सुनिश्चित की, ताकि घर खरीदने वालों का पैसा न फंसे

शहरों के बीच बढ़ा संपर्क, सफर हुआ आसान

- **मेट्रो रेल के विस्तार** से शहरों में रहने वालों की यात्रा और सुविधाजनक हुई
- **उड़ान** योजना से सस्ती हवाई यात्रा, टियर-2 और टियर -3 के कई शहर इससे जुड़े
- **कार लोन की ब्याज दर में** 2014 के मुकाबले **कमी**।

* * *

क्या आप जानते हैं?

- 40% भारतीय आयुष्मान भारत के अंतर्गत सुरक्षित हैं
- भारत के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा अनुमान के अनुसार, पूंजीगत व्यय सहित प्रति व्यक्ति व्यय 2015-16 में ₹1261, 2016-17 में ₹1418 और 2017-18 में ₹1753 था
- भारत ने इंटरनेट कनेक्शन में 231% (83.4 करोड़) की वृद्धि दर्ज की
- दुनिया के सबसे सस्ते सैनिटरी पैड (1 रुपया) 9304 से ज़्यादा जनऔषधि केंद्रों में उपलब्ध कराए गए
- 26 सप्ताह के पेड मैटरनिटी लीव के साथ चीन, सिंगापुर, जर्मनी और अमेरिका से कहीं ऊपर भारत
- भारत में 2014 से अब तक 5,700 से अधिक नए कॉलेज खुले, यानी प्रतिदिन लगभग 2 नए कॉलेज
- वंदे भारत मिशन ने लगभग 2.17 लाख उड़ानें संचालित कीं और दुनिया भर से 2.97 करोड़ से अधिक लोगों को भारत लाया गया

सरकार के बड़े काम

जुड़ रहा है भारत: आम लोगों का जीवन हो रहा सुगम

मेट्रो:
2014 में केवल 5 शहरों तक मेट्रो कनेक्टिविटी, अब 20 शहरों तक पहुंची

इलेक्ट्रिक बसें:
अब 2435 इलेक्ट्रिक बसें फेम -II के तहत देशभर में सेवारत

हवाई यात्रा:
Operational Airports की संख्या करीब दोगुना हुई, 2014 के 74 से 2023 में 148 तक पहुंची

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी तमिलनाडु के चेन्नई हवाई अड्डे के नए एकीकृत टर्मिनल भवन के उद्घाटन के मौके पर

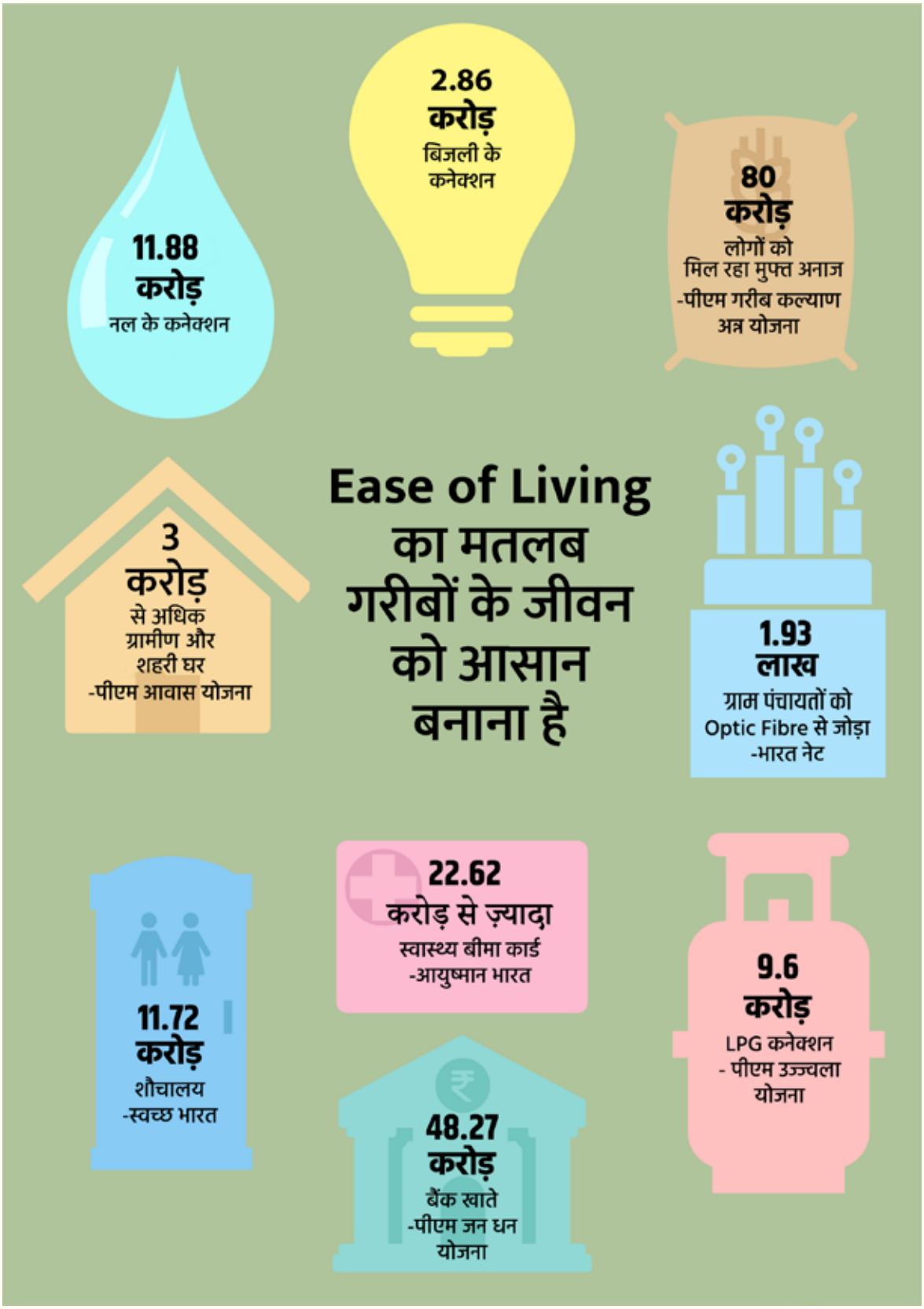
Ease of Living का मतलब गरीबों के जीवन को आसान बनाना है
11.88 करोड़ नल के कनेक्शन
2.86 करोड़ बिजली के कनेक्शन
80 करोड़ लोगों को मिल रहा मुफ्त अनाज -पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना
3 करोड़ से अधिक ग्रामीण और शहरी घर -पीएम आवास योजना
1.93 लाख ग्राम पंचायतों को Optic Fibre से जोड़ा -भारत नेट
11.72 करोड़ शौचालय -स्वच्छ भारत
22.62 करोड़ से ज़्यादा स्वास्थ्य बीमा कार्ड -आयुष्मान भारत
9.6 करोड़ LPG कनेक्शन - पीएम उज्ज्वला योजना
48.27 करोड़ बैंक खाते -पीएम जन धन योजना

मध्यम वर्ग के लिए
EASE OF LIVING सुनिश्चित
मध्यम वर्ग के जीवन का एक दिन
RERA के कारण घर मिलेंगे सही समय पर
UPI
BHIM यूपीआई के माध्यम से किराना खरीदारी और परिवहन का भुगतान आसान और त्वरित हुआ
नवनिर्मित मेट्रो से काम पर जाना हुआ आसान
TAX
ई-फाइलिंग के माध्यम से कर देनदारी आसान और परेशानी मुक्त हुई
कुछ ही घंटों के रिकार्ड टाइम में आयकर रिफ़ंड
भारतीय जन औषधि परियोजना
माता पिता के लिए जन औषधि केंद्र से दवाओं की खरीद, बाजार भाव से 50% कम कीमतों पर
LED
उजाला LED लाइट्स से बिजली के बिल में भारी बचत

रोजगार मेला- 10 लाख कर्मियों के लिए भर्ती अभियान। अधिक से अधिक रोजगार सृजित करने के लिए सरकार एक साथ कई मोर्चों पर काम कर रही है

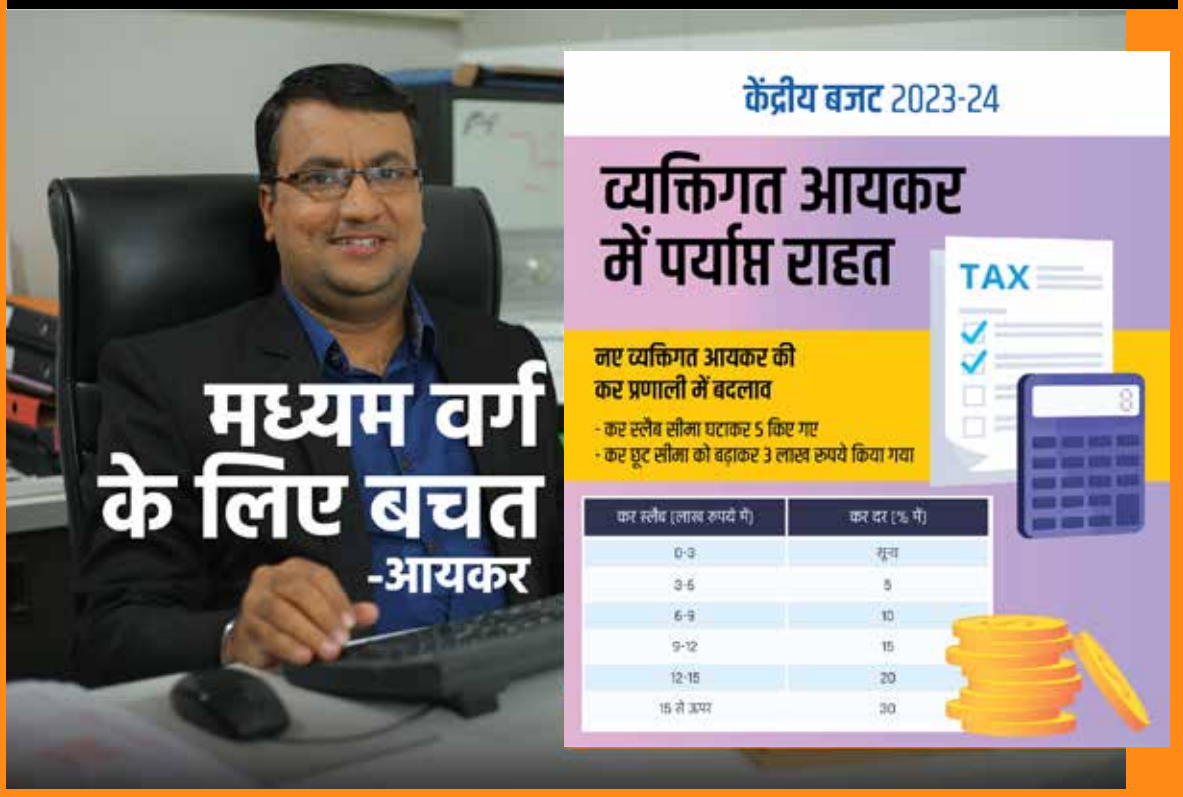

मोबाइल
120 करोड़ उपभोक्ता
- धन का सुगम एवं तेज प्रवाह
- सीधे लाभार्थियों तक पहुंचना
- दोहराव एवं धोखाधड़ी में कमी
AADHAAR
आधार
133 करोड़
आधार आवंटित
जन-धन खाते
48.27 करोड़
जन-धन खाते

“

हमने तय किया कि किसी भी गरीब को पैसे के अभाव में अपना इलाज टालना न पड़े। हमने यह सुनिश्चित करने की कोशिश की कि हमारे गरीब परिवारों को भी उनके घरों के पास बेहतर इलाज मिले।

-नरेन्द्र मोदी

”

सभी के लिए सस्ती, सुलभ स्वास्थ्य सेवा

6

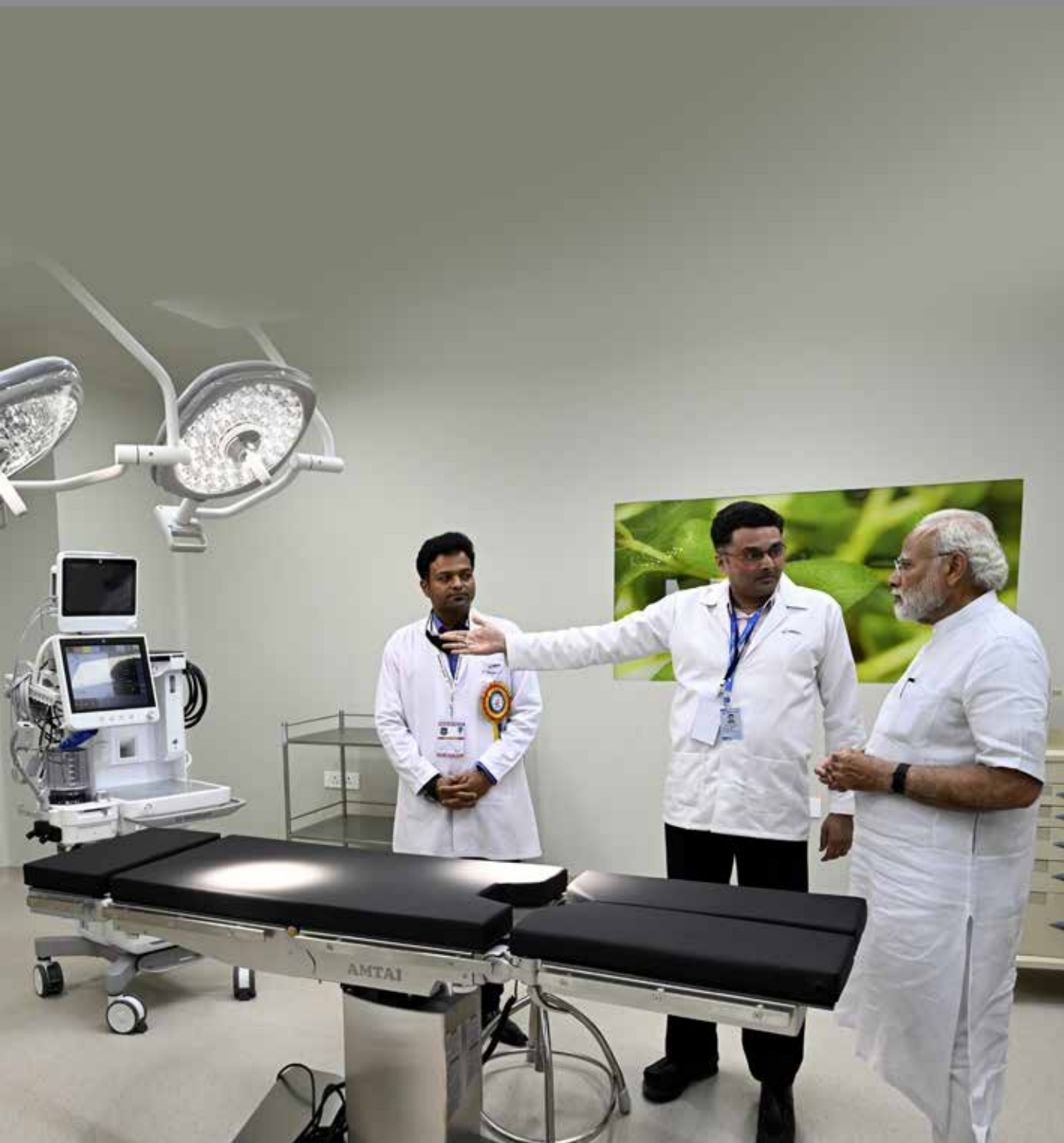

सारांश

पिछले नौ वर्षों के दौरान नरेंद्र मोदी सरकार के लिए स्वास्थ्य और आरोग्य क्षेत्र प्रमुख मुद्दों में से एक रहा है। टीकों की 220 करोड़ से अधिक खुराक देने और जरूरत के समय दुनिया को भारी संख्या में टीकों का निर्यात करने के साथ-साथ वैश्विक महामारी से भारत की जीत में यह महत्वपूर्ण घटक रहा है।

सभी के लिए सुलभ और सस्ती स्वास्थ्य सेवा सरकार की प्राथमिकता रही है और भारत के नागरिकों के लिए एक वास्तविकता बन गई है। पहले, कम आय वाले परिवारों के लिए चिकित्सा पर होने वाले खर्च भारी आर्थिक बोझ डाल देता था और अक्सर उन्हें कर्ज के जाल में फंसा देता था। 2018 में मोदी सरकार ने आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के रूप में दुनिया का सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम की शुरुआत की थी। यह योजना लगभग 22 करोड़ भारतीयों को चिकित्सा पर खर्च के बोझ से बड़ी राहत दे रही है। इसके अलावा, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (एबीडीएम) डिजिटल रूप से जुड़े स्वास्थ्य सेवा पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण के लक्ष्य को साकार कर रहा है।

25 करोड़ से अधिक लोगों के स्वास्थ्य रिकॉर्ड को उनके आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खातों (एबीएचए) से जोड़ा गया है। डिजिटल रूप से उपलब्ध स्वास्थ्य रिकॉर्ड एबीएचए धारकों को एबीडीएम नेटवर्क में कागज रहित स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाने में सक्षम बनाएंगे।

सरकार का टेलीमेडिसिन कार्यक्रम - ई-संजीवनी देश के स्वास्थ्य क्षेत्र में काफी बदलाव ला रहा है। इसके माध्यम से 10 करोड़ से अधिक लाभार्थी अपने घर से ही गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा प्राप्त करने में सक्षम हुए हैं, जिसने विशेषज्ञ चिकित्सा देखभाल सेवाओं में शहरी-ग्रामीण अंतर को पाटा है। 700 से अधिक जिलों में स्थित 9000 से अधिक जन औषधि केंद्र सभी को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक दवाएं उपलब्ध करा रहे हैं।

सरकार टीके से रोके जा सकने वाले किसी भी रोग से लोगों को बचाने के लिए प्रतिबद्ध है। इस संबंध में मिशन इंद्रधनुष के विभिन्न चरणों में 4.45 करोड़ बच्चों और 1.2 करोड़ गर्भवती महिलाओं को 12 बीमारियों के टीके लगाये जा चुके है। इस लक्षित सरकारी पहल के कारण देश में मातृ मृत्यु दर जो 2014-16 में यह दर 130 प्रति लाख जन्म से घट कर 2018-20 में यह दर 97 प्रति लाख जन्म हो गयी है।

मोदी सरकार द्वारा चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण बदलाव लाया गया है। सरकारी कॉलेजों की संख्या में कमी, निजी मेडिकल कॉलेजों की भारी फीस, और सीट आवंटन में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार ने चिकित्सा शिक्षा के अवसरों को गंभीर रूप से सीमित कर दिया था। पिछले नौ वर्षों में मोदी सरकार द्वारा कई राज्यों में नए एम्स और बड़ी संख्या में नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना की गयी है। इनमें पूर्वोत्तर में असम में अब तक का पहला एम्स शामिल है। इसके अलावा, भारतीय चिकित्सा परिषद को राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग से बदले जाने के सरकार के साहसिक निर्णय ने चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में भ्रष्टाचार को समाप्त कर दिया है। 'न्यू इंडिया' में साधारण पृष्ठभूमि से आये प्रतिभाशाली छात्र भी अब डॉक्टर बनने का सपना पूरा कर सकते हैं।

कोविड-19 महामारी पर भारत की त्वरितऔर प्रभावी प्रतिक्रिया को दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान के रोलआउट द्वारा मजबूती मिली, वह भी स्वदेशी रूप से विकसित टीकों का उपयोग करके। अतीत से एक ऐतिहासिक बदलाव में, जब नागरिकों को टीकाकरण अभियान शुरू करने के लिए दशकों तक इंतजार करना पड़ता था, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने दो साल की छोटी अवधि में कोविड वैक्सीन की 2.2 बिलियन से अधिक खुराक का टीकाकरण सुनिश्चित किया।

पिछले नौ वर्षों में भारत ने स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में काफी प्रगति की है। ऐसी सरकार जो स्वास्थ्य सेवा में निवेश करती है, वह अपने लोगों में निवेश करती है और इस प्रकार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार वास्तव में लोगों की, लोगों के लिए और लोगों द्वारा बनायी गयी सरकार है।

* * *

मुख्य बातें

आयुष्मान भारत
के तहत
4.54 करोड़
अस्पताल भर्ती

1.59 लाख से अधिक
आयुष्मान भारत
स्वास्थ्य और आरोग्य केंद्र

9,304
से अधिक
जन औषधि केंद्र

मिशन इन्द्रधनुष द्वारा
5.65 करोड़
से अधिक माताओं और बच्चों को मिली टीकों की सुरक्षा

15
नए एम्स और
225
मेडिकल कॉलेज जोड़े जा रहे हैं

3 करोड़
से अधिक नागरिकों ने **अमृत फार्मेसियों** से सस्ती दवाएं खरीदकर बचत की

220 करोड़
से अधिक COVID वैक्सीन डोज
दिए गए

37 करोड़
से ज़्यादा डिजिटल हेल्थ आईडी बनाए गए

जन औषधि केंद्रों के कारण
नागरिकों के लगभग
23,000 करोड़
रुपये बचे

2014 से अब तक कुल
69,663
मेडिकल सीट जोड़ी गईं

केंद्र सरकार द्वारा
1,500 से अधिक
पीएसए संयंत्र स्वीकृत

एचडब्ल्यूसी के माध्यम से
15 करोड़
टेली-परामर्श

उपलब्धियां

सक्रिय नेतृत्व बना संकटमोचक

- ऐसे समय में जब कई वैश्विक नेता COVID-19 के खतरे को भांपने में विफल रहे, भारत में एक भी मामला सामने आने से पहले ही **हवाई अड्डों पर स्क्रीनिंग** शुरु कर दी गई थी।
- कई अन्य देशों द्वारा इसे गंभीरता से लेने से बहुत पहले ही मार्च 2020 के प्रथम सप्ताह में **पीएम मोदी ने कह दिया था कि वह होली मिलन जैसे समारोहों से बचेंगे** और एक मिसाल कायम करेंगे।
- **विश्व स्वास्थ्य संगठन** के ऐलान से बहुत पहले ही भारत के बहुत बड़े हिस्से में मास्क को अनिवार्य घोषित कर दिया गया था।
- जब कई देश केवल बड़े पैमाने पर लोगों की मौत पर मंथन कर रहे थे, तब अप्रैल 2020 में भारत ने लोगों की जान बचाने के लिए **वैक्सीन टास्क फोर्स का गठन** कर दिया था।
- भारत ने WHO की सिफारिश से बहुत पहले **Rapid Antigen Tests** शुरु कर दिया था, ताकि **जांच में तेजी** लाई जा सके।
- भारत ने **शुरुआत में ही लॉकडाउन** का ऐलान कर दिया था, इसे पूरी दुनिया ने स्वीकारा और सराहा। इससे देश में मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने में मदद मिली।

प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन (PM-ABHIM) के साथ भारत का भविष्य सुरक्षित

- **64,180 करोड़** रुपये का निवेश।
- Focus States के 10 राज्यों के 17,788 ग्रामीण स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों के लिए सहायता।
- सभी राज्यों में 11,024 शहरी Health और Wellness केंद्रों की स्थापना।
- Focus States के 11 राज्यों में 3,382 ब्लॉक **सार्वजनिक स्वास्थ्य इकाइयां**।
- सभी जिलों में Integrated **Public Health Labs** की स्थापना।
- 5 लाख से अधिक आबादी वाले सभी जिलों में **क्रिटिकल केयर अस्पताल ब्लॉक** की स्थापना।

डिजिटल है सफलता की एकमात्र कुंजी- ABDHM

- CoWIN और Aarogya Setu की सफलता से **Healthcare में Tech की ताकत** दिखी।
- आयुष्मान भारत डिजिटल हेल्थ मिशन (ABDHM) Healthcare के लिए एक Online Platform तैयार कर रहा है।
- नागरिकों ने अपना ABHA (आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता) नंबर बनाया है, इनसे उनके **Digital Health Records जुड़े होते हैं**।
- नागरिकों की सहमति से, इस डेटा तक Healthcare Professionals द्वारा पहुंचा जा सकता है।
- ABDM **Evidence-Based Decision Making** की सुविधा देता है, इससे प्रभावी Health Intervention में मदद मिलती है।
- **37.07 करोड़ ABHA** बनाए जा चुके हैं!

* * *

भारत में टीकाकरण- इतिहास और वर्तमान

टीका	दुनिया में शुरुआत	भारत में शुरुआत
कोविड-19	दिसंबर 2020	एक महीना
IPV	1955	60 वर्ष
TT	1926	57 वर्ष
BCG	1927	51 वर्ष
खसरा	1971	46 वर्ष
DPT	1948	30 वर्ष
हेपेटाइटिस बी	1982	20 वर्ष
न्यूमोकोकल	2000	17 वर्ष
रोटावायरस	2006	10 वर्ष

जिस गति से भारत में COVID-19 टीके विकसित किए गए, वो इस न्यू इंडिया का जीता जागता उदाहरण है, जहां अब टीकों के लिए दशकों तक इंतजार नहीं करना पड़ता या दूसरे देशों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता है।

सरकार के बड़े काम

गरीबों की हर Healthcare जरूरत के लिए
व्यापक कवरेज

रोगों से बचाव के लिए
मिशन इंद्रधनुष

5 करोड़ से अधिक गर्भवती महिलाओं और बच्चों का टीकाकरण

AYUSH और योग को बढ़ावा

प्राथमिक सेवा के लिए
आयुष्मान भारत- स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र

1.5 लाख HWCs

उच्च रक्तचाप जांच - 35.43 करोड़

मधुमेह जांच - 30.5 करोड़

Teleconsultation– 15 करोड़

AB-HWCs पर सामान्य कैंसर (मुख, स्तन, गर्भाशय) की कुल जांच - 37.5 करोड़

Secondary और Tertiary care के लिए
आयुष्मान भारत- PMJAY

5 लाख रुपये का स्वास्थ्य कवर

आयुष्मान कार्ड - 23.19 करोड़

अस्पताल में दाखिले - 4.54 करोड़

इलाज का खर्च - 54,758 करोड़

दवाओं के लिए
जन औषधि केंद्र

9304 केंद्र कम कीमत पर देते हैं दवाएं

पिछले 9 वर्षों में नागरिकों के 23,000 करोड़ रुपये की बचत

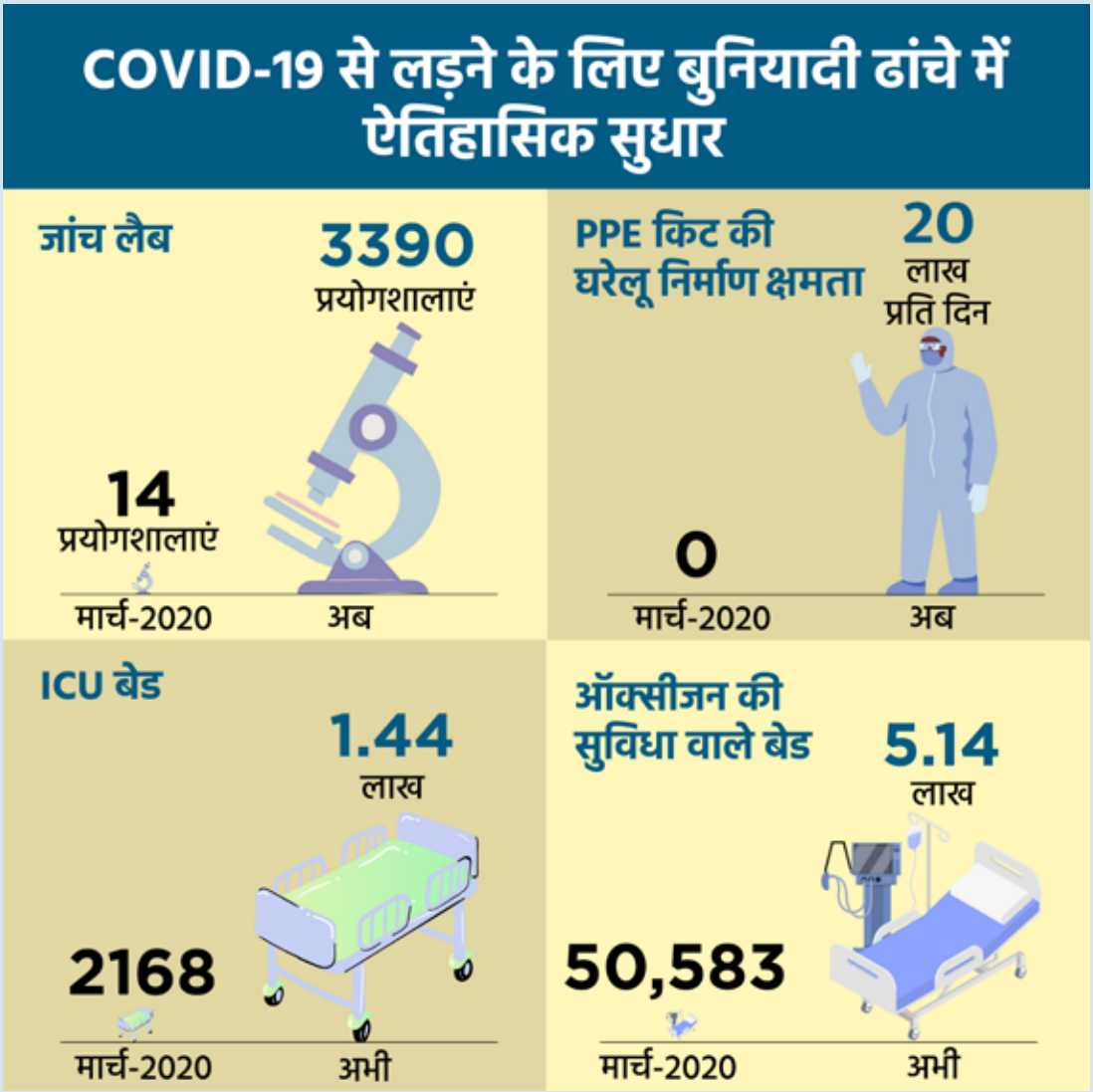
COVID-19 से लड़ने के लिए बुनियादी ढांचे में ऐतिहासिक सुधार
जांच लैब
3390
प्रयोगशालाएं
14
प्रयोगशालाएं
मार्च-2020
अब
PPE किट की घरेलू निर्माण क्षमता
20
लाख
प्रति दिन
0
मार्च-2020
अब
ICU बेड
1.44
लाख
2168
मार्च-2020
अभी
ऑक्सीजन की सुविधा वाले बेड
5.14
लाख
50,583
मार्च-2020
अभी

अभिनव समाधानों से कोविड प्रबंधन सुधार

ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन
लगभग 900 ऑक्सीजन एक्सप्रेस रेलगाड़ियों से 36,840 टन से अधिक तरल ऑक्सीजन पंहुचायी गयी।

वायु सेना
क्रायोजेनिक टैंकर लाने - ले जाने के लिये वायु सेना की मदद ली गयी।

आइसोलेशन कोच
रेलवे ने 4,176 कोचों को क्वारंटीन/पृथकवास केंद्रों में बदला

मेक शिफ्ट फैसिलिटी
अर्द्ध सैनिक बलों और केंद्रीय एजेंसियों ने मेकशिफ्ट क्वारंटीन केंद्र संचालित किये।

पीएसए संयंत्र
केंद्र सरकार द्वारा 1500 से अधिक पीएसए संयंत्र मंजूर किये गये।

भारत के कोविड टीकाकरण की रफ्तार और उपलब्धियां
उपलब्धियां हासिल करने के लिए निरंतर प्रयास
> 17 सितंबर 2021 को एक ही दिन में कोविड के 2.5 करोड़ टीके लगाए गए
9 months
9 months
Started on 16th Jan'21
50 Cr
75 Cr
100Cr
150 Cr
175Cr
200Cr
220 Cr
7th Aug'21
14th Sept'21
21st Oct'21
7th Jan'22
19th Feb'22
17 July'22
31st Mar'23
100 करोड़ टीके लगाने में लगे दिन-279 (21 अक्टूबर, 2021)
150 करोड़ टीके लगाने में लगे दिन-358 (07 जनवरी, 2022)
200 करोड़ टीके लगाने में लगे दिन-548 (17 जुलाई, 2022)

प्रधानमंत्री मोदी द्वारा असम के गुवाहाटी में पूर्वोत्तर के पहले एम्स का उद्घाटन

भारत ने जी-20 की अपनी अध्यक्षता के लिए 'एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य' की विषयवस्तु का चयन किया है। यह उद्देश्य में एकता और कार्रवाई में एकता की जरूरत का संकेत देती है।

-नरेन्द्र मोदी

‘राष्ट्र प्रथम’- विदेश नीति और राष्ट्रीय सुरक्षा

7

सारांश

पिछले नौ वर्षों में, नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने एक गतिशील और परिवर्तन आधारित विदेश नीति की परिकल्पना की है और इसका कार्यान्वयन किया है, जो परिणाम-उन्मुख, विकास-केंद्रित और सरकार के "सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास" के विज़न के अनुरूप है।

भारत की विदेश नीति का प्राथमिक ध्यान, 'पड़ोसी प्रथम' नीति (नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी) के तहत, अपने नजदीकी पड़ोसी देशों पर है। इसे 'एक्ट ईस्ट', 'थिंक वेस्ट' और 'कनेक्ट सेंट्रल एशिया' नीतियों द्वारा सशक्त बनाया गया है, जो विस्तारित पड़ोस में हमारे संपर्क को और बढ़ाना चाहते हैं। सरकार के विज़न, 'भारत-प्रशांत क्षेत्र' में क़ानून-आधारित व्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए समान विचारधारा वाले भागीदारों के साथ संबंधों को मजबूत करने के लिए 'क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास' (ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन) - 'सागर' को डिज़ाइन किया गया है।

अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (आईएसए), आपदा सहनीय अवसंरचना के लिए गठबंधन (सीडीआरआई), पर्यावरण-अनुकूल जीवनशैली (लाइफ) और इंटरनेशनल बिग कैट एलायंस (आईबीसीए) जैसी नई पहलों ने दुनिया के साथ हमारे बहुपक्षीय संबंधों को और मजबूत किया है। दुनिया भर में भारत की उपस्थिति का विस्तार करने के सरकार के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए, मिशनों, वाणिज्य दूतावासों और प्रतिनिधि कार्यालयों की संख्या बढ़ाने के लिए भी महत्वपूर्ण प्रयास किये गए हैं।

भारत ने 1 दिसंबर, 2022 को जी-20 की अध्यक्षता ग्रहण की है। भारत की अध्यक्षता की थीम "वसुधैव कुटुम्बकम" या "एक पृथ्वी-एक परिवार-एक भविष्य" विशिष्ट रूप से भारतीय है और इसकी व्यापक रूप से सराहना की गयी है।

हाल ही में भारत द्वारा जी20 बैठकों के आयोजन की संख्या 100 को पार कर गयी है। अप्रैल 2023 तक, 110 से अधिक राष्ट्रों के 12,300 से अधिक प्रतिनिधियों ने जी20 से संबंधित बैठकों में भाग लिया है। इनमें जी20 सदस्य देशों, आमंत्रित देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की भागीदारी शामिल हैं।

ई-शासन से जुड़े तरीकों के उपयोग के माध्यम से भारत के दूतावास परिचालन को विश्व स्तर पर सबसे तेज, सबसे पारदर्शी और उपयोगकर्ता-अनुकूल बनाया गया है। भारत ने विदेशों में भारतीय कामगारों के हितों की रक्षा के लिए सामाजिक सुरक्षा समझौतों पर हस्ताक्षर किये हैं, छात्रों, पेशेवरों और शोधकर्ताओं के पारस्परिक आवागमन को बढ़ाने के लिए समझौते हुए हैं एवं अवैध प्रवासन को रोकने के लिए कई देशों के साथ समझौते किये गए हैं।

मानवीय संकट के समय, भारत 'कार्रवाई करने वाले प्रथम राष्ट्र' के रूप में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। मानवीय संकट के दौरान प्रयासों के समन्वय के लिए विदेश मंत्रालय में एक विशेष प्रभाग के रूप में त्वरित कार्रवाई प्रकोष्ठ की स्थापना ने आपदा प्रोटोकॉल को और अधिक सहनशील बना दिया है। भारत ने पिछले 9 वर्षों के दौरान विभिन्न राहत और निकासी अभियान चलाए हैं, जिनमें प्रमुख हैं - ऑपरेशन कावेरी (2023), ऑपरेशन दोस्त (2023), ऑपरेशन गंगा (2022) और ऑपरेशन देवी शक्ति (2021) आदि।

राष्ट्रीय सुरक्षा मोदी सरकार के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता रही है। आतंक नीति के खिलाफ जीरो-टॉलरेंस अपनाने के साथ-साथ देश में वामपंथी उग्रवाद में महत्वपूर्ण कमी दर्ज की गयी है।

प्रधानमंत्री का दृढ़ विश्वास है कि विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा साथ-साथ चलते हैं और इसने रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा दिया है। भारत का पहला स्वदेशी विमानवाहक पोत आईएनएस विक्रांत, स्वदेशी निर्माण के क्षेत्र में देश की बढ़ती ताकत को प्रदर्शित करता है। वित्त वर्ष 2022-23 में, रक्षा निर्यात लगभग 16,000 करोड़ रुपये के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया है। नवाचार और प्रौद्योगिकी विकास को बढ़ावा देने के लिए, रक्षा उत्कृष्टता नवाचार (आईडीईएक्स) फ्रेमवर्क लॉन्च किया गया है। इसने सफल प्रोटोटाइप विकास के लिए स्टार्ट-अप्स और नवोन्मेषकों को समर्थन देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

आज दुनिया के अवसरों का लाभ प्राप्त करने और चुनौतियों का जवाब देने के लिए एक गतिशील विदेश नीति और राष्ट्रीय सुरक्षा नीति आवश्यक है। एक स्थिर, मजबूत और सुरक्षित राष्ट्र बनाने के लिए, मोदी सरकार ने इस मोर्चे पर लगातार काम किया है।

* * *

मुख्य बातें

युद्धग्रस्त सूडान से
3000+
भारतीयों को वापस लाया गया

अनुच्छेद 370 और **अनुच्छेद 35ए** को हटाने का ऐतिहासिक निर्णय

वित्त वर्ष 2034-24 में पूंजी अधिग्रहण बजट का
75%
घरेलू उत्पादन के लिए

रक्षा निर्यात में पिछले पांच सालों में
334% बढ़ोतरी

वंदे भारत मिशन, एयर बबल उड़ानों द्वारा
2.97 करोड़
से अधिक लोगों को लाया गया

रक्षा स्वदेशीकरण सूची में
4100 से अधिक आइटम जोड़े गए

23,000
भारतीयों की **यूक्रेन से सुरक्षित वतन वापसी** हुई

ऑपरेशन दोस्त के तहत
5945 टन
आपातकालीन राहत खेप सीरिया और तुर्की भेजी गई

ऑटोमैटिक रूट से **रक्षा क्षेत्र** में
74% FDI

डिफेंस स्टार्टअप्स के लिए करीब
500 करोड़ रु.
स्वीकृत
(2021-22 से 2025-26 तक)

ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को
7 रक्षा सार्वजनिक उपक्रमों
में बदला गया

वैक्सीन मैत्री के माध्यम से 100 से अधिक देशों के लिए
29.2 करोड़
से अधिक COVID-19 वैक्सीन

उपलब्धियां

आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस

- 2014 के बाद से non-Conflict zones वाले भारतीय शहरों में **कोई बड़ा आतंकवादी हमला नहीं**
- **वर्ष 2016 में सर्जिकल स्ट्राइक और 2019 में एयर स्ट्राइक** से सीमा पार आतंकवाद को मुंहतोड़ जवाब
- आतंकवाद के प्रायोजकों को **वैश्विक स्तर पर अलग-थलग** किया और उनके प्रभाव को कम किया
- भारत ने **आतंकवाद को न केवल वैश्विक मुद्दा** बनाया, बल्कि वो इसके खिलाफ लड़ाई का नेतृत्व भी कर रहा है।
- **UAPA** Amendment से कानूनी ढांचे को मजबूत बनाया

Positive Indigenisation क्या है और इसका महत्व

- प्रमुख उपकरणों वाली 4100 से अधिक वस्तुओं की सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची जारी।
- इस लिस्ट में उन **Weapons, Arms और Systems का रोडमैप है, जिनका भारत भविष्य में आयात नहीं** करेगा।
- डीपीएसयू के लिए 3,700 से अधिक आइटम की 3 अलग-अलग सूचियों को अधिसूचित किया गया है।
- घरेलू खरीद के लिए इस प्रकार के रोडमैप के सामने आने से घरेलू निर्माताओं को उत्पादन बढ़ाने में मदद मिलती है।
- इससे भारत को रणनीतिक बढ़त मिलती है, साथ ही युवाओं के लिए रोजगार सृजन भी होता है।

आत्मनिर्भर रक्षा क्षेत्र के लिए निवेश

- **ऑटोमेटिक रूट के माध्यम से रक्षा क्षेत्र में FDI की सीमा 74%** हुई।
- 2023-24 **के बजट में रक्षा के लिए Capital Procurement Budget का 75% घरेलू उद्योग के लिए रखा गया।**
- उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में डिफेंस कॉरिडोर के लिए प्रोत्साहन
- उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में बन रहे डिफेंस कॉरिडोर से इस इलाके को आर्थिक मजबूती मिलेगी।

* * *

अग्निपथ

अग्निपथ सशस्त्र बलों के लिए एक परिवर्तनकारी योजना है, जो भारतीय सेना को युवा शक्ति, उच्च तकनीक से लैस और अति-आधुनिक दृष्टिकोण के साथ दुनिया में सर्वश्रेष्ठ सैन्य बल के रूप में कार्य करने जा रही है।सरकार ने 15 जून, 2022 को अग्निपथ योजना की शुरुआत की थी। योजना के तहत पुरुष और महिला दोनों उम्मीदवारों को **अग्निवीर** के रूप में चार साल की अवधि के लिए देश तीनों सेनाओं के 'अधिकारी के रैंक से नीचे' कैडर में भर्ती किया गया। 17.5 से लेकर 21 वर्ष की आयु के बीच के उम्मीदवार इस योजना के लिए आवेदन करने के पात्र हैं।

सरकार के बड़े काम

भारत के रक्षा निर्यात में वृद्धि
रक्षा निर्यातों का कुल मूल्य
16,000
करोड़ रूपए
2022-23
1,941
करोड़ रुपये
2014
अधिक रक्षा निर्यात का अर्थ है, रोजगार के अधिक अवसर

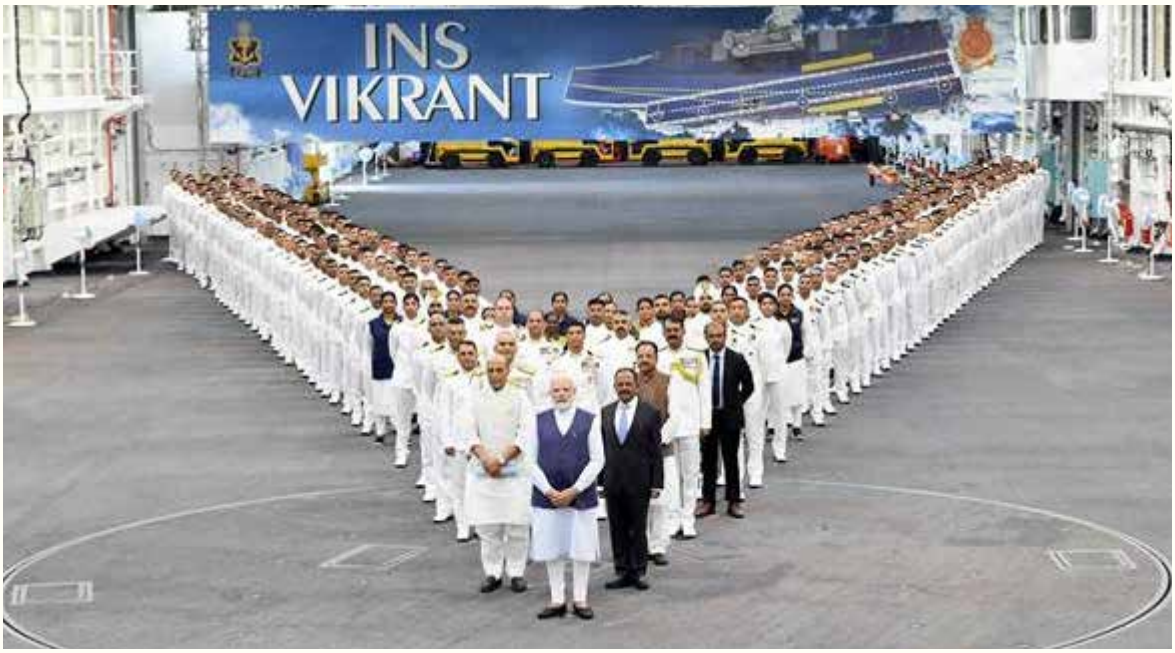
INS
VIKRANT

स्वदेश में विकसित हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर (LCH) को 'प्रचंड' नाम दिया गया है, जिसे भारतीय वायु सेना में शामिल किया गया है।

LCH दुनिया का एकमात्र लड़ाकू हेलिकॉप्टर है जो 5,000 मीटर की ऊंचाई पर हथियारों और ईंधन के अच्छे - खासे भार के साथ उतर और उड़ान भर सकता है।

सुरक्षा मामला : 2018 से जम्मू-कश्मीर में आतंकवादी घटनाओं में कमी

वर्ष	आतंकवादी घटनाएं
2018	228
2019	153
2020	126
2021	129
2022	125

भारत की G20 अध्यक्षता

सुधार, सद्भाव और आशा की अध्यक्षता

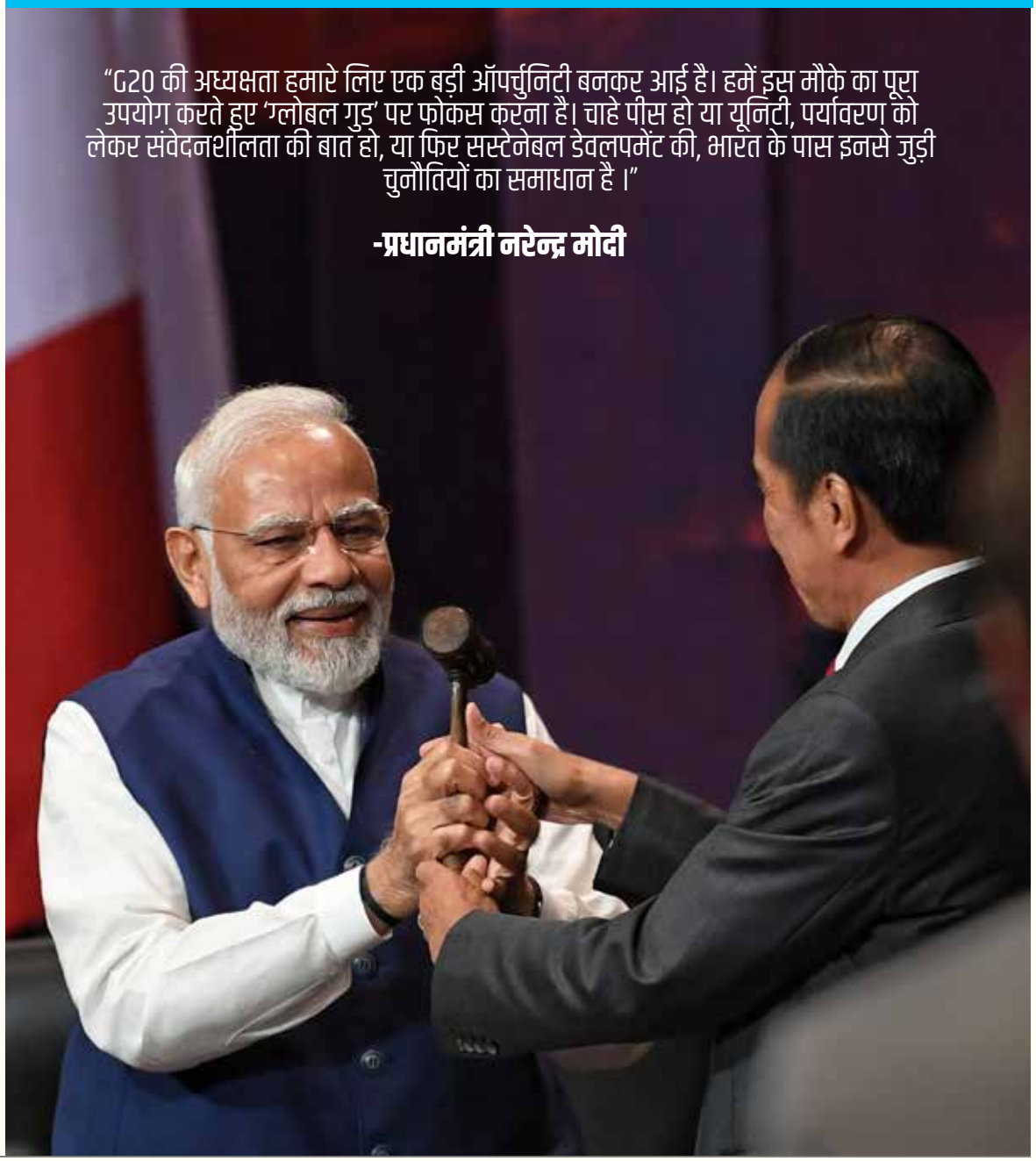

"G20 की अध्यक्षता हमारे लिए एक बड़ी ऑपर्चुनिटी बनकर आई है। हमें इस मौके का पूरा उपयोग करते हुए 'ग्लोबल गुड' पर फोकस करना है। चाहे पीस हो या यूनिटी, पर्यावरण को लेकर संवेदनशीलता की बात हो, या फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, भारत के पास इनसे जुड़ी चुनौतियों का समाधान है।"

-प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी

भारत 2023 INDIA

भारत की G20 अध्यक्षता

भारत ने 1 दिसंबर, 2022 से 30 नवंबर, 2023 के लिए इंडोनेशिया से जी 20 की अध्यक्षता ली थी। भारत की अध्यक्षता की विषय वस्तु "वसुधैव कुटुम्बकम" या "एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य" विशेष रूप से भारतीय है और इसकी व्यापक रूप से तारीफ भी हुई है।

भारत की जी 20 अध्यक्षता के दौरान निम्नलिखित विचार-विमर्श और नतीजे देखने को मिलेंगे-

13 शेरपा ट्रैक कार्यकारी समूह
8 फाइनेंस ट्रैक कार्य
4 रिसर्च इनोवेशन इनिशिएटिव गेदरिंग (आरआईआईजी) की पहल, जी20 सशक्तिकरण, स्पेस इकोनॉमी लीडर्स मीटिंग (एसईएलएम), चीफ साइंस एडवाइजर्स राउंड टेबिल (सीएसएआर)
11 इंगेजमेंट ग्रुप

हमारी जी 20 अध्यक्षता में आपदा के जोखिम में कमी (डीआरआर) पर एक नया कार्यकारी समूह, एक नया इंगेजमेंट ग्रुप "स्टार्टअप 20" और एक नई पहल चीफ साइंस एडवाइजर्स राउंडटेबिल (सीएसएआर) की शुरुआत की गई है।

भारत ने 17 अप्रैल, 2023 को वाराणसी में कृषि प्रमुख वैज्ञानिकों (एमएसीएस) की बैठक की मेजबानी के साथ अपनी जी 20 अध्यक्षता में 100वीं जी 20 की बैठक के रूप में एक अहम उपलब्धि हासिल की।

जी20 की 100 बैठकें 28 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 41 शहरों में हो चुकी हैं। ये बैठकें राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के पूर्ण समर्थन और भागीदारी के साथ भारत के हर कोने में आयोजित की जा रही हैं।

भारत की जी 20 अध्यक्षता के दौरान अभी तक की सबसे बड़ी व्यक्तिगत भागीदारी देखने को मिली है। अब तक हुई जी 20 से संबंधित बैठकों में 110 से अधिक देशों के 12,300 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया है। इसमें जी 20 सदस्यों, 9 आमंत्रित देशों और 14 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की भागीदारी शामिल है।

अध्यक्षता के दौरान भारत देश भर में लगभग 60 शहरों में 200 से ज्यादा जी 20 से संबंधित बैठकों के लिए विदेशी प्रतिनिधियों की मेजबानी करेगा। यह भौगोलिक क्षेत्र के लिहाज से जी 20 की सबसे ज्यादा व्यापक अध्यक्षता है।

अभी तक 7,000 से ज्यादा कलाकारों की भागीदारी के साथ 150 से ज्यादा सांस्कृतिक कार्यक्रम हो चुके हैं, जिनमें स्थानीय और राष्ट्रीय कलाओं का प्रदर्शन किया गया। भारत की जी 20 अध्यक्षता को "जनता का जी 20" बनाते हुए, समग्र राष्ट्र और समग्र समाज के दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर सक्रिय जनभागीदारी के साथ-साथ कई जन भागीदारी गतिविधियां भी आयोजित की जा रही हैं।

भारत की जी 20 अध्यक्षता के दौरान, प्रमुख विचार-विमर्शों में समावेशी और लचीले विकास; एसडीजी, हरित विकास और पर्यावरण के लिए जीवनशैली (एलआईएफई) पर प्रगति; तकनीक बदलाव और सार्वजनिक डिजिटल बुनियादी ढांचा; बहुपक्षीय संस्थानों में सुधार; महिलाओं की अगुआई में विकास; और अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सद्भाव जैसे व्यापक प्राथमिकता वाले क्षेत्र शामिल हैं।

सितंबर 2023 में जी 20 नई दिल्ली लीडर्स समिट के साथ इस अध्यक्षता का समापन हो जाएगा।

रक्षक पीएम मोदी!

यूक्रेन-2022

23,000 लोग बचाए गए

यूक्रेन-2014

1,000 लोग

ज्यादातर छात्र सुरक्षित निकाले गए

सीरिया-2014

जुलाई 2014 में ISIS द्वारा बंधक 46 भारतीय नर्सों को बचाया गया था।

इराक और सीरिया में संकट के दौरान **7,000** भारतीयों को सुरक्षित निकाला गया था।

लीबिया-2014

लीबिया संकट में फंसी 40 से अधिक भारतीय नर्सों को सुरक्षित घर पहुंचाया गया।

3,710 से अधिक भारतीयों को निकाला गया

यमन-2015

2015 में यमन में भारत ने न केवल अपने नागरिकों को बल्कि विदेशियों को भी बचाया।

ऑपरेशन राहत में **4,748** भारतीयों और 41 देशों के 1,962 विदेशियों को बचाया गया

सूडान-2016

जुलाई 2016 में दक्षिणी सूडान से **153 लोगों को** बचाया गया था।

नेपाल-2015

2015 में आए भूकंप से नेपाल तबाह हो गया था।
भारत ने ऑपरेशन मैत्री का संचालन किया और कई विदेशियों को, **5,188 भारतीयों को** बचाया

यमन-2017

2017 में, यमन से एक पादरी टॉम उज़ुन्नलिल को, जो 2016 में ISIS द्वारा अगवा कर लिया गया था, छुड़ाया गया

अफगानिस्तान–2021

2021 में जब अफगानिस्तान तालिबान के हाथों में चला गया, **550 से अधिक लोगों को** वहां से निकाला गया।

चीन-2020

2020की शुरुआत में, जब COVID-19 महामारी सामने आई, **637 भारतीयों को** वापस लाने के लिए वुहान के लिए उड़ानें भेजी गईं और **7 मालदीवियों** को भी बचाया गया।

श्री गुरु ग्रंथ साहिब के कई पवित्र सरुप वापस लाए। महान सम्मान प्रदर्शित करते हुए श्री गुरु ग्रंथ साहिब के 5 पवित्र सरुपों को बाद में दूसरी उड़ान से वापस लाया गया।

वंदे भारत मिशन

कोरोना महामारी के दौरान महत्वपूर्ण बचाव अभियान वंदे भारत मिशन के माध्यम से 2.17 लाख उड़ानों द्वारा 2.97 करोड़ से अधिक लोगों को वापस लाया गया!

ऑपरेशन दोस्त
भूकंप प्रभावित सीरिया और तुर्की में 5,945 टन आपात राहत सामग्री भेजी गई।

ऑपरेशन कावेरी
- युद्धग्रस्त सूडान से 3000 से अधिक भारतीयों को वापस लाया गया।
- एयरपोर्ट हेल्थ ऑफ़िसर्स द्वारा चलाये जा रहे कॉरांटाइन सेंटर्स में निःशुल्क आवास व भोजन की व्यवस्था।

“

ये दशक और आने वाले 25 साल भारत को लेकर अभूतपूर्व विश्वास के हैं। सबके प्रयास से ही भारत अपने लक्ष्यों को तेजी से प्राप्त करेगा।

-नरेन्द्र मोदी

”

भारत, वैश्विक आर्थिक महाशक्ति

8

सारांश

वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए पिछले कुछ वर्ष बड़े ही चुनौतीपूर्ण रहे हैं, क्योंकि दुनिया भर की आर्थिक गतिविधियां कोविड-19 महामारी और रूस-यूक्रेन संघर्ष होने जैसी बड़ी घटनाओं से उबर रही है। एक तरफ जहां दुनिया अपने पांव जमाने के लिए संघर्ष कर रही है, वहीं दूसरी ओर भारतीय अर्थव्यवस्था नये पायदान पर चढ़ती जा रही है। अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने वैश्विक आर्थिक विकास के मुद्दे पर व्यक्त किये गए अपने नवीनतम अनुमानों में भारत को दुनिया में सबसे तेज गति से बढ़ती हुई प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप में स्वीकार किया है।

वस्तु और सेवाकर संग्रह में भारी बढ़त, पूंजीगत व्यय परिव्यय में वृद्धि और निर्यात में हो रही रिकॉर्ड बढ़ोतरी एक जीवंत तथा आगे बढ़ती हुई भारतीय अर्थव्यवस्था का संकेत है, जो अब कोविड महामारी के प्रकोप से उबर चुकी है।

इसका श्रेय कोविड महामारी के दौरान और उसके उत्तरोत्तर की आर्थिक नीतियों के प्रबंधन के लिए न केवल मोदी सरकार के समग्र दृष्टिकोण को दिया जा सकता है, बल्कि अर्थव्यवस्था को सशक्त करने के उद्देश्य से वर्ष 2014 के बाद लगातार हो रहे प्रयासों को भी दिया जा सकता है। नरेन्द्र मोदी सरकार द्वारा शुरू किए गए संरचनात्मक सुधारों ने भारतीय अर्थव्यवस्था को पहले से बहुत मजबूत किया है और इसे कोविड महामारी के अभूतपूर्व प्रभावों का सामना करने के लिए भी सक्षम बनाया है।

मोदी सरकार ने भारत को विनिर्माण क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से 'आत्मनिर्भर भारत' के साथ-साथ 'मेक इन इंडिया' पहल के तहत कई कार्यक्रम शुरू किए हैं। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (पीएलआई) योजना से इस क्षेत्र को और अधिक प्रोत्साहित किया गया है। उत्पादन से जुड़ी इस प्रोत्साहन योजना को लाने के पीछे का उद्देश्य घरेलू विनिर्माण को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाना और व्यावसायिक गतिविधियों के लिए घरेलू कारोबारियों को तैयार करना है। पीएलआई योजनाओं ने रोजगार के लाखों अवसर सृजित किये हैं और भारतीय अर्थव्यवस्था को विकास के तीव्र पथ पर बनाए रखा है। भारत पहले मोबाइल फोन का एक बड़ा आयातक था, लेकिन अब एक वैश्विक विनिर्माण केंद्र बन चुका है। साल 2014-15 में मोबाइल फोन का उत्पादन लगभग 60 मिलियन होता था, जो बढ़कर वर्ष 2021-22 के दौरान लगभग 310 मिलियन हो गया है।

मोदी सरकार ने सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र को अपनी आर्थिक नीतियों का केंद्र बिंदु बनाया है। कोविड महामारी के दौरान सरकार की आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना ने एक करोड़ से अधिक सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को सहायता प्रदान की थी और उन्हें संभवतः स्थायी रूप से बंद होने से बचाया था। इसके अलावा, एमएसएमई की परिभाषा में संशोधन भी किया गया। श्रम तथा पर्यावरण कानूनों में परिवर्तन जैसे सुधारों ने सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र को अपने कामकाज का विस्तार करने और विकास की दिशा में आगे बढ़ने का मार्ग प्रशस्त किया है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देश के रोजगार उपार्जकों को लगातार नवाचार करने और भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में उनके प्रयासों को हरसंभव सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया है। भारतीय सेमीकंडक्टर मिशन (आईएसएम) के लिए उनके व्यक्तिगत ध्यान व सहयोग तथा भारत में सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम के निर्माण की दृष्टि से परिलक्षित होता है। यह भारत को ऐसी विनिर्माण क्षमताओं वाले कुछ प्रमुख देशों में से एक बना देगा।

भारत, प्रधानमंत्री मोदी के गतिशील नेतृत्व में वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान 83.57 अरब अमरीकी डॉलर का अपना उच्चतम वार्षिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रवाह प्राप्त करने के साथ ही एक पसंदीदा निवेश स्थल के रूप में उभर कर सामने आया है। मोदी सरकार ने भारतीय निर्यात को बढ़ावा देने के साथ-साथ साल 2030 तक भारतीय उत्पादों एवं सेवाओं के निर्यात को 42 ट्रिलियन तक ले जाने के लिए एक नई विदेश व्यापार नीति की भी घोषणा की है।

भारतीय अर्थव्यवस्था में पिछले नौ वर्षों के दौरान एक उल्लेखनीय परिवर्तन देखा गया है और इसका प्रभाव समाज के विभिन्न वर्गों के भीतर स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है।

* * *

मुख्य बातें

भारत 2023 में दुनिया की **तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था** बना

2021 में **ग्लोबल रीयल-टाइम डिजिटल पेमेंट** का **40%** हिस्सा भारत का

कोविड के दौरान भारत की अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए **27.1 लाख करोड़ रुपये** का **आत्मनिर्भर भारत पैकेज**

अक्टूबर 2021 में **सेवा पीएमआई** **दस साल के उच्च स्तर 58.4 पर पहुंच गया**

अप्रैल, 2023 में **1.87 लाख करोड़ रुपये** के साथ **मासिक जीएसटी संग्रह** अब तक के सबसे ऊंचे स्तर पर

वित्त वर्ष 2022-23 में गुड्स और सर्विसेज एक्सपोर्ट रिकॉर्ड **$770.18 बिलियन**

ECLGS के तहत MSMEs के लिए **3.63 लाख करोड़ रुपये** से अधिक स्वीकृत

अगले 5 वर्षों में **60 लाख अतिरिक्त रोजगार** पैदा करने के लिए **पीएलआई योजनाएं**

वित्त वर्ष 2022-23 में इलेक्ट्रॉनिक सामानों के निर्यात में **50%** की वृद्धि **$23.57 बिलियन** पर दर्ज की गई

6.60 लाख करोड़ रुपये से अधिक के **फंसे कर्ज की वसूली**

वित्त वर्ष 2021-22 में **$84.8 बिलियन** का अब तक का सबसे अधिक **वार्षिक एफडीआई इनफ्लो**

भारत अब **100+ यूनिकॉर्न** से संपन्न

उपलब्धियां

विश्व की सबसे तेज गति से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था-क्यों यह वृद्धि मात्र संख्या ही नहीं है

- दुनियाभर में इस बात को लेकर सहमति है कि भारत **विश्व की सबसे तेज गति से बढ़ने वाली** प्रमुख अर्थव्यवस्था बनी रहेगी
- High growth से सरकार के पास **बड़ी मात्रा में संसाधन** उपलब्ध होंगे, इनसे कल्याणकारी और ढांचागत योजनाओं को आगे बढ़ाया जा सकेगा।
- High growth से **नए रोजगार** के अवसर सृजित होंगे
- नए अवसरों से आय में निरंतर वृद्धि होगी और **Growth के Benefits** समाज के हर वर्ग को मिलेंगे।

विपदा को अवसर में बदलता आत्मनिर्भर भारत

- महामारी के प्रारंभ से ही प्रधानमंत्री मोदी के ठोस आर्थिक प्रबंधन ने **आपदा को अवसर में बदल दिया**।
- सभी आर्थिक संकेतक भारत के Economic Resurgence की ओर इशारा कर रहे हैं
- MSMEs से MNCs तक सभी कंपनियों के उत्पादन में विस्तार हो रहा है। इसने **Services, Manufacturing और Exports सेक्टर में ऐतिहासिक योगदान** दिया है।
- कई क्षेत्रों में Hiring Sentiment अपने सबसे उच्च स्तर पर है। इससे **Growth का Jobs में परिवर्तित होना सुनिश्चित** हुआ है।

Conviction और Consensus से सुधार

- पीएम मोदी ने कठिन समय में व्यक्तिगत रूप से संरचनात्मक सुधारों को आगे बढ़ाते हुए **Conviction और Consensus** से सुधारों की एक नई प्रवृत्ति शुरू की है।
- प्रधानमंत्री मोदी ने इस कठिन दौर में भी कई **Structural Reforms के लिए राजनीति को आड़े नहीं आने दिया**।
- Cooperative Federalism का मतलब है **केन्द्र का राज्यों को Voluntarily Reforms के लिए प्रोत्साहित करना**।
- सुधारों ने सभी stakeholders के हितों को सुरक्षित किया

बेहतर अर्थव्यवस्था का निर्माण

- उत्पाद और सेवा शुल्क के आने से **Formalisation का विस्तार** हुआ।
- सरकार की सख्त कार्रवाई से **NPAs और आर्थिक अपराधों में तेजी से कमी** आई।
- IBC ने भारतीय बैंकिंग और कॉरपोरेट क्षेत्रों को मुश्किलों से उबारा।
- भारत तेजी से 'Digital Economy' में बदल रहा है।

* * *

'ग्रोथेड' के लिए आधार तैयार

- आईपीओ के माध्यम से 2013-14 में 1,205 करोड़ रु. से बढ़कर 2021-23 में 1.60 लाख करोड़ रुपये से अधिक का रिकॉर्ड संसाधन
- नेशनल हाइवे का विस्तार 2014 में 91,287 किमी से बढ़कर 2022-23 में 1,45,155 किमी हो गया
- ऑपरेशनल हवाई अड्डों की संख्या 2014 में 74 से बढ़कर 2023 में 148 हो गई
- नई निर्माण इकाइयों के लिए 2024 तक 15% टैक्स रेट रखने और स्टार्ट-अप के लिए एक साल का कर प्रोत्साहन भविष्य में रोजगार पैदा करने वाले क्षेत्रों को बढ़ावा देगा
- अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) का सकल गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (जीइनपीए) अनुपात सितम्बर 2022 में छह साल के निचले स्तर 5% पर आ गया
- 2021 में एक दशक के बाद कीमतों और मात्रा में वृद्धि के साथ हाउसिंग अप-साइकल देखा गया जो लगातार जारी है

सरकार के बड़े काम

भारत दुनिया की पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना

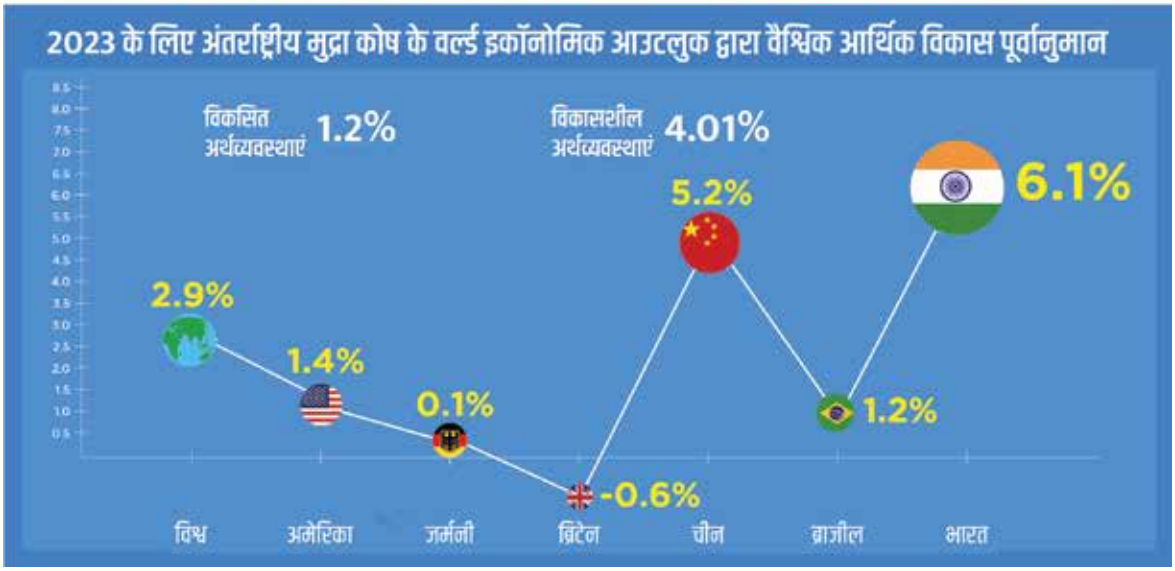

एक आधुनिक अर्थव्यवस्था के लिये व्यापक सुधार
पूर्वप्रभावी कराधान की समाप्ति
वस्तु और सेवा कर लागू किया जाना
वाणिज्यिक कोयला खनन
कॉरपोरेट टैक्स में कमी
भारत के एफडीआई नियमों को दुरुस्त करना
दिवाला और दिवालियापन संहिता
श्रम सुधार कानून
रणनीतिक विनिवेश और परिसंपत्ति मौद्रिकरण
अंतरिक्ष और परमाणु सेक्टर में निजी निवेश की अनुमति

नया भारत
निर्यात रिकॉर्ड को तोड़ता विनिर्माण पावरहाउस
पीएलआई स्कीम से विनिर्माण को बढ़ावा
14 सेक्टरों में उद्योगों को 1.97 लाख करोड़ रुपये मूल्य के प्रोत्साहन उपलब्ध कराये गये।
2.34 लाख करोड़ रुपये का निवेश और रोजगार के लाखों अवसर सृजित हुए।
विनिर्माण से निर्यात को बढ़ावा
2022-23 में पहली बार वस्तुओं का निर्यात 447 अरब डॉलर से अधिक
वित्त वर्ष 2022-2023 में 2021-22 के मुकाबले इंजीनियरिंग वस्तुओं के निर्यात में 50 प्रतिशत की बढ़ोतरी

क्या आप जानते हैं ?
2000 से दिसंबर 2022 तक 23 वित्तीय वर्षों में FDI के रूप में
भारत ने आकर्षित किया
$902 बिलियन का निवेश
इन 23 वर्षों में
9 साल
मोदी सरकार के (2014-23)
कुल FDI का 64 प्रतिशत निवेश हासिल हुआ
$578 बिलियन !

इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम से एमएसएमई सेक्टर को संरक्षण

- एमएसएमई को ऋण उपलब्ध कराकर 1.8 लाख करोड़ रुपये का एमएसएमई ऋण डूबने से बचाया जा सका।
- इससे 1.5 करोड़ रोजगारों की रक्षा हुई।
- यदि प्रत्येक रोजगार से 4 लोगों का परिवार जुड़ा माना जाये तो 6 करोड़ लोगों की आजीविका बचायी जा सकी।

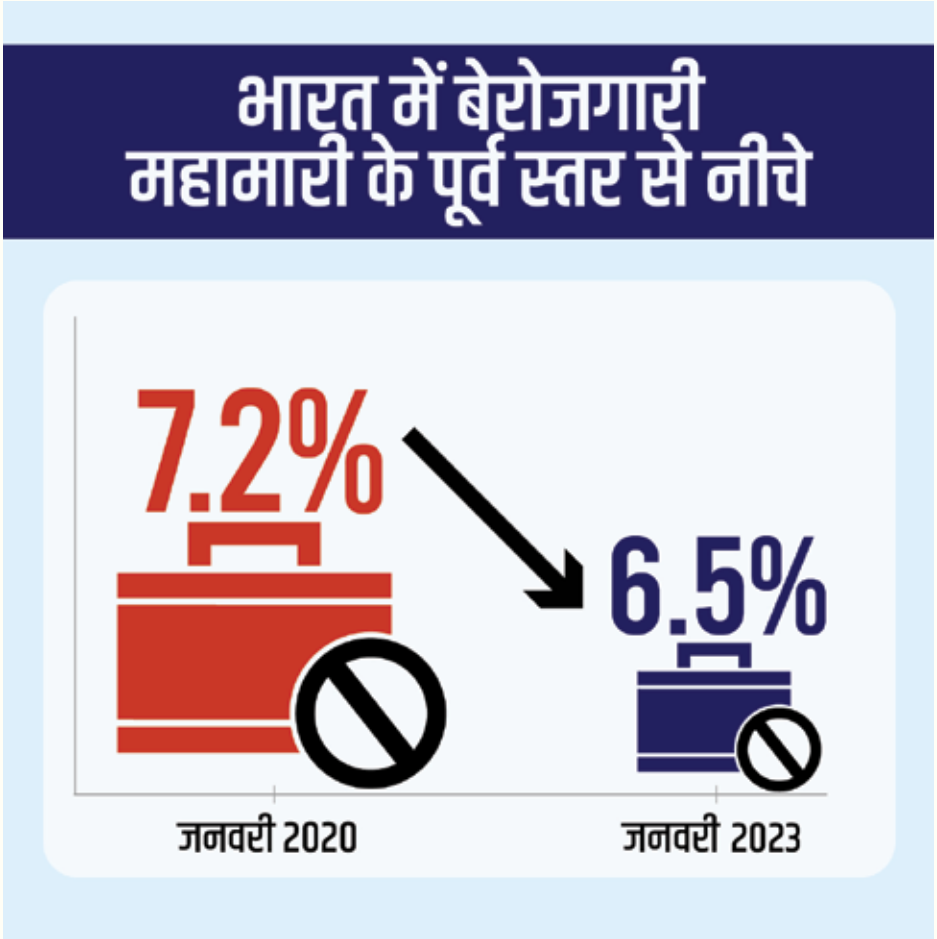

“

एक समय था जब कहा जाता था - Why India. अब जो Reforms देश में हुए हैं, उनका जो प्रभाव दिखा है, उसके बाद कहा जा रहा है- 'Why not India'

-नरेन्द्र मोदी

”

ईज ऑफ़ डूइंग बिज़नेस से कारोबार को लगे पंख

9

सारांश

आज दुनिया भारत को निवेश के लिए एक बेहद आकर्षक स्थान के रूप में देख रही है और वैश्विक कंपनियां यहां अपना व्यवसाय स्थापित करना चाहती हैं। भारत में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ाने के लिए परिवर्तनकारी व्यवस्था और आर्थिक सुधारों के लिए प्रधानमंत्री मोदी के प्रयासों की सराहना की जा रही है। इससे मौजूदा और साथ ही नए व्यवसायों और उद्यमियों को भारत में निवेश करने और व्यवसाय स्थापित करने में मदद मिली है। देश के कारोबारी माहौल में सुधार का सबसे बड़ा उदाहरण यहां के स्टार्टअप्स में देखा जा सकता है। 2014 से पहले, भारत में लगभग 350 स्टार्टअप थे। पिछले नौ वर्षों में, स्टार्टअप इंडिया जैसी योजनाओं से प्रोत्साहित होकर, स्टार्टअप्स की संख्या में 260 गुना वृद्धि हुई है। इसके अलावा, देश में आज 100 से अधिक यूनिकॉर्न भी हैं।

2014 के बाद से, किराए की मांग और लालफीताशाही की जगह रेड कार्पेट ने ले ली है। सरकार जोखिम उठाने वाले कारोबारियों के मार्ग में बाधक नहीं है, बल्कि सक्रियता के साथ उन्हे बल प्रदान कर रही है। भारत में उद्यमी और निवेशक अब व्यापार के अनुकूल माहौल और एक ऐसी सरकार से खुश हैं जो सक्रिय रूप से उनकी चिंताओं को दूर और शिकायतों का निवारण करती है। यह अभूतपूर्व बदलाव रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स व्यवस्था और एंजल टैक्स को हटाने के साथ-साथ कॉर्पोरेट टैक्स को कम करने जैसे ऐतिहासिक निर्णयों के माध्यम से संभव हुआ है। नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम से अब व्यवसाय से जुड़ी सभी तरह की स्वीकृतियां एक जगह पर प्राप्त हो रही हैं। इसके अलावा, मोदी सरकार ने 1,500 से अधिक पुरातन कानूनों और हजारों अनुपालनों को निरस्त करके अनावश्यक अनुपालन बोझ को कम किया है। इससे भारतीय उद्यमों के लिए अनावश्यक लागत और बाधाएँ पैदा होती थीं।

पारदर्शिता और अनुपालन आवश्यकताओं को कम करने का प्रधानमंत्री का मंत्र एक ऐसी सरकार को प्रदर्शित करता है जो अपने नागरिकों पर भरोसा करती है। करदाताओं की बढ़ती संख्या और रिकॉर्ड टैक्स कलेक्शन में इस भरोसा साफ दिखता है। इसी तरह, टैक्स कलेक्शन की प्रक्रिया में सेल्फ-रेग्यूलेश, सेल्फ-सर्टिफिकेशन, कम्प्यूटर आधारित रैंडम लेबर इंस्पेक्शन और फेसलेस असेसमेंट को बढ़ावा देने से न केवल 'इंस्पेक्टर राज' की कमर टूटी है, बल्कि अनुपालन में भी सुधार हुआ है।

ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सुधार के लिए भारत के प्रयासों को वैश्विक स्तर पर स्वीकार किया जा रहा है। यह विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग में लगातार हो रहे सुधार से स्पष्ट है। उदाहरण के लिए, विश्व बैंक के ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में देश की रैंकिंग 2014 में 142 से बढ़कर 2019 में 63 हो गई है।

विश्व बैंक के लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स (एलपीआई) 2023 में भारत छह स्थानों की छलांग लगाकर अब 139 देशों के सूचकांक में 38वें स्थान पर है।

यह भारत की वैश्विक स्थिति का एक मजबूत संकेतक है। भारत सरकार के प्रयासों का ही नतीजा है कि विकास को पीएम गति शक्ति और नई नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी आदि पहलों के माध्यम से लॉजिस्टिक से जुड़े बुनियादी ढांचे में सुधार से और मजबूत किया जा रहा है।

एमएसएमई और छोटे व्यवसायों के लिए अधिक पारदर्शिता और सभी को समान सुविधाओं पर जोर का उदाहरण जीईएम पोर्टल की सफलता के रूप में देखा जा सकता है जिसके माध्यम से सरकार ने 4 लाख करोड़ रुपये की खरीदारी की है।

कई सुधारों और ऐतिहासिक फैसलों के अलावा, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मानसिकता परिवर्तन का भी सफलतापूर्वक नेतृत्व किया है। पिछली सरकारों के विपरीत, मोदी सरकार न केवल उद्यमियों को धन सृजक मानती है बल्कि उन्हें राष्ट्रीय विकास में भागीदार भी मानती है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सुधार के ठोस प्रयासों से वेल्थ क्रिएटर्स के पूल में ऐतिहासिक विस्तार हुआ है। इसका बड़े पैमाने पर देश के जमीनी स्तर तक सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जैसे सुधारों से कल्याण और विकास कार्यक्रमों के लिए सरकार के पास उपलब्ध संसाधनों में वृद्धि हुई है, साथ ही साथ देश को रोजगार सृजन और उच्च आय प्राप्त करने में भी सक्षम बनाया है।

* * *

मुख्य बातें

ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग 2014 में 142 से बढ़कर 2020 में 63,

79 रैंक की जबरदस्त छलांग

1.67 लाख

नई कंपनियां पंजीकृत - एक वित्तीय वर्ष में अब तक का सबसे अधिक

श्रम कल्याण को बढ़ावा देने के लिए

4 नए

श्रम कोड

पूर्वव्यापी प्रभाव वाले टैक्स समाप्त

एंजेल टैक्स

खत्म

नई घरेलू मैनुफैक्चरिंग कंपनियों के लिए

कॉर्पोरेट टैक्स

25% से घटाकर 15% किया

कंपनी एक्ट के तहत

81 में से 16

अपराध गैर-अपराधकृत घोषित

39,556

अनावश्यक स्वीकृतियां समाप्त

1,500

से अधिक पुराने कानून निरस्त

कारोबार शुरू करने के लिए ज़रूरी **स्वीकृतियों की संख्या** 14 से घटाकर

सिर्फ 3

हुईं

पिछले सात वर्षों में पेटेंट पंजीकरण में

50% की रिकॉर्ड बढ़ोत्तरी

नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम ने

आसान अनुपालन सुनिश्चित किया

उपलब्धियां

Painless, Faceless और Seamless Tax System

- कर की दरें अब कष्टदायक नहीं रही हैं। भारत में आज Domestic Manufacturing Companies के लिए **सबसे कम 15 प्रतिशत Corporate Tax Rates**.
- मौजूदा कंपनियों के लिए सरकार ने **Corporate Tax Rates को 30 प्रतिशत से घटाकर 22 प्रतिशत किया**।
- Retrospective Tax ने वैश्विक निवेशकों के बीच भारत की छवि को खराब किया। इस **Retrospective Tax को अब समाप्त कर दिया गया है**।
- **Angel Tax को भी अब खत्म कर दिया गया है**। इससे स्टार्ट-अप्स को बढ़ावा मिलता है।
- अधिकांश Tax processing और Assessments ऑनलाइन हो रहे हैं। जो Returns Filing , Assessments, Appeals और Refunds को **Seamless और Quick बनाते हैं**।
- **Faceless Assessment और Appeals** ने उत्पीड़न की संभावना को खत्म और इंस्पेक्टर राज को कम किया है।

Red-Tapism से Red Carpet तक

- विभिन्न आर्थिक सुधारों और प्रोत्साहनों ने भारत को **निवेश के लिए सबसे पसंदीदा** Destination बनाया है।
- **Single window system के माध्यम से** Approvals और Clearances मिल रही हैं, इससे बाधाएं कम हुई हैं।
- कंपनी के Incorporation के लिए आवश्यक दस्तावेजों की संख्या में कमी हुई है।
- कई क्षेत्रों में **FDI नियमों को उदार बनाया है**। यही वजह है कि पिछले कुछ वर्षों में FDI ने सभी रिकार्ड तोड़े हैं।

Industry और Entrepreneurs पर भरोसा

- **Growth Ambassadors of India** यानि हमारे Entrepreneurs नौकरियों का सृजन कर भारत की Growth Story को ताकत दे रहे हैं।
- भरोसे वाली सोच का निर्माण हो रहा है, जिसमें सरकार और नागरिक एक दूसरे पर भरोसा करते हैं।
- **Self-Regulation और Self-Compliance आम हो चले हैं**।
- **इंस्पेक्टर राज के अंत**, labour Inspection में Reforms और पर्यावरण कानून में सुधारों से Rent Seeking और Corruption पर लगाम लगी है।

* * *

क्या आप जानते हैं?

- पीएम मोदी ने जरूरी स्वीकृतियों की संख्या को 14 से घटाकर सिर्फ 3 करके कारोबार शुरू करना आसान बना दिया
- 2014 के बाद से, पीएम मोदी ने 1,500 से अधिक निरर्थक या पुराने केंद्रीय कानूनों को निरस्त कर दिया
- भारत की फिनटेक अपनाने की दर (87%) वैश्विक औसत (64%) से अधिक है, जो इसे दुनिया के सबसे बड़े डिजिटल बाजारों में से एक बनाती है
- वित्त वर्ष 2022-23 में भारत का माल निर्यात 448 अरब डॉलर के रिकॉर्ड स्तर तक पहुंच गया, जो कि पाकिस्तान की संपूर्ण जीडीपी ($350 बिलियन) से अधिक है
- 2014 के बाद से इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण में 300% की वृद्धि हुई है
- अमेरिका और चीन के बाद भारत दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है
- निर्माण परमिट प्राप्त करने के लिए विश्व बैंक की रैंकिंग में भारत का स्थान 2018 में 181 से बढ़कर 2020 में 27 हो गया
- पेटेंट देने की संख्या 2015-16 में 6,326 से बढ़कर 2022-23 में 34,153 हुई

सरकार के बड़े काम

विकास का चक्र –
व्यापार करने में आसानी
कैसे मदद करती है
व्यवसाय करने में आसानी
निवेश प्रवाह होता है
उद्यम बढ़ता है
नौकरियां बढ़ती हैं
आय बढ़ती है
खपत बढ़ती है
खपत से व्यवसाय बढ़ता है
आय में वृद्धि का प्रसार होता है
कर संग्रहण बढ़ता है
कर की दरें कम होती हैं

हर कदम पर आसानी

व्यवसाय शुरू करने में आसानी:

कंपनी के निगमन के लिए आवश्यक कदमों की संख्या 2014 में 14 से घटकर 2022 में 3 हो गई।

अनुपालना में आसानी:

राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली सभी आवश्यक अनुमोदनों की पहचान करने और उन्हें प्राप्त करने के लिए एक एकल मंच प्रदान करती है।

बाहर निकलने में आसानी:

दिवाला और दिवालियापन संहिता कंपनियों के आसान अवसान की अनुमति देती है।

बौद्धिक संपदा की रक्षा करना आसान

पेटेंट, ट्रेडमार्क और कॉपीराइट प्राप्त करना बहुत आसान हो गया है

- फाइलिंग फीस में कमी।
- ई-फाइलिंग की शुरुआत।
- प्रक्रिया को सरल बनाना और जारी करने के समय को कम करना।

इज ऑफ़ डूइंग बिज़नेस

तब	अब
इज ऑफ़ डूइंग बिज़नेस इंडेक्स	इज ऑफ़ डूइंग बिज़नेस इंडेक्स
142	63
लॉजिस्टिक परफ़ॉर्मेंस इंडेक्स	लॉजिस्टिक परफ़ॉर्मेंस इंडेक्स
54	38
	क्रमशः वर्ष 2020 और 2023 के लिए

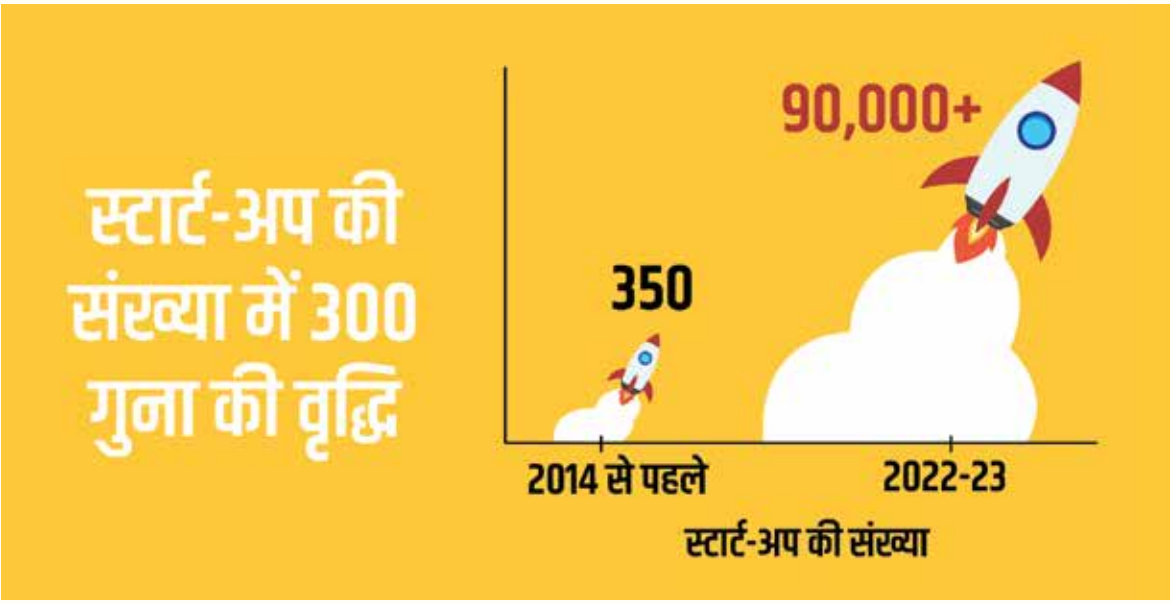
स्टार्ट-अप की संख्या में 300 गुना की वृद्धि
90,000+
350
2014 से पहले
2022-23
स्टार्ट-अप की संख्या

यूनिकॉर्न में जबरदस्त बढ़ोतरी
4
100+
2014 में
2023 में
भारत में यूनिकॉर्न की संख्या

नवोन्मेषी भारत
वैश्विक नवाचार सूचकांक रैंकिंग
2022
40
2015
81
स्वीकृत पेटेंट की संख्या
6,326
30,074
2015-16
2021-22

जब ऐसी आधुनिक सड़कें बनती हैं, आधुनिक रेलवे स्टेशन, रेलवे ट्रैक, मेट्रो, एयरपोर्ट बनते हैं, तो देश की प्रगति को गति मिलती है।

-नरेन्द्र मोदी

इंफ्रास्ट्रक्चर- तेज़ी से हो रहा बेहतर

10

सारांश

किसी देश की आर्थिक प्रगति को आकार देने में उसके बुनियादी ढांचे की गुणवत्ता की एक अहम भूमिका होती है। हमारे देश के एक वैश्विक आर्थिक महाशक्ति बनने की प्रक्रिया में गुणवत्तापूर्ण बुनियादी ढांचा एक महत्वपूर्ण मूलभूत तत्व है। इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए, श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने बुनियादी ढांचे को अपने विकास के एजेंडे में सबसे ऊपर व केन्द्र में रखा है।

अतीत में, बुनियादी ढांचे से जुड़ी परियोजनाओं को अत्यधिक देरी का सामना करना पड़ता था। लेकिन पिछले नौ वर्षों के दौरान, बड़ी सोच और बिना किसी देरी के काम को पूरा करना देश में बुनियादी ढांचे के विकास की पहचान रही है। प्रधानमंत्री ने नियमित रूप से प्रगति प्लेटफॉर्म के जरिए परियोजनाओं की प्रगति की निगरानी की है, जिसके कारण बुनियादी ढांचे की विभिन्न विलंबित व नई घोषित परियोजनाओं को सफलतापूर्वक पूरा किया गया है।

अंतिम छोर तक कनेक्टिविटी की सुविधा पहुंचाने के लक्ष्य के अनुरूप, राजमार्ग निर्माण का दैनिक औसत अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है और यह 2014 के पूर्व के स्तरों की तुलना में लगातार अधिक बना हुआ है। इसी तरह, ग्रामीण सड़कों के निर्माण में हुई तेज वृद्धि ने दूरदराज के इलाकों में सड़क तक पहुंच को लगभग सर्वसुलभ बना दिया है। भारतीय रेल ने भी पिछले नौ वर्षों के दौरान रेलवे लाइनों के दोहरीकरण और रेलवे पटरियों के विद्युतीकरण के जरिए बड़े पैमाने पर अपनी क्षमता का विस्तार किया है। भारत की पहली स्वदेशी सेमी हाई-स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस 'मेक इन इंडिया' की सफलता की कहानी कहती है।

जहां तक हवाई यात्रा का प्रश्न है, मोदी सरकार द्वारा उठाए गए विभिन्न कदमों ने इसे सस्ता और सुलभ बना दिया है। पिछले नौ वर्षों के दौरान, 74 हवाई अड्डों का निर्माण करके वहां आवागमन शुरू किया गया है। इसके अलावा, 58 हवाई अड्डे, 8 हेलीपोर्ट और 2 वाटर एयरोड्रोम सहित 68 कम आवागमन वाले / हवाई सेवा की सुविधा से वंचित स्थलों को उड़ान योजना के तहत जोड़ा गया है।

हवाई अड्डों की तरह, मेट्रो रेल भी अब बड़े शहरों तक सीमित नहीं रह गई है। पिछले नौ वर्षों के दौरान मेट्रो रेल परियोजनाएं 20 शहरों तक पहुंच चुकी हैं।

ढांचागत जुड़ाव को और बढ़ाने तथा नागरिकों के लिए लागत को कम करने हेतु हाल ही में शुरू की गई राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति का उद्देश्य लॉजिस्टिक्स संबंधी लागत को कम करना, अंतरराष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देना, हमारे स्टार्टअप, व्यवसायों एवं किसानों को नए अवसर उपलब्ध कराना और देश में समृद्धि लाना है।

किसी देश के ढांचागत विकास को मजबूत वित्तीय प्रतिबद्धताओं द्वारा समर्थित होना चाहिए। इसी के अनुरूप, प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान (एनएमपी) की घोषणा की थी। यह मास्टर प्लान संबंधित मंत्रालयों/विभागों के बीच एकीकृत एवं समग्र योजना निर्माण की दिशा में एक परिवर्तनकारी दृष्टिकोण है ताकि मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी एवं लॉजिस्टिक्स संबंधी दक्षता को बेहतर बनाया जा सके और व्यवधानों को कम करने व परियोजनाओं को समय पर पूरा करने पर ध्यान देकर लोगों और सामानों की निर्बाध आवाजाही हेतु महत्वपूर्ण ढांचागत अंतराल को पाटा जा सके। आजाद भारत के इतिहास में बुनियादी ढांचे के विकास की यह सबसे व्यापक योजना है, क्योंकि सरकार आने वाले वर्षों में लगभग 100 लाख करोड़ रुपये निवेश करने की योजना बना रही है।

बुनियादी ढांचे के विकास का प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का दृष्टिकोण भारत के आर्थिक विकास को नई उंचाइयों पर ले जाने में मदद करेगा। यह नागरिकों के जीवनयापन को आसान बनाएगा, रोजगार सृजन में बढ़ोतरी करेगा और समावेशी विकास सुनिश्चित करने हेतु अंतिम छोर तक कनेक्टिविटी स्थापित करेगा।

* * *

मुख्य बातें

2014 से रोड ट्रांसपोर्ट और हाइवे बजट आवंटन में
500%
की वृद्धि

400
विश्व स्तरीय **वंदे भारत ट्रेनों** से सुविधाजनक होगी यात्रा
17 ट्रेनों का संचालन शुरू

हाइवे निर्माण की गति
37 किमी/दिन
तक पहुंची

99%
ग्रामीण सड़क संपर्क

34 महीने
में एक भी रेल यात्री की मौत नहीं

मेट्रो का विस्तार
2014 में 248 किमी से बढ़कर 2023 में
860 किमी हुआ

पीएम गति शक्ति
मास्टरप्लान के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए

प्रगति बैठकों
के माध्यम से पीएम मोदी ने 311 से अधिक परियोजनाओं की समीक्षा की

2014 से
74 हवाई अड्डों
का संचालन

अमृत
के तहत शहरी विकास के लिए 4832 परियोजनाएं संपन्न

2014 से बनी
3.28 लाख किलोमीटर
ग्रामीण सड़कें

राष्ट्रीय जलमार्ग
अधिनियम, 2016 के तहत
111 जलमार्गों
को राष्ट्रीय जलमार्ग (एनडब्ल्यू) घोषित किया गया

उपलब्धियां

Delays से तेज Delivery तक

- **दशकों से रुके** महत्वपूर्ण Infrastructure Projects हो रहे पूरे।
- **पीएम मोदी ने व्यक्तिगत रूप से** PAGATI Platform के माध्यम से इनकी निगरानी की।
- सरकार ने सुनिश्चित किया कि महामारी के प्रभाव से Infrastructure Projects को पूरा करने में देरी न हो।

नए भारत के लिए New Infrastructure का रिकॉर्ड

- हर साल **सबसे तेज हाइवे निर्माण** का रिकॉर्ड - 2020-21 में रोजाना 37 किलोमीटर
- **सबसे तेज सड़क निर्माण** का रिकॉर्ड
  - 24 घंटे में 4 लेन वाली 2.5 किलोमीटर कंक्रीट की सड़क बनी
  - 24 घंटे में 1 लेन वाली 25 किलोमीटर बिटुमेन सोलापुर-बीजापुर सड़क का निर्माण
- दुनिया की **सबसे ऊंची प्रतिमा** - स्टैच्यू ऑफ यूनिटी
- दुनिया का **सबसे ऊंचा बन रहा रेलवे पुल** - चिनाब पुल
- 10 हजार फीट से ऊपर विश्व की **सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग** - अटल टनल

गतिशक्ति के साथ Infrastructure का तेज विकास

- पीएम गतिशक्ति मास्टरप्लान से भारत के Infrastructure की जरूरतों के लिए **दीर्घकालिक योजनाएं**।
- Integrated Platform के माध्यम से 100 लाख करोड़ रुपये के **फंड का समुचित उपयोग** सुनिश्चित।
- पूरे भारत में **अंतिम छोर तक** Connectivity और Multi-Model Connectivity में सुधार।
- Infrastructure के निर्माण से **बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन**।

* * *

क्या आप जानते हैं?

- पीएम गति शक्ति सिंगल एकीकृत पोर्टल के माध्यम से सभी योजनाओं और विभागों के भीतरी तालमेल को संस्थागत रूप दे रही है
- केंद्र सरकार के 35 विभागों को जोड़कर एकीकृत पोर्टल चल रहे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को दृश्यता प्रदान करेगा और विभिन्न हितधारकों के बीच बातचीत की सुविधा प्रदान करेगा
- गति शक्ति सभी हितधारकों के बीच बेहतर तालमेल और विभिन्न परियोजनाओं की रीयल-टाइम ट्रैकिंग सुनिश्चित करेगी
- पीएम गति शक्ति से परियोजनाओं की बेहतर कार्य योजना, भारी लागत से बचत और परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने में मदद मिलेगी
- सरकार अगले तीन वर्षों में मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक सुविधाओं के लिए 100 PM गति शक्ति कार्गो टर्मिनल विकसित करेगी

सरकार के बड़े काम

लंबित परियोजनाएं हुईं पूरी

उत्तर प्रदेश में सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना
स्वीकृति का वर्ष:1978
4 दशकों की देरी
मोदी युग में पूरी

बिहार में कोसी रेल महासेतु
स्वीकृति का वर्ष: 2003-04
2 दशकों की देरी
मोदी युग में तैयार

केरल में कोल्लम बाईपास परियोजना
स्वीकृति का वर्ष-1975
लगभग 50 वर्षों से विलंबित
मोदी युग में पूरी

ब्रह्मपुत्र पर बोगीबील रेल-सह-सड़क पुल
स्वीकृति का वर्ष- 1997
2 दशकों की देरी
मोदी युग में बनाया गया

अटल सुरंग- 10,000 फीट की सबसे लंबी सुरंग
स्वीकृति का वर्ष- 2000
2 दशकों की देरी
मोदी युग में तैयार

दिल्ली के आस-पास ईस्टर्न और वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे
स्वीकृति का वर्ष- 2006
एक दशक की देरी
मोदी युग में परियोजना पूरी

रेलवे ने भारत को विकास की राह पर लाकर खड़ा किया
2022-23 में:
माल ढुलाई में रिकॉर्ड
1400 मीट्रिक टन से पार
रिकॉर्ड 6500 किलोमीटर मार्ग
का विद्युतीकरण
2,400 किलोमीटर के लक्ष्य की तुलना में
4756 किलोमीटर की नई लाइन/दोहरी/गेज
निर्माण व परिवर्तन शामिल किया गया
विद्युत लोको

क्या आप जानते हैं?
मार्च 2019 से लगातार 34 महीनों में किसी भी रेल यात्री की मौत नहीं हुई और
2,000 किलोमीटर रेलवे नेटवर्क को कवच के तहत लाया जाएगा, जो ट्रेन की टक्कर
को रोकने के लिए स्वदेशी रूप से विकसित तकनीक है।

भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों और
ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का विकास
1,45,155
कि.मी.
91,287
कि.मी.
59%
1 अप्रैल, 2014
वर्तमान में
पिछले 9 वर्षों (2014-23) में, भारत ने अपने राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क में
53,868+ किलोमीटर का विस्तार
किया है

भारत वाणिज्य और लॉजिस्टिक्स के लिए एक केंद्र बनने की राह पर
देश
टर्न अराउंड टाइम
दिन
भारत 0.9
सिंगापुर 1.0
मलेशिया 1.0
न्यूजीलैंड 1.1
इंडोनेशिया 1.1
यू ए ई 1.1
आयरलैंड 1.2
जर्मनी 1.3
बेल्जियम 1.3
यू एस ए 1.5
ऑस्ट्रेलिया 1.7
रूस 1.8
कनाडा 2.0
साउथ अफ्रीका 2.8

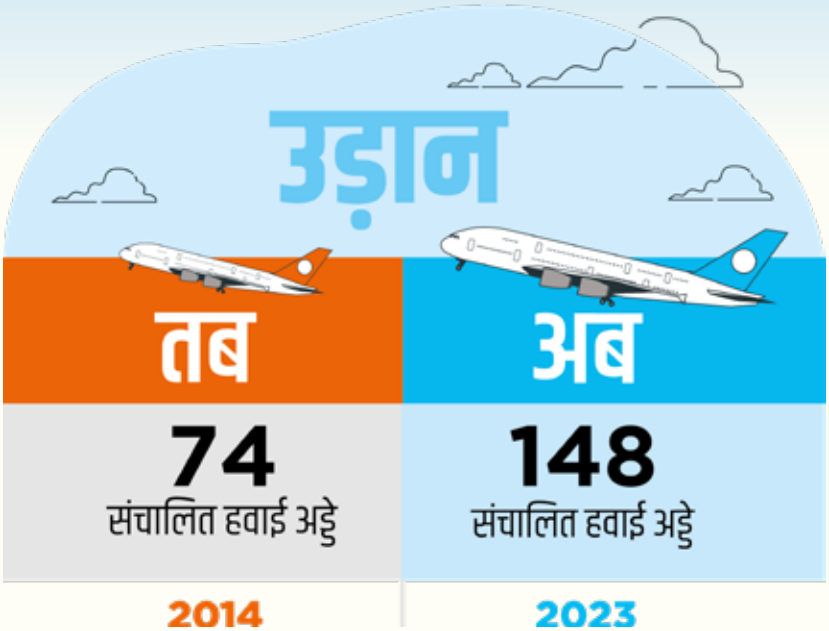
उड़ान
तब
74
संचालित हवाई अड्डे
2014
अब
148
संचालित हवाई अड्डे
2023

‘गोल्डन ज्वाइंट’ का कार्य पूरा

विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल, जम्मू-कश्मीर का चिनाब ब्रिज

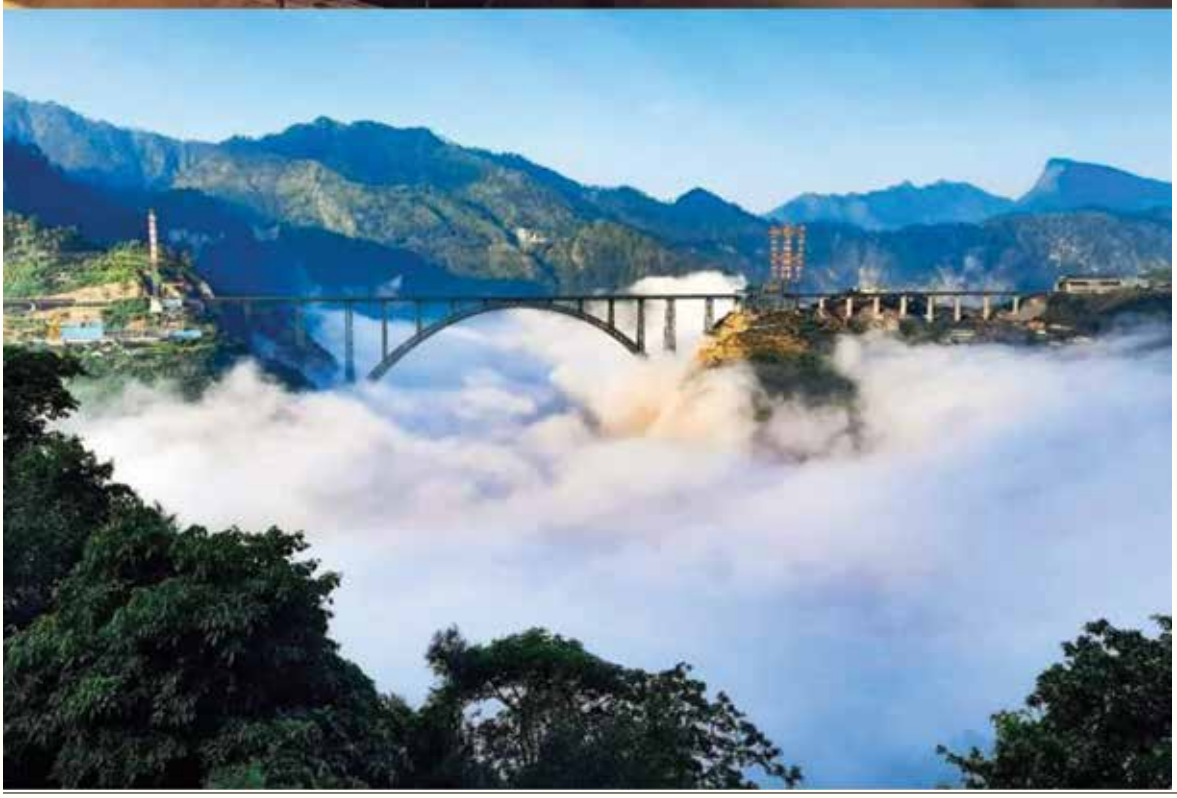

‘डेक क्लोज़र’ समारोह 13 अगस्त 2022 को संपन्न

चिनाब ब्रिज नदी तल से 359 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, यानी यह पुल पेरिस के एफिल टावर से भी ऊंचा है!

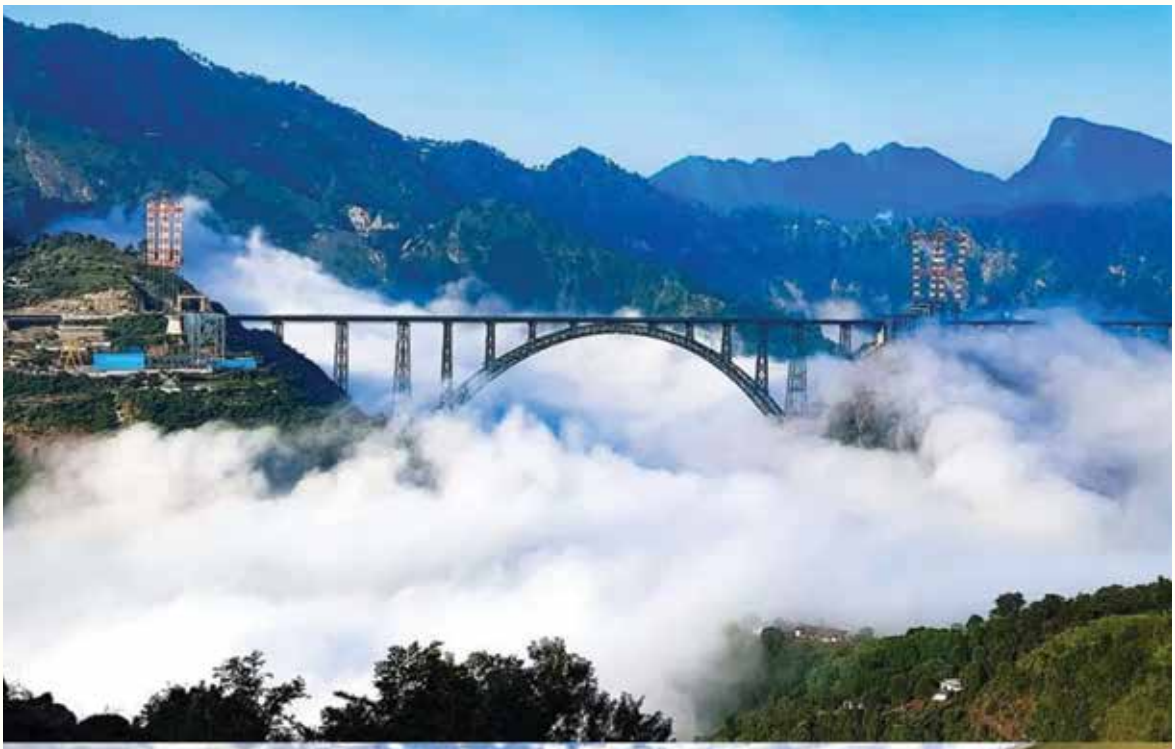

“

हम भारत में आधुनिक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रहे हैं, साथ ही यह भी सुनिश्चित कर रहे हैं कि डिजिटल क्रांति का फायदा समाज के हर वर्ग तक पहुंचे।

- नरेन्द्र मोदी

”

टेक्नोलॉजी से भारत को नई शक्ति

11

सारांश

मोदी सरकार ने समावेशी विकास और सहज जीवन (ईज ऑफ लिविंग) को बढ़ावा देने के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग के प्रति अटूट प्रतिबद्धता दिखाई है। टेक्नोलॉजी की पहुंच सुनिश्चित करने और सरकारी कामकाज (गवर्नेंस) में तेजी से डिजिटलीकरण लाने के लिए सरकार काफी तेजी से काम कर रही है।

देश में डिजिटल भुगतान को लोकप्रिय रूप से अपनाने में उल्लेखनीय सफलता की कहानी जगजाहिर है। जनवरी, 2023 में, यूनाइटेड पेमेंट इंटरफेस पर 200 बिलियन डॉलर (लगभग 2 लाख करोड़ रुपये) के लगभग 8 बिलियन (800 करोड़) लेनदेन किए गए। भारत की डिजिटल भुगतान प्रणाली विश्व स्तर पर विभिन्न देशों से जुड़ी हुई है। आधार ई-केवाईसी सेवाएं भी पारदर्शी और बेहतर ग्राहक अनुभव प्रदान करके और व्यापार करने में आसानी (ईज ऑफ डूइंग बिज़नेस) में मदद करके बैंकिंग और गैर-बैंकिंग वित्तीय सेवाओं के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। भारत में आज फिनटेक अपनाने की दर दुनिया में सबसे अधिक है।

पिछले नौ वर्षों में, पूरे भारत में मोबाइल स्वामित्व में जबर्दस्त तेजी हुई है। डेटा की लागत में तेज गिरावट ने शहरी-ग्रामीण विभाजन को पाटते हुए इंटरनेट की गहरी पैठ बनाई है। हाल ही में 5जी सेवाओं की शुरुआत के साथ, देश डिजिटल बदलाव और कनेक्टिविटी की अगली लहर का साक्षी बनेगा। भारत नेट परियोजना के तहत, देश की 2,50,000 ग्राम पंचायतों में से 70% से अधिक को पहले ही ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान की जा चुकी है।

पिछले नौ वर्षों में सरकार द्वारा प्रौद्योगिकी को अपनाने से शासन के कामकाज में आई पारदर्शिता में उल्लेखनीय वृद्धि सुनिश्चित हुई है। आज सभी सरकारी कार्यक्रमों में एक डिजिटल डैशबोर्ड होता है जो लाभार्थियों के सभी विवरण प्रदान करता है। सार्वजनिक सेवाओं की डिजिटल डिलीवरी से भ्रष्टाचार समाप्त हो रहा है और जीवन सुगमता को बढ़ावा मिल रहा है। कोविन प्लेटफॉर्म के माध्यम से टीकों की डिजिटल डिलीवरी ने भारत को वैक्सीन वितरण में इक्विटी और पहुंच को सुनिश्चित करना आसान कर दिया है। अन्य देश अब कोविन प्लेटफॉर्म जैसे प्रौद्योगिकी समाधान हासिल करने के लिए भारत की ओर देख रहे हैं।

मोदी सरकार ने शासन में पारदर्शिता सुनिश्चित करने और खामियों को दूर करने के लिए प्रौद्योगिकी और डिजिटल उपकरणों को प्रभावी ढंग से तैनात किया है। उदाहरण के लिए, विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण और आधार प्रमाणीकरण की शुरुआत से लाखों फर्जी लाभार्थियों का सफाया हुआ है, सरकार के लिए भारी बचत हुई, और नागरिकों को समय पर लाभ मिला है। 2015 और 2022 के बीच, सरकार ने डीबीटी के माध्यम से लाभ वितरण के कारण 2.73 लाख करोड़ रुपये से अधिक की बचत की।

सार्वजनिक खरीद, जो पहले नौकरशाही भ्रष्टाचार के लिए एक आम तरीका था, अब डिजिटल हो गया है क्योंकि सरकारी ई-मार्केटप्लेस (जीईएम) पोर्टल का उपयोग सरकारी विभागों और सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा उनकी खरीद के लिए किया जा रहा है। यह पोर्टल देश में भ्रष्टाचार को सफलतापूर्वक समाप्त कर रहा है और सार्वजनिक खरीद को सुव्यवस्थित कर रहा है।

पिछले नौ वर्षों में, भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम लगातार मजबूत हुआ है। भारत के अब तक के पहले निजी लॉन्च वाहन विक्रम-एस के हालिया लॉन्च के साथ इसके विभिन्न मिशनों के बारे में व्यापक रूप से बात की जाती है। भारत अब इस क्षेत्र में नवाचार और उन्नति के एक नए दशक में प्रवेश करने के लिए तैयार है।

* * *

मुख्य बातें

2021 में भारत में
121 करोड़ मोबाइल सबस्क्राइबर
79 करोड़ लोग करते हैं स्मार्टफोन का प्रयोग

1.98 लाख
ग्राम पंचायतें
ऑप्टिक फाइबर
से जुड़ीं

प्रति जीबी डेटा
की कीमत 308 रु. से घटकर 9.94 रु. से भी कम

डीबीटी के माध्यम से
2.73 लाख करोड़ रुपये
से अधिक की बचत

GeM पोर्टल पर
3.90 लाख करोड़ रुपये
की रिकॉर्ड खरीद

देश भर के
669 जिलों में
नए स्टार्ट-अप

मार्च 2023 में
868 करोड़
UPI लेनदेन

2022 में दुनिया का
46%
डिजिटल लेनदेन
भारत में हुआ!

पिछले 5 वर्षों में भारत में
इंटरनेट उपयोगकर्ता
दोगुने से अधिक

डिजिटल इंडिया के तहत
5.47 लाख
कॉमन सर्विस सेंटर संचालित (सीएससी)

भारत नेट
के तहत
6.20 लाख किमी
ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाई गई

इसरो द्वारा एक ही बार में
104 सैटेलाइट
लॉन्च किए गए - एक अभूतपूर्व विश्व रिकॉर्ड!

उपलब्धियां

डिजिटल इंडिया का सपना हो रहा साकार

- डिजिटल डिवाइड को पाट रही है **स्मार्टफोन धारकों की संख्या में भारी वृद्धि**।
- **डेटा की कीमत में काफी गिरावट** से इंटरनेट के उपयोग में वृद्धि हुई है।
- **डिजिटल साक्षरता** से शासन के डिजिटलाइजेशन में मिल रही मदद

डायरेक्ट बिचौलिया ट्रांसफर से डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर तक

- डी बी टी जैम द्वारा क्रियाशील : **जनधन- आधार- मोबाइल फोन**
- **लीकेज को रोक कर** पब्लिक सर्विस डिलीवरी का कायाकल्प
- कल्याणकारी योजनाओं के लाभ के लिए **बिचौलियों के कमीशन से मुक्ति**
- **फ़र्ज़ी लाभार्थियों के अंत** से भारी बचत।

* * *

सरकार के बड़े काम

सरकारी खरीद में
भ्रष्टाचार ख़त्म
GeM
Government
e Marketplace
सरकारी ई-मार्केटप्लेस (जीईएम) पोर्टल को 2016 में सभी सरकारी खरीद के लिए लॉन्च किया गया था। इस पर कीमतें अन्य ऑनलाइन मंचों की तुलना में 9.5% कम हैं।
वित्त वर्ष 2021-22 में
आदेशों की संख्या 50 लाख से अधिक
वार्षिक खरीद 2 लाख करोड़ रुपये
एमएसएमई से खरीद 50% से अधिक

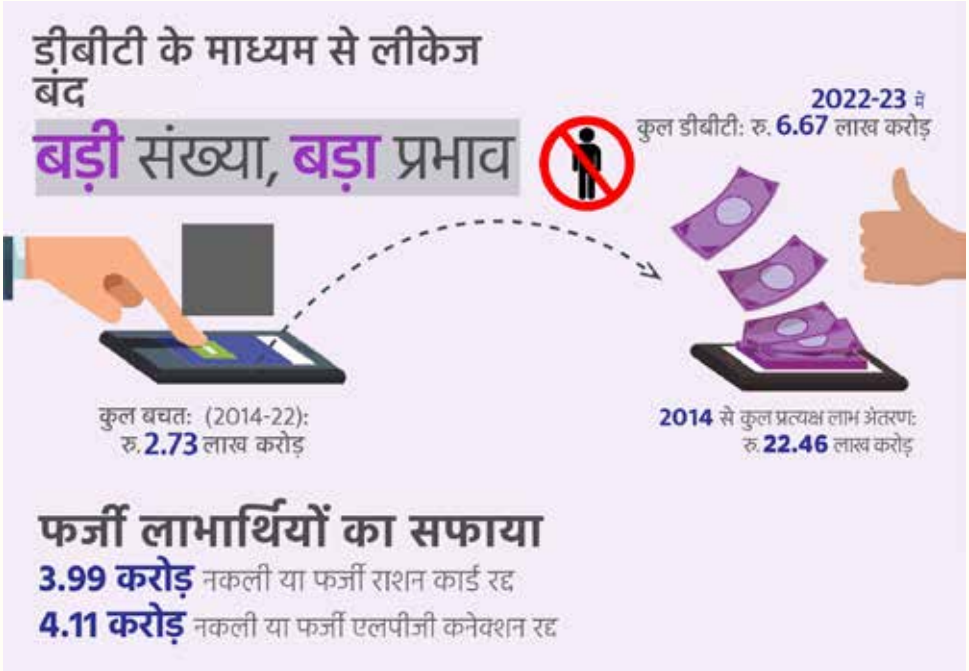
डीबीटी के माध्यम से लीकेज बंद
बड़ी संख्या, बड़ा प्रभाव
2022-23 में
कुल डीबीटी: रु. 6.67 लाख करोड़
कुल बचत: (2014-22):
रु. 2.73 लाख करोड़
2014 से कुल प्रत्यक्ष लाभ अंतरण:
रु. 22.46 लाख करोड़
फर्जी लाभार्थियों का सफाया
3.99 करोड़ नकली या फर्जी राशन कार्ड रद्द
4.11 करोड़ नकली या फर्जी एलपीजी कनेक्शन रद्द

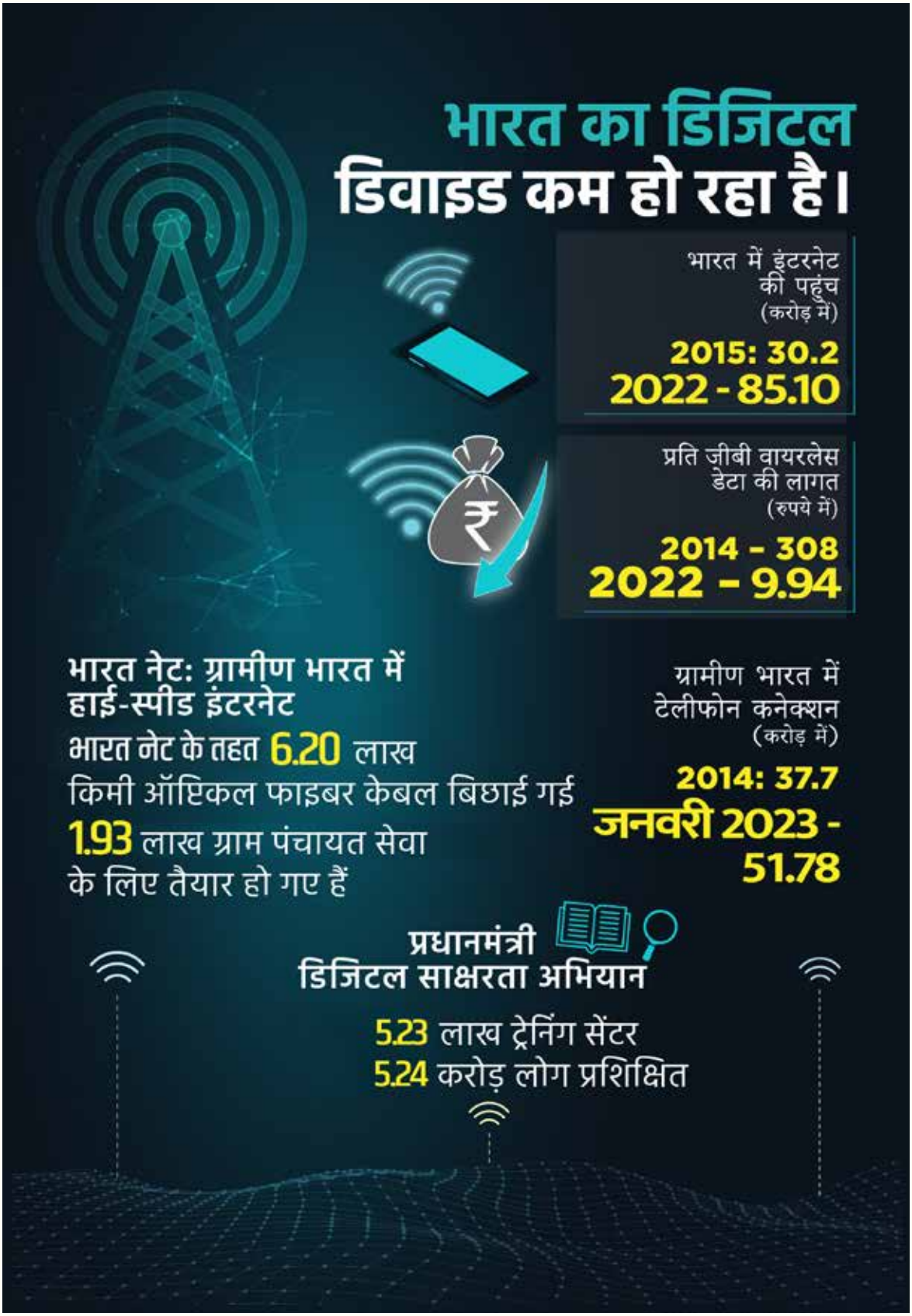
भारत का डिजिटल
डिवाइड कम हो रहा है।
भारत में इंटरनेट की पहुंच (करोड़ में)
2015: 30.2
2022 - 85.10
प्रति जीबी वायरलेस डेटा की लागत (रुपये में)
2014 - 308
2022 - 9.94
भारत नेट: ग्रामीण भारत में हाई-स्पीड इंटरनेट
भारत नेट के तहत 6.20 लाख किमी ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाई गई
1.93 लाख ग्राम पंचायत सेवा के लिए तैयार हो गए हैं
ग्रामीण भारत में टेलीफोन कनेक्शन (करोड़ में)
2014: 37.7
जनवरी 2023 - 51.78
प्रधानमंत्री डिजिटल साक्षरता अभियान
5.23 लाख ट्रेनिंग सेंटर
5.24 करोड़ लोग प्रशिक्षित

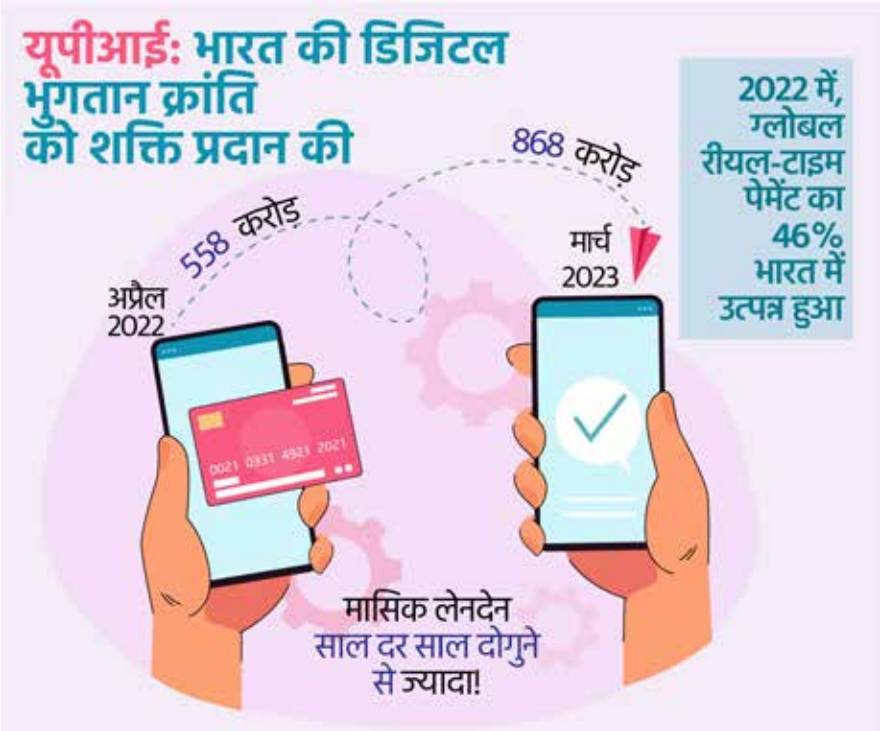

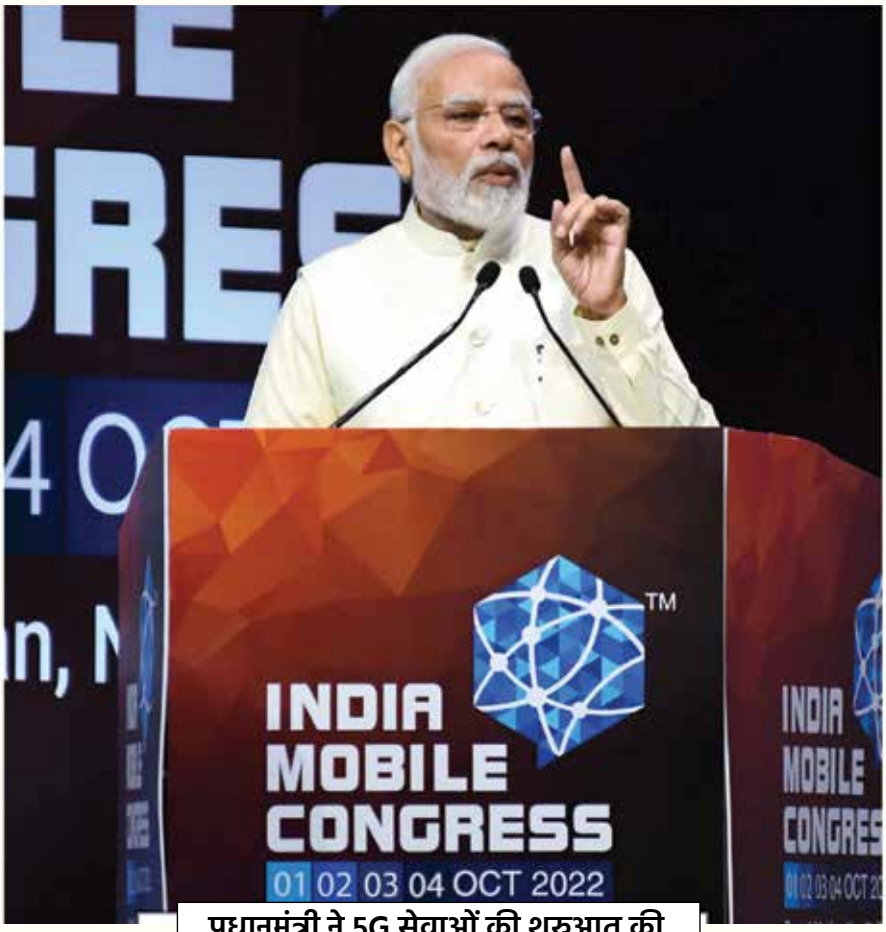

प्रधानमंत्री ने 5G सेवाओं की शुरुआत की

“

अलग-अलग समुदाय हो, या फिर अलग-अलग क्षेत्र, हम हर प्रकार के डिविजन को दूर कर रहे हैं। आज नॉर्थ ईस्ट में हम विवादों के बॉर्डर नहीं बल्कि विकास के कॉरिडोर बना रहे हैं

-नरेन्द्र मोदी

”

नॉर्थ ईस्ट बन रहा विकास का नया इंजन

12

सारांश

नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने हमेशा समावेशी विकास को प्राथमिकता दी है और सरकार की उत्तर-पूर्व नीति इस क्षेत्र को मुख्यधारा में लाने के लिए उसके प्रयासों को प्रतिबिंबित करती है। सरकार ने अपनी उत्तर-पूर्व नीति के माध्यम से आर्थिक विकास, आंतरिक सुरक्षा के साथ-साथ क्षेत्र की सांस्कृतिक विविधता के संरक्षण और संवर्धन पर अपना ध्यान केंद्रित किया है।

पिछले नौ वर्षों में दिल्ली अब खुद प्रधानमंत्री, उनके सहयोगी मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों के नियमित दौरे के माध्यम से उत्तर-पूर्व के दरवाजे पर पहुंच गई है। प्रधानमंत्री, देश और विश्व के बाकी हिस्सों के लिए उत्तर-पूर्व संस्कृति के एक दूत बन गए हैं।

पिछले नौ वर्षों में उत्तर-पूर्व में आर्थिक विकास के लिए विशेष निवेश किया गया है। पिछले 9 वर्षों के दौरान कई परियोजनाएं पूरी की गई हैं। साल 2017 से 2023 की अवधि में उत्तर पूर्व विशेष अवसंरचना विकास योजना (एनईएसआईडीएस) के तहत 145 परियोजनाओं के लिए लगभग 3400 करोड़ रुपये मंजूर किए गए। वहीं, साल 2014-22 की अवधि के दौरान उत्तर-पूर्व क्षेत्र में विकास कार्यों के लिए 15867.01 करोड़ रुपये की 1,350 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। केंद्रीय बजट 2022-23 के एक हिस्से के तहत उत्तर- पूर्व क्षेत्र के लिए प्रधानमंत्री की विकास पहल (पीएम-डिवाइन) की घोषणा की गई। इसका उद्देश्य विशेष प्रभाव वाली परियोजनाओं के वित्तपोषण के माध्यम से इस क्षेत्र का तीव्र और समग्र विकास करना है।

कई दशकों से कनेक्टिविटी की कमी और खराब बुनियादी ढांचा इस क्षेत्र के अलगाव का मुख्य कारण बना हुआ था। पिछले नौ वर्षों में लंबे समय से लंबित अनगिनत बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को पूरा किया गया इनमें प्रतिष्ठित परियोजनाएं जैसे कि बोगीबील पुल, जिसका उद्घाटन पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजेपयी की घोषणा के 16 साल बाद 2018 में प्रधानमंत्री ने किया था, रेलवे नेटवर्क का विस्तार, क्षेत्र में नए हवाईअड्डों का परिचालन के साथ ही उत्तर- पूर्व के पहले एम्स सहित नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना शामिल हैं। बेहतर कनेक्टिविटी के प्रभाव को इस क्षेत्र में पर्यटकों की बढ़ती संख्या के रूप में देखा जा सकता है।

उत्तर-पूर्व ने दशकों तक आंतरिक सुरक्षा से संबंधित गंभीर चुनौतियों का सामना किया था। मोदी सरकार के उठाए गए प्रभावी कदमों के कारण उत्तर-पूर्व में सुरक्षा की स्थिति में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। साल 2014 के बाद से चरमपंथी घटनाओं और इसके चलते सुरक्षाकर्मियों व नागरिकों की मौत में भारी कमी आई है। शांति समझौते पर हस्ताक्षर करने से क्षेत्र में शांति और हिंसा में कमी आई है। इन प्रयासों ने क्षेत्र में अफ्स्पा (सशस्त्र बल विशेषाधिकार कानून) के दायरे को कम करने का रास्ता दिखाया है। इस क्षेत्र में राज्यों के बीच लंबे समय से लंबित विवाद एक प्रमुख चिंता का विषय रहा है। लेकिन मोदी सरकार के सक्रिय प्रयासों से कई दशकों से चले आ रहे विवादों का समाधान अब स्थायी रूप से होने लगा है। हाल ही में असम और अरुणाचल प्रदेश ने राज्यों की साझा सीमा पर दशकों पुराने विवाद के समाधान को लेकर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

बांस को घास घोषित करने के ऐतिहासिक निर्णय और राष्ट्रीय बांस मिशन की शुरुआत ने इस क्षेत्र में बांस आधारित उत्पादों के उत्पादन को एक नई गति प्रदान की। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कई अवसरों पर जैविक खेती को बढ़ावा देने और विश्व का पहला पूर्ण जैविक राज्य बनने को लेकर सिक्किम की सफलता को रेखांकित किया है।

भारत की कहानी में हाशिए पर होने के बाद, उत्तर-पूर्व अब तेजी से देश के विकास इंजनों में से एक बन रहा है।

* * *

मुख्य बातें

AFSPA क्षेत्रों में
75% कमी

16 साल बाद
बोगीबील पुल
का इंतजार हुआ पूरा

2014 के मुकाबले 2022 में उग्रवाद की घटनाओं में
76% की गिरावट

आदिवासी असम शांति समझौता 2022 और बोडो, नागा, कार्बी, NLFT(SD) के साथ शांति समझौतों से पूर्वोत्तर क्षेत्र में शांति स्थापित

पिछले नौ सालों में
7 एयरपोर्ट
का निर्माण

सभी राज्यों की राजधानियों को
ब्रॉड-गेज
से जोड़ा जा रहा

1.55 लाख हेक्टेयर
भूमि का उपयोग ऑर्गेनिक खेती के लिए किया जा रहा है

वर्तमान में चल रही हैं
4,016 किमी
की सड़क परियोजनाएं

पूर्वोत्तर के लिए
22,000 करोड़ रु.
की लगभग 2,000 परियोजनाएं स्वीकृत

बांस और संबंधित उद्योग को बढ़ावा देने के लिए
राष्ट्रीय बांस मिशन
स्थापित

असम में किए जा रहे हैं
12 मेडिकल कॉलेज स्थापित

वन धन योजना के तहत
3.3 लाख
संग्रहकर्ता लाभान्वित

उपलब्धियां

नॉर्थ ईस्ट के द्वार तक दिल्ली

प्रधानमंत्री मोदी ने नॉर्थ ईस्ट का कम से कम 50 बार दौरा किया। यह किसी भी प्रधानमंत्री के लिए एक रिकॉर्ड है। इससे उनकी प्राथमिकता साफ झलकती है, साथ ही क्षेत्र के महत्व को लेकर सरकारी तंत्र में एक स्पष्ट संदेश भी जाता है।

प्रगति के लिए शांति

- **NSCN(IM) के साथ 2015 में बुनियादी समझौता**
- **NLFT(SD) त्रिपुरा शांति समझौता**, 2019
- **बोडो शांति समझौता**, 2020
- **ब्रू पुनर्वास समझौता,** 2020
- **Karbi-Anglong शांति समझौता**, 2021
- **असम-मेघालय सीमा समझौता**, 2022
- **आदिवासी असम शांति समझौता**, 2022
- शांति समझौतों ने इस क्षेत्र में हिंसा को बहुत हद तक कम कर दिया
- अलगाववाद में कमी के साथ नागरिकों की सुरक्षा बढ़ी
- दशकों लंबे सीमा विवाद का शांतिपूर्वक हो रहा समाधान

विकास की राह

- मोदी सरकार तेजी से **नॉर्थ ईस्ट के सभी हिस्सों को भारत के Railway Map पर** ला रही है।
- **असम, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश** इन तीनों राज्यों की, राजधानियों को ब्रॉडगेज से जोड़ा।
- अन्य राज्यों की राजधानियों को जोड़ने के काम में तेजी
- नॉर्थ ईस्ट और अन्य राज्यों के बीच **यात्रा समय कम हुआ**, जिससे आर्थिक अवसरों में बढ़ोतरी हुई।
- Connectivity से मजबूत हो रहा व्यापार, उत्तर पूर्व में बने उत्पादों को देशभर में पहुंचाया गया।
- **Economic Activity से रोजगार के लिए पलायन कम** होगा, विकास को और शक्ति मिलेगी।

* * *

क्या आप जानते हैं?

आजादी के 75 वर्षों बाद मालगाड़ी पहली बार मणिपुर में 2022 और मेघालय में 2023 में पहुंची।

सरकार के बड़े काम

पूर्वोत्तर में हिंसा में कमी

76%
2014 की तुलना में 2022 में उग्रवाद की घटनाओं में कमी

97%
2014 की तुलना में 2022 में नागरिक मौतों की संख्या में कमी

90%
2014 के मुकाबले 2022 में सुरक्षा बलों के हताहतों में कमी

पूर्वोत्तर में संचालित हवाई अड्डे

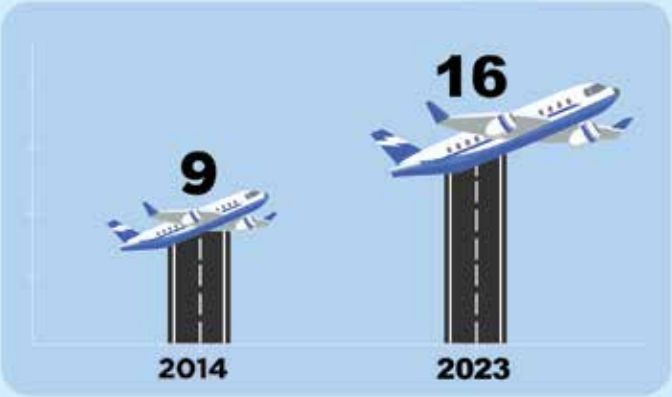

सपने देखना और उन्हें साकार करना

पूर्वोत्तर की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा दिया जा रहा है

रानी गैदिन्ल्यू
आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय मणिपुर में स्थापित किया गया है

सिबसागर
को असम में एक प्रतिष्ठित स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है जहां साइट पर संग्रहालय भी होगा।

क्या आप जानते हैं?

असम 14 अस्पतालों के साथ दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा कैंसर देखभाल नेटवर्क होगा।

7 अस्पतालों का उद्घाटन पहले ही हो चुका है तथा 7 और निर्माणाधीन हैं।

पहले चरण में डिब्रूगढ़, कोकराझार, बारपेटा, दरांग, तेजपुर, लखीमपुर और जोरहाट में सात कैंसर अस्पताल बनाए जा रहे हैं।

दूसरे चरण में धुबरी, नलबाड़ी, गोलपारा, नगांव, शिवसागर, तिनसुकिया और गोलाघाट में सात नए कैंसर अस्पताल बनाए जाएंगे।

पूर्वोत्तर में कृषि सशक्तिकरण

- पूर्वोत्तर खाद्य तेल उत्पादन में भारत के विस्तार को आकार देगा
- इस क्षेत्र को ऑर्गेनिक खेती के लिए वैश्विक केंद्र के रूप में परिवर्तित किया जा रहा है
- वन धन विकास योजना ने 3.3 लाख संग्रहकर्ताओं और 19,155 स्वयं सहायता समूहों की मदद की
- बांस के घास के रूप में पुनर्वर्गीकरण और राष्ट्रीय बांस मिशन ने बांस उद्योग को बढ़ावा दिया है

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निरंतर प्रयास रहा है कि वे गुमनाम नायकों को उचित तरीके से सम्मानित करें. इसी के अंतर्गत देश ने 2022 को लचित बोरफुकन की 400वीं जयंती के रूप में मनाया. लचित बोरफुकन (24 नवंबर, 1622 - 25 अप्रैल, 1672) असम के अहोम साम्राज्य की शाही सेना के प्रसिद्ध जनरल थे जिन्होंने मुगलों को हराया और औरंगजेब के अधीन मुगलों की लगातार बढ़ती महत्वाकांक्षाओं को सफलतापूर्वक रोक दिया. उन्होंने 1671 में लड़ी गई सरायघाट की लड़ाई में असमिया सैनिकों को प्रेरित किया और मुगलों को हराया।

डोनी पोलो हवाई अड्डा- अरुणाचल प्रदेश के इतिहास और संस्कृति का गवाह

“

यह भारत की समृद्ध विरासत है जो समयानुकूल परिवर्तन करने की आदत रखती है। नित्य नूतन स्वीकारती रही है। और इसलिए इस विरासत के प्रति हमें गर्व होना चाहिए।

-नरेन्द्र मोदी

”

सांस्कृतिक धरोहरों का संरक्षण

13

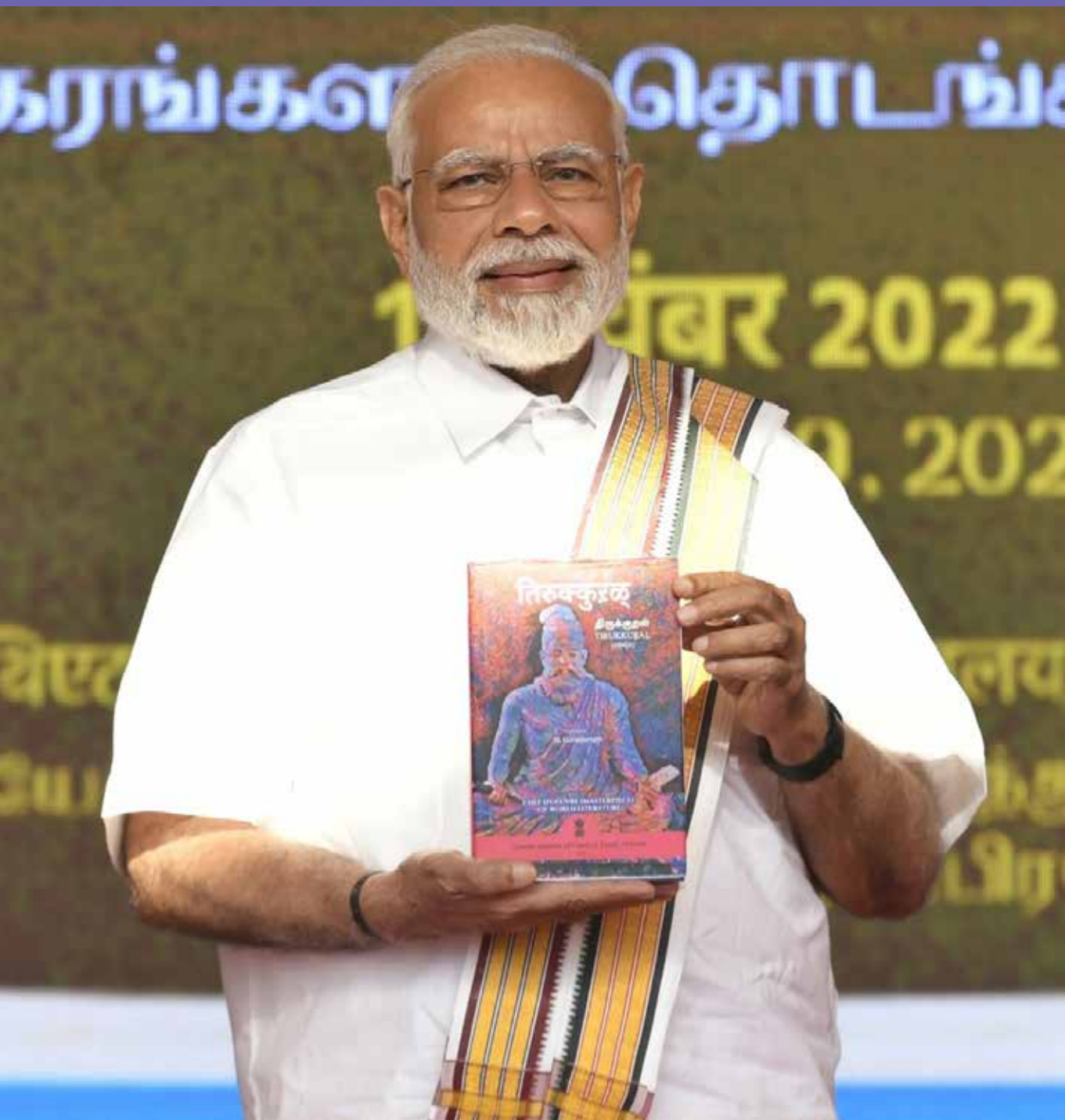

सारांश

भारत के समृद्ध सभ्यतागत इतिहास और इसकी संस्कृति के प्रति यथोचित सम्मान सुनिश्चित करना प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के लिए प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में से एक रहा है।

दशकों की उपेक्षा के पश्चात, मोदी सरकार के प्रयासों से सभ्यतागत महत्व वाले विभिन्न स्थलों का पुनर्विकास और पुनरुद्धार किया गया है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर और वाराणसी में कई अन्य परियोजनाओं के माध्यम से नगर की गलियों, घाटों और मंदिर परिसरों का कायाकल्प किया गया है। इसी तरह, उज्जैन में महाकाल लोक परियोजना और गुवाहाटी में माँ कामाख्या कॉरिडोर तीर्थयात्रियों को विश्व स्तरीय आधुनिक सुविधाएं प्रदान करने के साथ-साथ पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देकर मंदिर में आने वाले तीर्थयात्रियों के अनुभव को समृद्ध बनाने में सहयोग प्रदान करेगा। 900 किलोमीटर लंबी चारधाम सड़क परियोजना चार पवित्र धामों को बारहमासी निर्बाध सड़क संपर्क प्रदान करेगी। प्रधानमंत्री मोदी के हृदय में समाहित केदारनाथ में पुनर्विकास परियोजनाओं की प्रगति की भी उन्होंने व्यक्तिगत रूप से निगरानी की है। केदारनाथ परिसर में आदि शंकराचार्य की नव अनावरण प्रतिमा सभी क्षेत्रों में सभ्यता और सांस्कृतिक एकता का एक शाश्वत प्रतीक होगी। अगस्त 2020 में, आधुनिक भारत के इतिहास में एक अविस्मरणीय क्षण के रूप में, प्रधानमंत्री मोदी अयोध्या में राम मंदिर के लिए किए गए भूमिपूजन में सहभागी बने थे।

औपनिवेशिक मानसिकता की किसी भी पहचान को समाप्त करने के लिए प्रधानमंत्री ने 'कर्तव्य पथ' का उद्घाटन किया जो तत्कालीन राजपथ से सार्वजनिक स्वामित्व और सशक्तिकरण के परिवर्तन के एक उदाहरण का प्रतीक है।

देश की खोई हुई विरासत को वापस लाना मोदी सरकार की प्राथमिकता रही है। सदियों से, असंख्य अमूल्य कलाकृतियाँ को चोरी करके विदेशों में तस्करी के माध्यम से भेज दिया गया था, मोदी सरकार ने 'हमारे देवताओं को वापस लाने' के लिए एक सक्रिय दृष्टिकोण अपनाया है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी कई विदेशी यात्राओं के दौरान इस मामले पर वैश्विक नेताओं और बहुपक्षीय संस्थानों से चर्चा की। इसी के परिणामस्वरूप, पिछले 9 वर्षों में कई अमूल्य पुरावशेष भारत वापस लाए गए हैं।

मोदी सरकार ने राष्ट्र-निर्माताओं की एक विस्तृत श्रृंखला को विशेष मान्यता प्रदान की है। गुजरात में विश्व की सबसे ऊँची मूर्ति 'स्टैच्यू ऑफ यूनिटी' ने केवडिया को न केवल वैश्विक पर्यटन मानचित्र पर स्थान दिया है अपितु इसे भारत के लौह पुरुष को स्मरण करने का एक माध्यम भी बना दिया है। जलियाँवाला बाग परिसर के पुनरुद्धार और 'पंचतीर्थ' के रूप में डॉ. बी.आर. अम्बेडकर से संबंधित स्थलों के विकास जैसी परियोजनाएँ हमारे राष्ट्र-निर्माताओं और स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान और उनकी उपलब्धियों को सार्वजनिक स्मृति के तौर पर हमारे दिलों में अंकित करेंगी। मोदी सरकार ने सभी राष्ट्रीय नायकों के राजनीतिक दृष्टिकोण या विचारधारा से इतर उन्हें मान्यता दी है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की साहसपूर्ण विरासत का सम्मान करने और उनका महोत्सव मनाने के लिए इंडिया गेट पर उनकी एक प्रतिमा का अनावरण किया गया है। भारत के सभी प्रधानमंत्रियों के जीवन और योगदान के महत्व को दर्शाने वाला दिल्ली में नवउद्घाटित प्रधानमंत्री संग्रहालय भी सभी राष्ट्रीय नायकों को गैर-पक्षपातपूर्ण मान्यता देने का साक्षी है।

2019 में, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय युद्ध स्मारक का उद्घाटन किया, यह देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीरों का स्मरण करता है। हालांकि यह परियोजना 1961 से विचाराधीन थी, लेकिन इस महत्वपूर्ण परियोजना में ज्यादा प्रगति नहीं हुई थी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इस परियोजना को आवश्यकतानुरूप त्वरित गति दी और 2015 में स्वीकृति के बाद इस पर कार्य प्रारंभ हुआ।

उत्तर प्रदेश के वाराणसी में एक माह तक चलने वाले महत्वपूर्ण कार्यक्रम 'काशी तमिल संगम' का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य देश के दो सबसे महत्वपूर्ण और प्राचीन शिक्षा केंद्रों, तमिलनाडु और काशी के बीच सदियों पुराने संबंधों का उत्सव मनाना, उन्हें फिर से मज़बूत बनाना और पुनः स्थापित करना था। मोदी सरकार ने एक भारत श्रेष्ठ भारत के विचार का महोत्सव मनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है, इसका उद्देश्य देश की सांस्कृतिक विविधता का उत्सव मनाना है।

* * *

मुख्य बातें

विश्व स्तरीय
काशी विश्वनाथ कॉरिडोर और महाकाल प्रोजेक्ट

2020 में रखी गई
राम मंदिर
की नींव

स्वदेश दर्शन
के तहत किए जा रहे
75 पर्यटन सर्किट
विकसित

2014 से अब तक
231
चोरी हुई कलाकृतियां
भारत लाई गईं, 2014 तक सिर्फ 13 वापस आईं

207.3 करोड़ रुपये
की लागत से **केदारनाथ** पुनर्विकास परियोजना

चार धाम एनएच कनेक्टिविटी योजना के तहत
889 किलोमीटर
के राष्ट्रीय राजमार्ग विकसित किए जाएंगे

3.5 करोड़ रुपये
की लागत से **सोमनाथ मंदिर** पुनर्निर्माण परियोजना

राष्ट्रीय युद्ध स्मारक
और
राष्ट्रीय पुलिस स्मारक
अंततः वास्तविकता के धरातल पर

हृदय योजना
के तहत 12 हेरिटेज शहरों का विकास

10
नए जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय
स्थापित किए जा रहे हैं

PRASHAD योजना
के तहत सांस्कृतिक स्थलों के विकास के लिए
1,586 करोड़ रुपये
का निवेश

सिख तीर्थयात्रियों के लिए
करतारपुर साहिब कॉरिडोर
का उद्घाटन

उपलब्धियां

लोकमाता अहिल्याबाई होल्कर के पदचिह्नों का अनुसरण

माहनतम रानियों में से एक लोकमाता अहिल्याबाई होल्कर का मंदिरों के कायाकल्प में योगदान आज भी देशभर में याद किया जाता है। प्रधानमंत्री मोदी उनके ही पदचिह्नों पर चल रहे हैं।

लोकमाता अहिल्याबाई होल्कर	पीएम मोदी
वाराणसी में मौजूदा काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण	मंदिर के चारों ओर काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का विकास
वाराणसी के प्रसिद्ध घाटों का जीर्णोद्धार	घाटों की सफाई, नमामि गंगे से गंगा का प्रदूषण कम हुआ
अयोध्या में सरयू घाट का नवीनीकरण कराया	भव्य राम मंदिर का भूमिपूजन
जूना सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण कराया	सोमनाथ मंदिर के आसपास विकास कार्य, पार्वती मंदिर का निर्माण

पूर्व के राजनेताओं के विपरीत पीएम मोदी को देश की विरासत और संस्कृति से गहरा लगाव

- प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी संस्कृति को सम्मान देने में कभी कदम पीछे नहीं खींचा।
- सरकार भी भारतीय संस्कृति और मूल्यों को बढ़ावा देने में निरंतर जुटी है।
- प्रधानमंत्री मोदी **गणमान्य लोगों को जो उपहार देते हैं** और वैश्विक नेताओं को जिन स्थानों पर ले जाते हैं, वह एक प्रकार से हमारी सांस्कृतिक विरासत की अभिव्यक्ति है।
- चोरी हुए Antiquities और Artefacts की वापसी के लिए उन्होंने सक्रिय प्रयास किए हैं।

सोमनाथ से केदारनाथ तक, अयोध्या से अजमेर तक, वाराणसी से वेलंकन्नी तक

- मोदी सरकार महत्वपूर्ण स्थलों को संरक्षित करना अपना कर्तव्य मानती है, **चाहे वह किसी भी क्षेत्र या धर्म के हों**।
- सोमनाथ, अयोध्या, केदारनाथ जैसे स्थलों पर प्रधानमंत्री मोदी के कार्य जगजाहिर हैं। **PRASHAD Scheme के तहत हर धर्म के स्थानों का विकास किया जा रहा है**।
- चेरामन जुमा मस्जिद, हजरतबल, अजमेर, सेंट थॉमस श्राइन और वेलंकन्नी को अपग्रेड किया गया है।
- कश्मीर में सेंट ल्यूक चर्च का जीर्णोद्धार किया गया और तीन दशक के बाद फिर से खोल दिया गया।

भारत के महापुरुषों का सम्मान

- स्टैच्यू ऑफ यूनिटी अखंड भारत के निर्माण में **सरदार वल्लभभाई पटेल** के योगदान का सम्मान है।
- **नेताजी सुभाष चंद्र बोस** की विरासत को सम्मान देने के लिए पुरानी फाइलों को जारी करने के साथ ही इंडिया गेट पर उनकी प्रतिमा स्थापित की गई है।
- साबरमती आश्रम के पुनर्विकास के माध्यम से **महात्मा गांधी** की विरासत को आगे बढ़ाया गया।
- **पंचतीर्थ डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर** को देश की चर्चा के केंद्र में लाकर उनके योगदान को नई पहचान देता है।
- **Jallianwala Bagh Memorial** का जीर्णोद्धार स्वतंत्रता संग्राम की यादों को भावी पीढ़ियों के लिए प्रासंगिक बनाता है।
- **11 जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय** विकसित किए जा रहे हैं।
- राष्ट्र-निर्माताओं को पहचान और सम्मान देने में कोई राजनीतिक पूर्वाग्रह नहीं है। प्रधानमंत्री संग्रहालय **न तो एक व्यक्ति और न ही एक पार्टी** के लिए के लिए बनाया गया है, बल्कि यह सभी प्रधानमंत्रियों के लिए है।

* * *

सरकार के बड़े काम

क्या आप जानते हैं?

वर्ष 2014 से पहले, विदेशों से केवल 13 चोरी की पुरावशेष भारत लौटाए गए थे। तब से अब तक प्रधानमंत्री मोदी की निरंतर राजनीतिक और कूटनीतिक पहल के कारण, 231 **चोरी की गई प्राचीन वस्तुएं वापस पा ली गई हैं** और भारत लौटने के विभिन्न चरणों में हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान के भीलवाड़ा में भगवान श्री देवनारायण जी के 1111वें 'अवतरण महोत्सव' के मौके पर

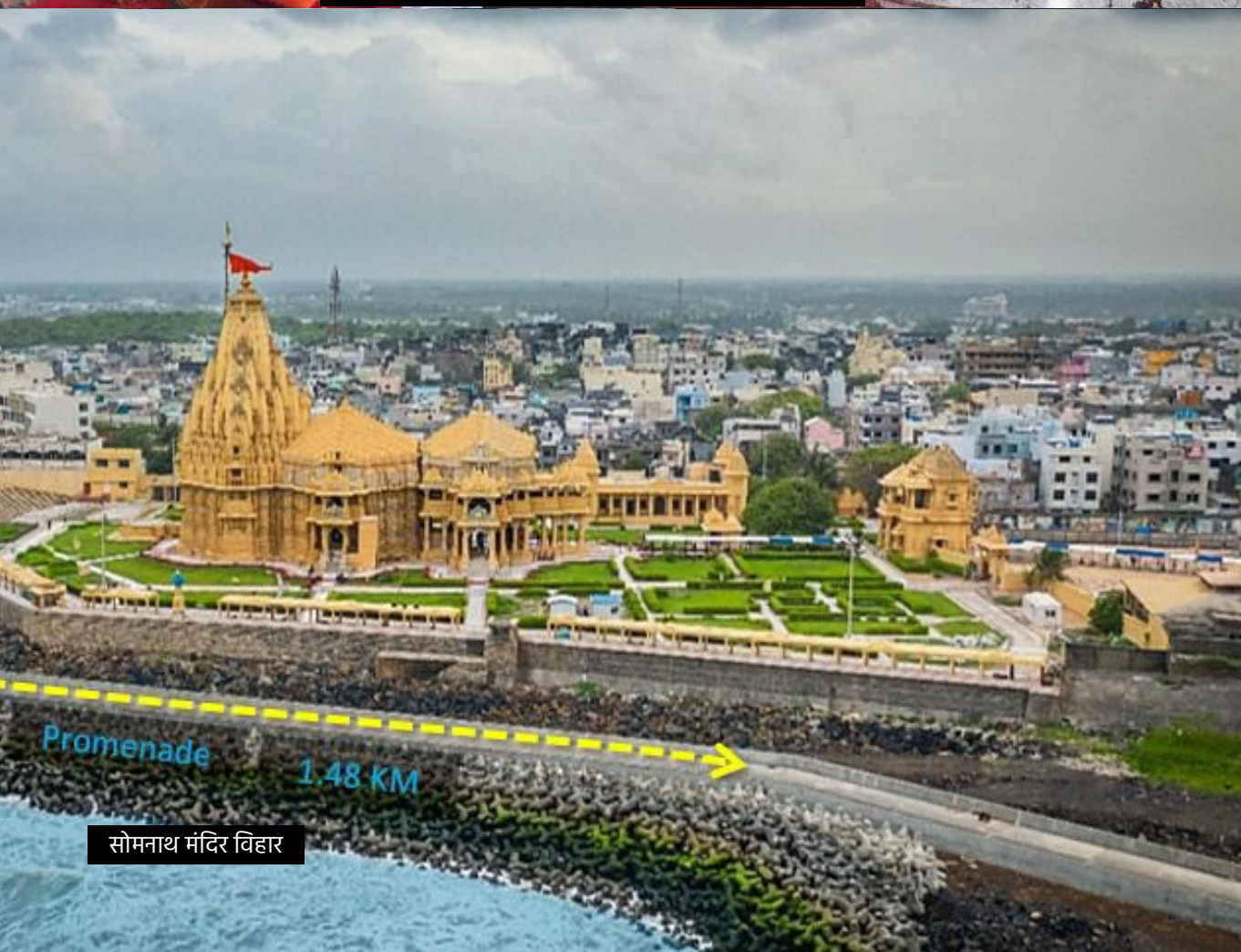

सोमनाथ मंदिर विहार

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की स्वतंत्रता के 75 वें वर्ष के अवसर पर लोगों को तिरंगा घर लाने और इसे फहराने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु "हर घर तिरंगा" अभियान शुरु किया।

जलियांवाला बाग स्मारक परिसर

सिख संस्कृति का उत्सव

पवित्र गुरुओं का सम्मान

श्री गुरु गोबिंद सिंह जी का 350वां प्रकाश पर्व

श्री गुरु नानक देव जी का 550वां प्रकाश पर्व

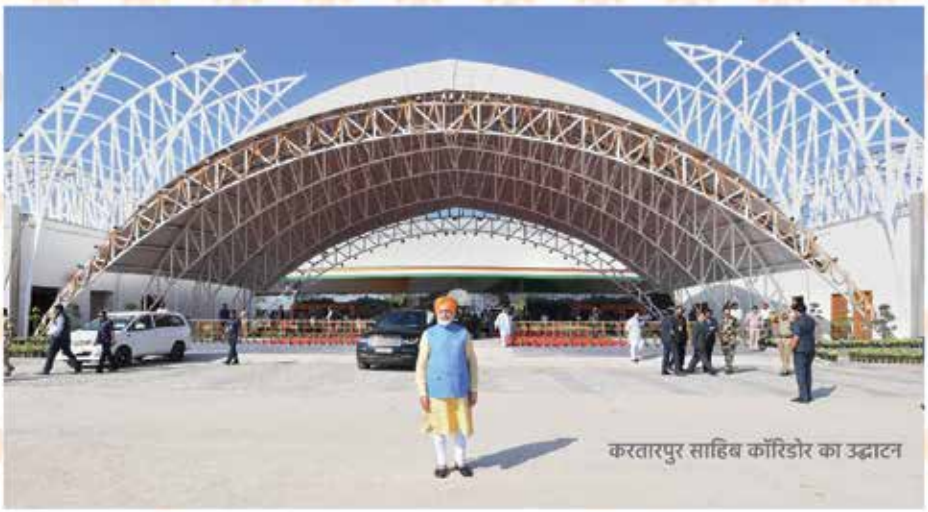

करतारपुर साहिब कॉरिडोर का उद्घाटन

पीएम संग्रहालय, नई दिल्ली

राष्ट्रीय पुलिस स्मारक:
लंबित: 1994 से
स्वीकृत: 2014में
उद्घाटन: 2018में

स्टैच्यू ऑफ यूनिटी

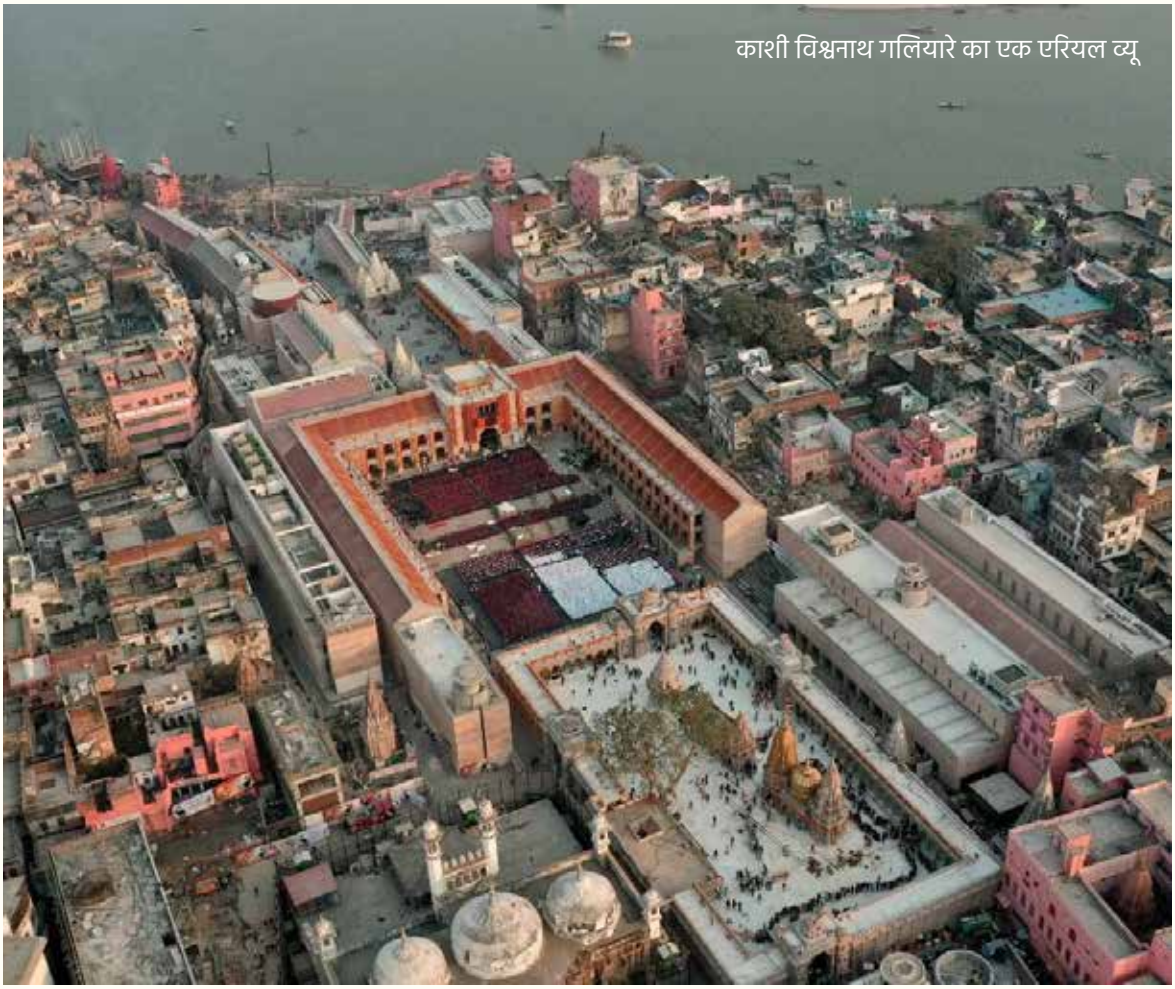

काशी विश्वनाथ गलियारे का एक एरियल व्यू

मन की बात, जन-जन के साथ

"

'मन की बात' सरकारी बात नहीं है- यह समाज की बात है। 'मन की बात' एक आकांक्षी भारत, महत्वाकांक्षी भारत की बात है।

- नरेन्द्र मोदी

"

मन की बात 100

MANN KI BAAT 100

अब तक **100** एपिसोड हुए पूरे

3 अक्टूबर 2014 को 'मन की बात' की हुई शुरुआत

प्रधानमंत्री हर महीने के अंतिम रविवार को लोगों से करते हैं संवाद

कार्यक्रम **22 भारतीय भाषाओं, 29 बोलियों** और अंग्रेजी के अलावा **11 विदेशी भाषाओं** में पहुंच रहा लोगों तक

एक सर्वे के अनुसार, **65%** लोगों ने बताया कि 'मन की बात' सुनने से उनका देश के प्रति सकारात्मक रुख हुआ है

100 करोड़ से ज्यादा देशवासियों ने 'मन की बात' कम से कम एक बार सुना है जिसमें **23 करोड़** नियमित श्रोता हैं

प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में 'कर्तव्य पथ' का उद्घाटन किया (सितंबर 08, 2022)

नई दिल्ली में अप्रैल, 2023 में आयोजित वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन

"भगवान बुद्ध का अष्टांगिक मार्ग कई समाजों और राष्ट्रों की भलाई का मार्ग दिखाता है। यह करुणा और दया के महत्व पर प्रकाश डालता है। भगवान बुद्ध की शिक्षाएँ विचार और कर्म दोनों में सादगी का प्रतीक हैं"

- नरेंद्र मोदी

“

भारत प्रकृति के साथ सद्भाव में रहने की हमारी संस्कृति के अनुरूप सतत विकास को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है।

-नरेन्द्र मोदी

”

पर्यावरण एवं सतत विकास

14

सारांश

अथर्ववेद में कहा गया है, पृथ्वी हमारी माता हैं और हम उनके बच्चे हैं। भारतीय दर्शन और जीवन शैली हमेशा से ही प्रकृति के साथ सह-अस्तित्व की संकल्पना के साथ जुड़ी रही है।

पिछले नौ वर्षों के दौरान, प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में, भारत जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध लड़ाई में एक वैश्विक नेता के रूप में उभरा है।

जब प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 2014 में कार्यभार ग्रहण किया तो भारत को वैश्विक रूप से जलवायु संबंधित बातचीतों में एक बाधक के रूप में देखा जा रहा था। बहरहाल, प्रधानमंत्री ने भविष्य के लिए मार्ग बताने के उपाय किए। सीओपी 21 के बाद से, जलवायु न्याय के प्रधानमंत्री के सिद्धांत ने यह सुनिश्चित किया है कि जलवायु परिवर्तन वार्ताओं में समानता की चिंताओं की अनदेखी न की जाए। भारत का ध्यान एक ' निष्पक्ष समझौता ' प्रदान करने पर केंद्रित रहा है।

ग्लासगो में COP-26 में, प्रधानमंत्री ने एलआईएफई (LiFE) का विचार प्रस्तुत किया। भारत मानता है कि जलवायु कार्रवाई व्यक्तिगत स्तर पर आरंभ होती है और प्रधानमंत्री श्री मोदी ने जलवायु परिवर्तन की जटिल समस्या का एक सरल समाधान उपलब्ध कराया है।

देश में वन आच्छादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। पिछले दशक के दौरान, भारत में बाघों की संख्या में दोगुने से भी अधिक की वृद्धि हुई है और आज भारत में विश्व की बाघों की संख्या के 75 प्रतिशत से अधिक का वास है।

इसके अतिरिक्त, अफ्रीकी चीतों को एक महादेश से दूसरे महादेश में स्थानांतरण से भी भारत की वन्य जीवन विविधता को बढ़ावा मिला है। 2023 में, 70 वर्षों के बाद चीता शावक पैदा हुआ, यह प्रजाति देश में पहले विलुप्त हो चुकी थी।

जहां कई देश अपने जलवायु लक्ष्य को पूरा करने में विफल रहे हैं, भारत ने अंतिम समय सीमा (डेडलाइन) से पहले ही अपने टारगेट पूरे कर लिए हैं। उदाहरण के लिए, गैर फॉसिल स्रोतों से संस्थापित विद्युत क्षमता का 40 प्रतिशत अर्जित करने के लक्ष्य, जिसे सीओपी 21 में निर्धारित किया गया था, को समय सीमा से नौ वर्ष पहले ही पूरा कर लिया गया। राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति के तहत एथनौल मिश्रित पेट्रोल के लिए निर्धारित लक्ष्य को अंतिम समय सीमा से पांच महीने पहले ही अर्जित कर लिया गया।

नमामि गंगे कार्यक्रम की बदौलत इस पवित्र नदी के प्रदूषण को सफलतापूर्वक रोक दिया गया और इससे अनगिनत स्थानों पर जल की गुणवत्ता में सुधार दर्ज किया गया। यह लक्ष्य प्रधानमंत्री श्री मोदी के दिल के बेहद निकट रहा है जैसाकि उन्हें प्राप्त उपहारों की नीलामी से मिली सभी आय को नमामि गंगे कार्यक्रम को दान करने के उनके निर्णय से जाहिर होता है।

पिछले नौ वर्षों के दौरान ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों की ओर तीव्र रूपांतरण देखा गया है। नवीकरणीय ऊर्जा सेक्टर के लिए बहुत से प्रोत्साहन और इनपुट की निम्न लागत के कारण नवीकरणीय ऊर्जा टैरिफ में भारी कमी दर्ज की गई है।

इसके अतिरिक्त, उजाला कार्यक्रम के कारण हजारों करोड़ रुपये की बचत हुई है और कार्बन डायऑक्साइड उत्सर्जन में भी कमी आई है।

इस बीच, स्वच्छ एवं नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने में अपने वैश्विक नेतृत्व की भागीदारी के रूप में, प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व के तहत भारत ने इस क्षेत्र में अगुवाई की और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के निर्माण में अग्रणी भूमिका निभाई।

हाल ही में लांच किए गए राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन का लक्ष्य भारत को ऊर्जा के मामले में आत्म निर्भर बनाना तथा हरित हाइड्रोजन के उत्पादन और निर्यात के लिए एक हब बनाना भी है।

स्वच्छता से लेकर सिंगल -यूज़-प्लास्टिक से बचने तक प्रधानमंत्री ने अक्सर नागरिकों को अपनी जीवनशैली में ऐसा बदलाव लाने के लिए प्रोत्साहित किया है जो पर्यावरण में योगदान दे सके। इन प्रयोजनों को जन आंदोलनों में रूपांतरित करने के द्वारा उन्होंने सार्वजनिक आदतों में अस्थायी बदलाव की जगह बड़े पैमाने पर परिवर्तन को सुनिश्चित किया है।

प्रधानमंत्री श्री मोदी के अनुसार, हमारा ग्रह एक है लेकिन हमारे प्रयास कई होने चाहिए- एक पृथ्वी, कई प्रयास। भारत बेहतर पर्यावरण और वैश्विक कल्याण के लिए होने वाले किसी भी प्रयास में सहायता करने के लिए हमेशा ही तत्पर रहेगा।

* * *

मुख्य बातें

2022 में बाघों की गिनती के अनुसार भारत में कुल
3167 बाघ
है जो की एक रिकॉर्ड है

प्रोजेक्ट चीता
विश्व की पहली अंतरमहाद्वीपीय जंगली मांसाहारी जीव स्थानांतरण परियोजना

नमामि गंगे मिशन
के तहत
35,415 करोड़ रुपये
से अधिक की परियोजनाएं लॉन्च

भारत ने निर्धारित समय से
9 साल पहले COP 21 लक्ष्य
हासिल कर लिया

नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता
दोगुना से अधिक

2014 से सौर ऊर्जा स्थापित क्षमता
2300% बढ़ी है

2014 के बाद से
सौर ऊर्जा दरों में लगभग
62%
की कमी

पीएम-कुसुम
के तहत लगेंगे
35 लाख
कृषि सोलर पंप

उजाला योजना
के तहत
36.86 करोड़
एलईडी बल्ब वितरित

12 भारतीय समुद्र तटों
को अब
ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट

जम्मू और कश्मीर का पल्ली भारत का पहला **'कार्बन न्यूट्रल पंचायत'** है

विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क
(2,200 मेगावाट से अधिक) भादला, राजस्थान में शुरू

उपलब्धियां

सतत विकास सुनिश्चित करना

- मोदी सरकार ने दिखाया कि **विकास के साथ-साथ पर्यावरण संरक्षण** भी संभव है।
- मोदी सरकार में पर्यावरण कानूनों में हुए सुधार ने **Compliance और Ease of Doing Business दोनों को प्रोत्साहित किया**

वैश्विक जलवायु परिवर्तन वार्ताओं को भारत दे रहा आकार

- भारत पहले की तुलना में आज Climate Change संबंधी वार्ताओं में **Leading Voice बना**
- भारत 'Climate Justice' को वैश्विक जलवायु परिवर्तन से संबंधित चर्चा के केंद्र में लाया।
- प्रधानमंत्री मोदी की **'Panchamrit' और 'LiFE यानि लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट'** की पहल भारत को जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई में एक रोल मॉडल के रूप में सामने लाया है।
- **GOBARdhan**, एसबीएम-जी के एक भाग के रूप में 30 अप्रैल, 2018 को लॉन्च की गई वेस्ट टू वेल्थ पहल है। जो भारत सरकार के अर्थव्यवस्था और मिशन लाइफ इनिशिएटिव में से एक है।
- GOBARdhan परियोजनाओं में बायोगैस और बायो स्लरी की बिक्री से उद्योग/उद्यमी, ग्रामीण परिवारों, किसान, स्वयं सहायता समूहो, गौशाला और ग्राम पंचायत को लाभ हुआ है।
- GOBARdhan जैव-कचरे का वैज्ञानिक प्रबंधन सुनिश्चित करता है, जिसके परिणामस्वरूप गाँवों में स्वच्छता और मवेशियों के गोबर और ठोस कृषि अपशिष्ट को खाद और बायोगैस में परिवर्तित करके धन और ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है।

भारत के Green Landscape को बदल रही है जनभागीदारी

- Big Targets और Speedy Achievement भारत की Renewable Energy Policy की पहचान
- 2014 के बाद सौर ऊर्जा क्षमता में 23 गुना वृद्धि हुई
- प्रधानमंत्री मोदी ने पर्यावरण संरक्षण में जनभागीदारी को प्रोत्साहित किया
- स्वच्छ भारत से लेकर सिंगल यूज़ प्लास्टिक पर रोक लगाने तक, लोगों को प्रेरित कर दैनिक आदतों में स्वैच्छिक बदलाव लाए।

* * *

क्या आप जानते हैं ?

ग्लासगो में COP26 शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी ने 'लाइफ' के रूप में दुनिया के सामने 'वन-वर्ड मूवमेंट' पर जोर दिया, जिसका मतलब 'लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट' है।

प्रधानमंत्री ने दुनिया से **पर्यावरण अनुरूप जीवन शैली' यानी LiFE** को जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए एक वैश्विक मिशन बनाने का आह्वान किया। इसका विजन न केवल ऊर्जा उत्पादन बल्कि ऊर्जा संरक्षण और बेहतर जीवन पर भी जोर देता है। इन समाधानों में ऊर्जा कुशल एसी, गीजर, हीटर और ओवन शामिल हैं।

सरकार के बड़े काम

स्वच्छ गंगा का सपना
हो रहा साकार

शब्द

कार्यवाही

नमामि गंगे कार्यक्रम 2014 में एक प्रमुख पहल के रुप में शुरु

- 35,415 करोड़ रुपए की लागत से 424 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। इनमें से 243 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं।
- सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की क्षमता में वृद्धि से नदी स्वच्छ हुई है
- डॉल्फिन जैसी जलीय प्रजातियां लौट रही हैं।
- नदी में फेंके जाने वाले लाखों लीटर प्रदूषक पदार्थ रुक गए हैं।

बड़े पैमाने पर अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने की भारत की कहानी

पीएम मोदी ने दुनिया से वादा किया था कि भारत 2030 तक 500 GW गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा क्षमता तक पहुंच जाएगा

महत्वाकांक्षी? लेकिन भारत पहले से ही रिकॉर्ड गति स्थापित कर रहा है

गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा कुल स्थापित क्षमता का 42.97% है

2014 के बाद से भारत की स्वच्छ ऊर्जा क्षमता में **2.25 गुना** की वृद्धि

मार्च 2014 तक

76.38 GW

भारत की स्थापित स्वच्छ ऊर्जा क्षमता

केवल 9 वर्षों में,

172 GW

के साथ भारत की क्षमता दोगुने से अधिक

यहां जानिए कि भारत कैसे अक्षय ऊर्जा में एक उभरता हुआ वैश्विक नेता है!

- भारत के पास अब विश्व की **चौथी सबसे बड़ी** स्वच्छ ऊर्जा क्षमता है
- भारत के पास **चौथी सबसे बड़ी** स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता है
-भारत के पास **पाँचवीं** सबसे बड़ी क्षमता है

अक्षय ऊर्जा देश आकर्षण सूचकांक निवेश और तैनाती के अवसरों के आकर्षण पर देशों को रैंक करता है।

इस भारी उछाल के पीछे कारण क्या है?

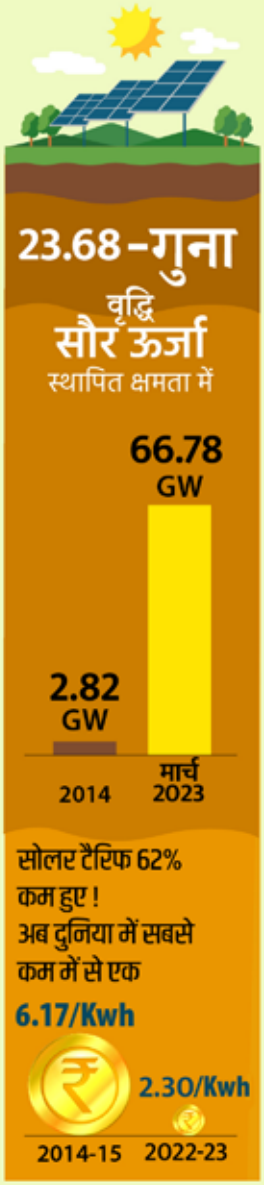

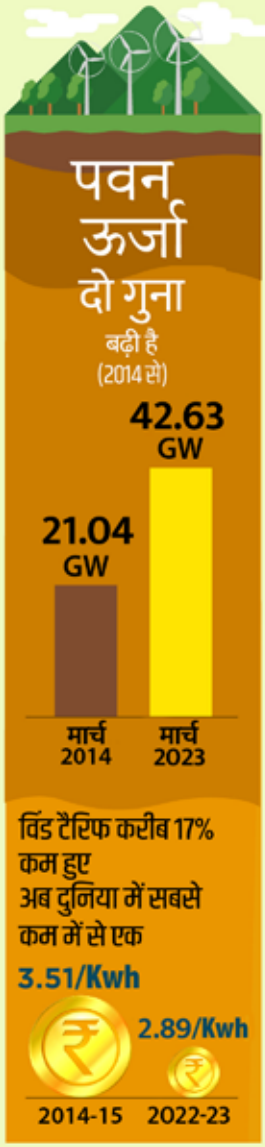

केवल क्षमता बढ़ाना पर्याप्त नहीं है। उसे अपनाना भी मायने रखता है।
इसलिए दरों में भी कमी की गई है।

भारत उदाहरण के साथ अग्रणी:

गैर-जीवाश्म ईंधन स्रोतों से 40% ऊर्जा का कॉप 21 लक्ष्य निर्धारित समय से लगभग **एक दशक पहले हासिल** किया गया

भारत सतत विकास लक्ष्यों को पूरा करने के मार्ग पर चल रहा है

वैश्विक परिवर्तन में अग्रणी:

प्रधानमंत्री मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन बनाने की वैश्विक पहल की अगुवाई की जिसमें 92 सदस्य देश हैं

नौ साल- सेवा, सुशासन

स्वच्छ भारत मिशन

2014

सभी ग्रामीण घरों में शौचालयों का विस्तार

48.27 करोड़
घरेलू शौचालयों का निर्माण

पीएमजेडीवाई: प्रधानमंत्री जन-धन योजना

2014

बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं तक सार्वभौमिक पहुंच का विस्तार

11.72 करोड़
बैंक खाते

9 साल

पीएमएसबीवाई: प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना

2015

भारत सरकार की दुर्घटना बीमा योजना

32.97 करोड़
नागरिक नामांकित

पीएमएमवाई: प्रधानमंत्री मुद्रा योजना

2015

छोटे व्यवसायियों को 10 लाख रु. तक का माइक्रो-क्रेडिट लोन

39.65 करोड़
लोन स्वीकृत

लॉन्च वर्ष
लाभ का विवरण
लाभार्थियों की संख्या

और गरीब कल्याण

सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण

पीएम-किसान: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि

2019

किसानों को 6,000 रुपये प्रति वर्ष का सुनिश्चित नकद ट्रांसफर।

11.39 करोड़
किसान

प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना

2018

मुफ्त स्वास्थ्य बीमा कवरेज तक पहुंच

23.19 करोड़ से ज्यादा
स्वास्थ्य बीमा कार्ड जारी

पीएमयूवाई: प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना

2016

खाना पकाने के स्वच्छ ईंधन के लिए मुफ्त एलपीजी कनेक्शन

9.6 करोड़
महिलाएं

पीएमजेजेबीवाई: प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना

2015

भारत सरकार की जीवन बीमा योजना

15.54 करोड़
नागरिक नामांकित

भारतीय नेतृत्व को मिली वैश्विक सराहना

David Malpass

Good to see Prime Minister @NarendraModi at today's @G7 meetings – we discussed energy transition efforts, @WorldBank Group programs in India & the importance of debt transparency & sustainability.

I was also glad to affirm WBG support for India's upcoming @G20org Presidency.

World Intellectual Property Or... @WIPO

Good news! WIPO's Global Design Database and Global Brand Database have added India's national collections of:
- 2 million trademark records
- 58,000+ design models

Free search at ow.ly/wPnI50C9Den and ow.ly/Xdxi50C9Del

Barry O'Farrell AO @AusHCIndia

Prime Minister @narendramodi said India is the mother of all democracies and #Vaishali in #Bihar is where it all began - the world's first republic in the 6th century BCE. Shared democratic values are a cornerstone of our #dosti. @PMOIndia @DrSJaishankar @MEAIndia @DFAT

Arindam Bagchi and 9 others

António Guterres @antonioguterres

I was inspired to learn that during #COVID19, **India**'s proportion of renewable energy rose from 17% to 24%.

This promising trend needs to continue. #ClimateAction

326

Tedros Adhanom Ghebreyesus @DrTedros · Apr 20

Honoured to build the foundations for the @WHO Global Traditional Medicine Centre together with Prime Minister @narendramodi. We welcome #India's support to this initiative, which will help millions of people access safe & effective treatments. #HealthForAll

Bill Gates @BillGates

As India celebrates its 75th Independence Day, I congratulate @narendramodi for prioritizing healthcare and digital transformation while spearheading India's development. India's progress in these sectors is inspiring and we are fortunate to partner in this journey #AmritMahotsav

IMF @IMFNews

IMF Projections: 2022

USA🇺🇸: 5.2%
Germany🇩🇪: 4.6%
France🇫🇷: 3.9%
Italy🇮🇹: 4.2%
Spain🇪🇸: 6.4%
Japan🇯🇵: 3.2%
UK🇬🇧: 5%
Canada🇨🇦: 4.9%
China🇨🇳: 5.6%
India🇮🇳: 8.5%
Russia🇷🇺: 2.9%
Brazil🇧🇷: 1.5%
Mexico🇲🇽: 4%
KSA🇸🇦: 4.8%
Nigeria🇳🇬: 2.7%
S. Africa🇿🇦: 2.2%

Ray Dalio @RayDalio

In my opinion, Indian's Prime Minister Modi is one of the best, if not the best, leaders in the world. I had an opportunity to explore with him how he thinks as well as what he thinks. If you're interested in listening to it, here it is:

YouTube

Ray Dalio & India's PM Narendra Modi Discuss Meditation, the World,...

Tedros Adhanom Ghebreyesus @DrTedros

Very impressed with India's initiative on Ayushman Bharat or universal Health Coverage! Thank you Prime Minister @narendramodi. Great commitment!
Thank you 🇮🇳 Minister of Health, @JPNadda, for meeting me today!

World Intellectual Property Or... @WIPO

India's 🇮🇳 investment in innovation 💡 is paying off: India's rise in the Global Innovation Index is the largest jump among the world's major economies since 2015. wipo.int/gii #GII2019

3,580 views

19:02 · 24 Jul 19 · Twitter Web App

UN Development @UNDP

Ahead of the Lunar #YearOfTheTiger, we presented today with partners Bardia National Park in Nepal and the Sathyamangalam Tiger Reserve in India with the TX2 Award for doubling their population of wild tigers 🐅 since 2010. Learn more here: bit.ly/3nUDYRe

World Bank @WorldBank

India 🇮🇳 has achieved the fastest-growing rate of renewable electricity growth in any major economy, thanks to a proactive approach that allowed utilities to find a cost-efficient way to incorporate #renewable #energy. Read the blog 👉 wrld.bg/Rrti50Kz2h2

0:30 · 04 Sept 22 · Hootsuite Inc.

Alex Ellis @AlexellisUK

Honoured to be present at the commissioning of #INSVikrant by @narendramodi - a great day for 🇮🇳 @indiannavy & for open & free seas

3:13 pm · 2 Sep 2022 · Twitter for iPhone

सत्यमेव जयते

भारत सरकार